सुबह सवेरे

A Daily News Magazine
इंदौर
शनिवार, 06 दिसंबर, 2025

इंदौर एवं भोपाल से एक साथ प्रकाशित

वर्ष 11 अंक 71, नगर संस्करण, पृष्ठ 8, मूल्य रू. 2

प्रसंगवश

आखिर अरुणाचल प्रदेश के लोग चीन के निशाने पर क्यों हैं ?

संजीव चोपड़ा

पासपोर्ट पर वीज़ा स्टेपल करना और अंतरराष्ट्रीय ट्रांजिट ज़ोन में भारतीय यात्रियों को रोकना, अरुणाचल प्रदेश के लोगों के साथ होने वाली परेशानियों के कुछ उदाहरण हैं। चीन अरुणाचल प्रदेश को 'दक्षिण तिब्बत' का हिस्सा मानता है। इन कार्रवाइयों को किसी ज़्यादा उत्साहित इमीग्रेशन अधिकारी की गलती नहीं कहा जा सकता। यह एक सोची-समझी रणनीति का हिस्सा है, जिसके ज़रिए चीन अरुणाचल प्रदेश की भारत के एक पूर्ण राज्य के रूप में स्थिति पर सवाल उठाता है। यही ज़्यादा सच लगता है क्योंकि चीन के पूरे सिस्टम में कुछ भी बिना तालमेल के नहीं होता।

पिछले हफ्ते ही, प्रेमा वांगजॉम थोंगडॉक, जो यूके में रहने वाली एक भारतीय फाइनेंशियल कंसल्टेंट हैं, को शंघाई एयरपोर्ट पर गैरकानूनी तरीके से रोका गया। भारत के कड़े विरोध के बाद, चीन की विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग ने वही आधिकारिक बयान दोहराया कि 'बॉर्डर इंस्पेक्शन अधिकारियों ने कानून और नियमों के अनुसार पूरी प्रक्रिया का पालन किया और संबंधित व्यक्ति के कानूनी अधिकारों की पूरी सुरक्षा की।' उन्होंने अरुणाचल प्रदेश को 'जांगनान' कहा और दावा किया कि 'चीन ने कभी भी भारत द्वारा बनाए गए तथाकथित अरुणाचल प्रदेश को स्वीकार नहीं किया।'

अब तथ्य साफ कर लेते हैं। आज का अरुणाचल प्रदेश पहले नॉर्थ-ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी (NEFA) का हिस्सा था और 1914 में भारत, तिब्बत और चीन के प्रतिनिधियों द्वारा सिमला और नई दिल्ली में हुई बैठक के बाद मैकमोहन समझौते के तहत बनाई गई सीमा रेखा में इसे स्पष्ट रूप से दर्शाया गया था। इस सम्मेलन को शिमला कन्वेंशन कहा जाता है – जिसकी शुरुआती बैठकें ब्रिटिश भारत की गर्मियों की राजधानी में हुई थीं, लेकिन बातचीत सर्दियों तक चली और नई दिल्ली में खत्म हुई। यह सच है कि प्रथम विश्व युद्ध और कठिन भौगोलिक स्थिति के कारण भारतीय राजस्व और नागरिक अधिकारियों की इन दूरदराज़ सीमाई इलाकों में यात्राएं बहुत कम हुईं। इसी वजह से वहां के मठों में दलाई लामा के प्रति निष्ठा रखने वाले भिक्षु प्रशासन संभालते रहे, खासकर तवांग मठ में, जो NEFA का मुख्य द्वार था।

लेकिन स्वतंत्रता के बाद – और खासकर पाकिस्तान द्वारा भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ की कोशिशों के बाद – भारत के उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल ने संविधान की पहली अनुसूची में बताए क्षेत्रों पर भारत के अधिकारों को मज़बूती से स्थापित करने की पहल की। अपनी मृत्यु से एक हफ्ते पहले, 15 दिसंबर 1950 को, उन्होंने प्रधानमंत्री नेहरू का ध्यान चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (PLA) के विस्तारवाद के खतरे की ओर दिलाया। उन्होंने लिखा, 'इतिहास में हमने शायद ही कभी अपनी उत्तर-पूर्वी सीमा की चिंता की हो। हिमालय को हमेशा उत्तर से आने वाले खतरे के खिलाफ एक अभेद्य दीवार (न टूटने वाली दीवार) माना जाता था। हमारे पास एक मैत्रीपूर्ण तिब्बत था, जिससे कोई परेशानी नहीं थी (लेकिन) हाल का इतिहास बताता है कि कम्युनिज़्म साम्राज्यवाद से बचाव नहीं है और चीनी कम्युनिस्ट भी अन्य साम्राज्यवादियों की तरह ही हैं।'

इस पत्र में उन्होंने नेहरू से तुरंत इन कदमों पर कार्रवाई करने को कहा-

(a) उत्तरी और उत्तर-पूर्वी सीमाओं को मज़बूत करने के लिए राजनीतिक और प्रशासनिक कदम, जिसमें पूरी सीमा – नेपाल, भूटान, सिक्किम, दार्जिलिंग और असम के जनजातीय क्षेत्र – शामिल हों।

(b) सीमा क्षेत्रों और उनसे लगे राज्यों जैसे यूपी, बिहार, बंगाल और असम में आंतरिक सुरक्षा के उपाय।

(c) इन क्षेत्रों और सीमा चौकियों के साथ सड़क, रेल, हवाई और वायरलेस संचार को बेहतर बनाना।

(d) सीमा चौकियों की पुलिसिंग और खुफिया व्यवस्था।

(e) ल्हासा में हमारे मिशन का भविष्य और ग्यांत्से और यातुंग में ट्रेड पोस्ट, और तिब्बत में ट्रेड रूट की सुरक्षा के लिए काम कर रही सेना; और, आखिर में, मैकमोहन लाइन से जुड़ी पॉलिसी।

इस पत्र की एक प्रति जयरामदास दौलतराम, तत्कालीन असम के राज्यपाल, को भेजी गई, जिन्हें NEFA की विशेष ज़िम्मेदारी दी गई थी। उन्होंने तुरंत कार्रवाई करने का फैसला किया। उन्होंने असम राइफल्स के मेजर रालेंगनाओ 'बॉब' खाथिंग को बुलाया – जिन्होंने 1950 के असम भूकंप के बाद पुनर्वास कार्य में अपनी पहचान बनाई थी। दौलतराम ने उन्हें मैकमोहन लाइन के अनुसार तवांग पर भौतिक कब्ज़ा करके NEFA की सीमा सुरक्षित करने का आदेश दिया। खाथिंग ने तवांग मठ पर भारत का अधिकार स्थापित करने के लिए कुमाऊं रेजिमेंट के 200 जवानों और 800 कुलियों व खच्चरों के साथ यात्रा शुरू की। 9 फरवरी 1951 को खाथिंग तवांग पहुंचे और घोषणा की कि अब से लामाओं को भारत के प्रति निष्ठा दिखानी होगी।

ज़्यादा विरोध नहीं हुआ क्योंकि स्थानीय लोग लंबे समय से भारी करों के कारण परेशान थे, खासकर जब युद्ध के लंबे दौर ने उनकी रोज़ी-रोटी प्रभावित की थी। अगर पटेल कुछ और समय जीवित रहते, तो शायद भारत ल्हासा में वाणिज्य दूतावास या ग्यांत्से और यातुंग में सैन्य ठिकाने नहीं छोड़ता, क्योंकि उनकी मृत्यु के बाद हमारी विदेश नीति 'राष्ट्र-प्रथम' के बजाय वैचारिक दिशा में चली गई। हमने न सिर्फ तिब्बत पर चीन के प्रभुत्व की राय मानी, बल्कि चीन की संयुक्त राष्ट्र में सदस्यता का भी समर्थन किया – एक कदम जो बाद में हमारे लिए बोझ साबित हुआ। मानचित्र के स्तर पर देखें तो हिंदी में 'चीन' शब्द पहली बार 1952 में प्रकाशित भारत के पहले हिंदी नक्शे पर दिखाई दिया।

दस साल बाद, 23 अक्टूबर 1962 को चीनी सैनिक नेफा में घुसे, जो चीन और भूटान से सटा हुआ है, और भारी गोलाबारी शुरू कर दी। उन्होंने तवांग, जो एक मठ वाला कस्बा है, पर कब्ज़ा कर लिया। नवंबर के मध्य तक वे बोमडिला पहुंच गए, जो एक और मठ वाला इलाका है और असम से सिर्फ 250 किलोमीटर दूर है, जहां भारत के चाय बागान, तेल के कुएं और जूट उद्योग हैं। लेकिन हमले की शुरुआत के सिर्फ एक महीने बाद, 21 नवंबर को चीन ने एकतरफा युद्धविराम की घोषणा कर दी और दोनों देशों के बीच मौजूद धुंधली वास्तविक सीमा रेखा – यानी मैकमहोन लाइन – से 20 किलोमीटर पीछे हट गया, जिसे वह हमेशा चुनौती देता रहा था। यही अब वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) कहलाती है।

इसके बाद भी, प्रेमा द्वारा उठाया गया मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है। 'द्विपक्षीय या भू-राजनीतिक मसले को एक निजी भारतीय नागरिक पर डाल दिया गया।' ऐसा अंतरराष्ट्रीय ट्रांज़िट में कभी नहीं होना चाहिए क्योंकि यह शिकागो और मॉन्ट्रियल कन्वेंशनों का उल्लंघन है जो नागरिक उड्डयन से जुड़े हैं।

(दि प्रिंट हिंदी में प्रकाशित लेख के संपादित अंश)

भारत-रूस के संबंध हर कसौटी पर उतरे हैं खरे

● मोदी बोले-दोनों देशों की दोस्ती ध्रुव तारे की तरह अटल ● भारत को बिना रुकावट फ्यूल सप्लाई करता रहेगा रूस

नई दिल्ली (एजेंसी)। दो दिवसीय भारत दौरे पर आए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और पीएम मोदी ने शुक्रवार को संयुक्त बयान दिए। इसमें पुतिन ने दो टूक कहा कि भारत को होने वाली तेल की सप्लाई जारी रहेगी। रूसी राष्ट्रपति के इस बयान से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को मिर्ची लगना तय माना जा रहा है, क्योंकि वह भारत से रूसी तेल खरीदना बंद करने को कहते रहे हैं। यहां तक कि उन्होंने रूसी तेल खरीदने के लिए भारत पर 25 फीसदी अतिरिक्त टैरिफ (कुल 50 फीसदी टैरिफ) भी लगाया हुआ है। पुतिन ने नई दिल्ली के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कहा, रूस तेल, गैस, कोयला और भारत की एनर्जी के विकास के लिए जरूरी हर चीज का एक भरोसेमंद सप्लायर है। हम तेजी से बढ़ती भारतीय इकॉनमी के लिए तेल की बिना रुकावट शिपमेंट जारी रखने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि हम एनर्जी सेक्टर में सहयोग बढ़ाने पर विचार कर रहे है। व्लादिमीर पुतिन ने कहा, रूस और भारत ब्रिक्स, एससीओ और दुनिया के दूसरे बड़े देशों में एक जैसी सोच वाले देशों के साथ इंडिपेंडेंट और आत्मनिर्भर फॉरेन पॉलिसी अपना रहे हैं। हम यूएन में दिए गए कानून के मुख्य सिद्धांत की रक्षा करेंगे।

● टैरिफ वार के बीच राष्ट्रपति पुतिन का ट्रंप को बड़ा मैसेज

दोनों देशों ने 2030 तक आर्थिक सहयोग की रणनीति बनाई

पीएम मोदी ने भारत और रूस के बीच दोस्ती को ध्रुव तारे की तरह स्थिर बताया है। उन्होंने कहा, पिछले 8 दशकों में दुनिया ने कई उतार-चढ़ाव देखे हैं। मानवता को कई तरह की चुनौतियों और संकटों से गुजरना पड़ा है। लेकिन इन सबके बीच भारत-रूस की दोस्ती ध्रुव तारे की तरह हमेशा अटल और स्थिर बनी रही है। मोदी ने कहा कि दोनों देशों के संबंध हर कसौटी पर खरे उतरे हैं। पीएम ने कहा कि दोनों देशों ने 2030 तक आर्थिक सहयोग की रणनीति बनाई है। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि एनर्जी सिक्योरिटी पार्टनरशिप भारत-रूस साझेदारी का एक मजबूत और अहम स्तंभ रही है। सिविल न्यूक्लियर एनर्जी में हमारी दशकों पुरानी साझेदारी ने स्वच्छ ऊर्जा के हमारे साझा लक्ष्यों को हासिल करने में बड़ी भूमिका निभाई है। हम इस 'विन-विन' सहयोग को आगे भी जारी रखेंगे। क्रिटिकल मिनरल्स में हमारा सहयोग दुनिया भर में सुरक्षित और विविध सप्लाई चेन बनाने के लिए बेहद जरूरी है। यह स्वच्छ ऊर्जा, हाई-टेक मैन्युफैक्चरिंग और नई पीढ़ी के उद्योगों में हमारी साझेदारी को मजबूत समर्थन देगा। उन्होंने आगे कहा कि जहाज निर्माण (शिपबिल्डिंग) में हमारा गहरा सहयोग 'मेक इन इंडिया' को और मजबूत करने की क्षमता रखता है। इससे नौकरी, स्किल्स और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बढ़ावा मिलेगा। पीएम मोदी ने कहा कि साल 2010 में भारत-रूस की साझेदारी को स्पेशल प्रिविलेज्ड स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा दिया गया था। पिछले ढाई दशकों से राष्ट्रपति पुतिन ने अपनी नेतृत्व क्षमता और दूरदर्शिता से इस रिश्ते को मजबूत किया है।

आरबीआई ने घटाई ब्याज दर

जल्द सस्ते होंगे लोन

नई दिल्ली (एजेंसी)। आने वाले दिनों में लोन सस्ते हो जाएंगे। मौजूदा ईएमआई भी घट जाएगी। आरबीआई ने रेपो रेट को 0.25 फीसदी घटाकर 5.25 फीसदी कर दिया है। इस कटौती का फैसला मॉनीटरी पॉलिसी कमेटी की 3 से 5 दिसंबर तक चली मीटिंग में लिया गया। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने 5 दिसंबर को इसकी जानकारी दी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई जिस रेट पर बैंकों को लोन देता है उसे रेपो रेट कहते हैं। जब आरबीआई रेपो रेट घटाता है, तो बैंकों को सस्ता कर्ज मिलता है और वो इस फायदे को ग्राहकों तक पहुंचाते हैं। यानी, आने वाले दिनों में होम और ऑटो जैसे लोन 0.25 फीसदी तक सस्ते हो जाएंगे।

ताजा कटौती के बाद 20 साल के 20 लाख के लोन पर ईएमआई 310 रुपए तक घट जाएगी। इसी तरह 30 लाख के लोन पर ईएमआई 465 रुपए तक घट जाएगी। नए और मौजूदा ग्राहकों दोनों को इसका फायदा मिलेगा। रेपो रेट घटने के बाद बैंक भी हाउसिंग और ऑटो जैसे लोन्स पर ब्याज दरें कम करते हैं। ब्याज दरें कम होने पर हाउसिंग डिमांड बढ़ेगी। ज्यादा लोग रियल एस्टेट में निवेश कर सकेंगे। इससे रियल एस्टेट सेक्टर को बूस्ट मिलेगा। आरबीआई ने फरवरी में हुई मीटिंग में ब्याज दरों को 6.5 फीसदी से घटाकर 6.25 फीसदी कर दिया था। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की ओर से ये कटौती करीब 5 साल बाद की गई थी। दूसरी बार अप्रैल में हुई मीटिंग में भी ब्याज दर 0.25 फीसदी घटाई गई।

● 20 साल में 20 लाख के लोन पर करीब 74 हजार का फायदा

हम नहीं चाहते एआई न्यायिक प्रक्रिया पर हावी हो: सीजेआई

नई दिल्ली (एजेंसी)। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को ज्यूडिशियल सिस्टम में आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस और मशीन लर्निंग के बिना रेगुलेशन वाले इस्तेमाल पर रोक लगाने की मांग वाली पीआईएल पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि उसे ज्यूडिशियरी में आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस और मशीन लर्निंग टूल्स के बुरे असर के बारे में पता है, लेकिन इन मुद्दों को ज्यूडिशियल निर्देशों के बजाय एडमिनिस्ट्रेटिव साइड से ठीक से सुलझाया जा सकता है। सीजेआई सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच ने एडवोकेट अनुपम लाल दास की दलीलें सुनीं। जिन्होंने एआई से बने कंटेंट और ज्यूडिशियल प्रोसेस में इसके गलत इस्तेमाल से होने वाले खतरों के खिलाफ सुरक्षा की मांग की थी। एआई टूल्स ऐसे ज्यूडिशियल उदाहरण और फैसले बनाते हैं जो मौजूद नहीं हैं। वे आखिरकार ज्यूडिशियल फैसलों का हिस्सा बन जाते हैं। निचली अदालतों ने सुप्रीम कोर्ट के ऐसे उदाहरणों का हवाला देना शुरू भी कर दिया है।

यशोदा मैया जैसी ही शिक्षा और संस्कार आंगनबाड़ी से दिए जाएं : मुख्यमंत्री

ऑनलाइन भर्ती की यह पहल करने वाला पहला राज्य बना मध्यप्रदेश

भोपाल (नप्र)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने नवनियुक्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाओं से कहा कि आपकी जिम्मेदारी यशोदा मैया की तरह है, जिस प्रकार उन्होंने गोपाल कृष्ण का पालन-पोषण कर उन्हें संस्कार प्रदान किए, उसी तरह आप भी आंगनबाड़ी में आने वाले हर बच्चे की देखभाल श्रीकृष्ण की तरह करें। नवनियुक्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को नियुक्ति पत्र के रूप में बच्चों की मुस्कुराहट, पोषण और माताओं के स्वास्थ्य व सुरक्षा की जिम्मेदारी निभाने का वचन पत्र सौंपा जा रहा है। हमें विश्वास है कि हमारी बहनें अपना दायित्व पूर्ण समर्पण और प्रतिबद्धता से निभाएंगी और प्रदेश को कुपोषण के खिलाफ लड़ाई में विजय दिलवाएंगी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने शुक्रवार को पारदर्शी ऑनलाइन प्रक्रिया से नवनियुक्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को विधानसभा के समिति कक्ष में हुए कार्यक्रम में नियुक्ति-पत्र प्रदान कर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। कार्यक्रम में महिला बाल विकास मंत्री सुश्री निर्मला भूरिया, विधायक तथा पूर्व मंत्री श्रीमती अर्चना चिटनीस, अपर मुख्य सचिव श्री नीरज मंडलोई और विभाग की सचिव सुश्री जी.वी. रश्मि विशेष रूप से उपस्थित थीं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने प्रतीक स्वरूप तीन नवनियुक्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को नियुक्ति-पत्र प्रदान किए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव की उपस्थिति में विधायक श्रीमती अर्चना चिटनीस ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं को अपने कार्य दायित्व का निर्वहन पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करने, विकसित मध्यप्रदेश@2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने में हर संभव योगदान देने और सुपोषित मध्यप्रदेश के निर्माण में अपने दायित्व का पूर्णतः पालन करने की शपथ दिलाई। नवनियुक्त आँगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं ने विधानसभा संचालन की प्रक्रिया भी देखी।

प्रमुख बिन्दु

- आंगनबाड़ी में आने वाले हर बच्चे की देखभाल श्रीकृष्ण की तरह करें।
- नवनियुक्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को नियुक्ति पत्र के रूप में बच्चों की मुस्कुराहट, पोषण और माताओं के स्वास्थ्य व सुरक्षा की जिम्मेदारी निभाने का वचन पत्र सौंपा जा रहा है।
- हमारी बहनें अपना दायित्व पूर्ण समर्पण और प्रतिबद्धता से निभाएंगी और प्रदेश को कुपोषण के खिलाफ लड़ाई में विजय दिलवाएंगी।
- मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने प्रतीक स्वरूप तीन नवनियुक्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को नियुक्ति-पत्र प्रदान किए।
- विकसित मध्यप्रदेश@2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने में हर संभव योगदान देने और सुपोषित मध्यप्रदेश के निर्माण में अपने दायित्व का पूर्णत: पालन करने की शपथ दिलाई।
- नवनियुक्त आँगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं ने विधानसभा संचालन की प्रक्रिया भी देखी।
- आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिक परिवार की सदस्य बन जाती हैं।

subahsaverenews@gmail.com
facebook.com/subahsaverenews
www.subahsavere.news
twitter.com/subahsaverenews

शरद की सुबह

मैं एक बार और आऊंगा
रूक कर जाऊंगा जा
कर और आऊंगा

रूत नहीं हूं मैं हर
बरस आऊं जाऊं
फसल सूखती होगी तो
बरस कर और आऊंगा

कोशिश यही रहेगी
बदला हुआ आऊं
बदलना सीख गया हूं
बदल कर और आऊंगा

ऐसा ना हो कि दुनिया बदल चुके
पहले देख लूंगा फिर और आऊंगा

लिख जो डाले हैं बहुत
तो हैं पर कम हैं
हैं पन्ने कई खाली
मैं लिखने और आऊंगा

ना होंगे वो तो कोई और ही होंगे
लेने वालों को देने और आऊंगा

कुछ काम ऐसे हैं
अभी हो जायें तो अच्छा
रोका गया ऊपर तब भी
उतर कर और आऊंगा

सवाल उठेंगे क्यों ही
ऐसा कह डाला
अब भी नहीं सुनोगे तो
क्यों कर और आऊंगा।

-सुधीर मोता

भोपाल का तापमान
अधिकतम 27 °c
न्यूनतम 23°c

सुबह सवेरे

इंदौर ■ शनिवार, 06 दिसंबर 2025

जो अग्नि हमें गर्मी देती है , हमें नष्ट भी कर सकती है ; यह अग्नि का दोष नहीं है।

चाणक्य नीति

पंजाब में रेलवे ट्रैक पर किसानों की पुलिस से झड़प

- जालंधर में स्टेशन पहुंचने से पहले डिटेन, किसान नेताओं को छोड़ने पर अड़े

चंडीगढ़ (एजेंसी)। पंजाब में किसानों ने अपनी मांगों को लेकर कई जगह रेलवे ट्रैक जाम किया। किसानों की तरफ से फिरोजपुर, जालंधर, अमृतसर समेत कई जगह ट्रैक पर धरना दिया गया। फिरोजपुर में ट्रैक पर बैठे किसानों की पुलिस से झड़प भी हो गई। जालंधर में पुलिस ने जहां कई किसानों को डिटेन किया तो वहीं लुधियाना में भारी पुलिस बल की तैनाती के कारण ट्रैक बाधित नहीं हो पाया। दूसरी ओर, किसानों ने

अमृतसर के देवीदास पुरी में रेलवे ट्रैक जाम कर दिया और सैकड़ों की संख्या में धरना देने पहुंचे। वहीं, फिरोजपुर में भी ऐसा ही आलम दिखा। इसके चलते कई जगह ट्रेनें भी कैंसिल की गई। इससे पहले पंजाब पुलिस किसानों के ऐलान का पता चलते ही शुक्रवार तड़के ही किसान नेताओं के घर पहुंच गई और कई नेताओं को हिरासत में ले लिया गया। किसान नेता दिलबाग सिंह, मक्खन सिंह और सुखदेव मगली जैसे नेताओं को घर में ही नजरबंद कर दिया गया है। इसको लेकर भारतीय किसान मजदूर यूनियन के प्रधान दिलबाग सिंह ने कहा- पुलिस ने रात से ही रेड शुरू कर दी।

बिहार समेत 3 राज्यों में एनआईए की रेड

- 2 गिरफ्तार, अवैध हथियार तस्करी केस में ऐक्शन

शेखपुरा (एजेंसी)। अवैध हथियार और गोला-बारूद को लेकर एनआईए ने पटना, नालंदा, शेखपुरा समेत राज्य के सात ठिकानों के साथ हरियाणा और यूपी में छापेमारी कर चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इसमें पटना से शशि कुमार और शेखपुरा से रविरंजन को गिरफ्तार किया है। बिहार के 7, हरियाणा के 2 और यूपी के 13 ठिकानों पर गुरुवार की सुबह से देर शाम तक चली छापेमारी में एनआईए ने बिहार से दो लोगों के

गुड्डू सिंह, आरोपी

अलावा हरियाणा के कुरुक्षेत्र से विजय कालरा और कुश कालरा को दबोचा है। जांच के अनुसार ये सभी एक बड़े नेटवर्क का हिस्सा थे। जो हरियाणा से यूपी और फिर बिहार सहित देश के अन्य हिस्सों में अवैध गोला-बारूद की तस्करी बिक्री और खरीद में शामिल थे। शेखपुरा में नई दिल्ली और पटना से आई राष्ट्रीय जांच एजेंसी की टीम ने स्थानीय एसटीएफ और सिरारी थाना पुलिस के सहयोग से भदौस गांव में छापेमारी कर गुड्डू सिंह उर्फ रवि रंजन को गिरफ्तार किया है। टीम ने उसकी ब्रेजा कार को भी जब्त कर लिया है। गिरफतारी के बाद, टीम ने जयमंगला गांव में खड़ी उसकी सफेद रंग की ब्रेजा कार को जब्त कर लिया। दिल्ली और पटना से आई टीम ब्रेजा कार को स्थानीय थाने को सौंपने के बाद गई।

मुख्यमंत्री ने वर्ष 2026 को कृषि वर्ष के रूप में मनाने संबंधी ली बैठक

वर्ष 2026 को समृद्ध किसान-समृद्ध प्रदेश की थीम पर कृषि वर्ष के रूप में मनाया जाएगा : मुख्यमंत्री

भोपाल (नप्र)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि कृषि का क्षेत्र गरीब वर्ग और किसानों को लाभ पहुंचाने वाला मुख्य क्षेत्र है। कृषि से संबद्ध गतिविधियों के माध्यम से युवाओं को रोजगार और स्वावलंबन के भी कई अवसर उपलब्ध कराए जा सकते हैं। इसी उद्देश्य से प्रदेश में वर्ष 2026 को कृषि वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है। प्रदेश में कृषि के क्षेत्र में नवाचार की पर्याप्त संभावना है। प्रदेश की विविधता से परिपूर्ण भौगोलिक स्थिति को देखते हुए खेती से किसानों की आय बढ़ाने के प्रयासों को गति दी जाए। धान की खेती को प्राथमिकता देने के साथ गेहूं, चना, दलहन, तिलहन, हॉर्टीकल्चर आदि के क्षेत्र में भी अन्य राज्यों के साथ ही अन्य देशों में हो रहे नवाचारों से अवगत कराने के लिए कृषकों को विविध देशों का भ्रमण कराया जाए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने यह निर्देश शुक्रवार को वर्ष 2026 के कृषि वर्ष मनाने के संबंध में विधानसभा के समिति के कक्ष में आयोजित बैठक में दिए। बैठक में किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री श्री एदल सिंह कंषाना, पशुपालन एवं डेयरी राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री लखन पटेल, पूर्व मंत्री श्री गोपाल भार्गव, मुख्य सचिव श्री अनुराग जैन सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि वर्ष 2026 को समृद्ध किसान-समृद्ध प्रदेश की टैगलाइन के साथ कृषि वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों के विकास और रोजगार सृजन पर विशेष फोकस रहेगा। किसानों की आय दोगुनी करने से आगे बढ़कर कृषि को लाभकारी, टिकाऊ और तकनीक प्रेरित, रोजगार सृजन मॉडल में परिवर्तित करना कृषि वर्ष का मूल उद्देश्य है। अतः आत्मनिर्भर किसान, उन्नत कृषि और कृषकों के हित में बाजार से संबंधों के आधार पर ग्रामीण अर्थव्यवस्था के माध्यम से समृद्ध प्रदेश के निर्माण के विजन से गतिविधियां संचालित की जाएं। कृषि उद्यानिकी, पशुपालन, मत्स्य एवं वानिकी सहित सभी संबद्ध क्षेत्रों को एकीकृत करते हुए जिला आधारित क्लस्टर विकास के लिए गतिविधियां संचालित की जाएं। उच्च उत्पादकता, प्राकृतिक खेती, डिजिटल सेवाओं, प्रसंस्करण एवं निर्यात उन्मुख कृषि के माध्यम से किसान की शुद्ध आय में वृद्धि के लिए प्रयास हों और ग्रामीण युवाओं के लिए नई पीढ़ी के कृषि आधारित रोजगार जैसे ड्रोन सर्विस, एफपीओ प्रबंधन, खाद्य प्रसंस्करण, हाइड्रोपोनिक्स आदि के अवसरों का सृजन किया जाए। किसानों की शुद्ध आय में तेजी और स्थायी वृद्धि करने, कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में रोजगार के अधिक से अधिक अवसर उपलब्ध करने, किसानों के लिए उनके उत्पादों की बाजार में पहुंच सुनिश्चित करने और उनकी खाद्य प्रसंस्करण क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से गतिविधियां संचालित की जाएं।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव की अध्यक्षता में हुई बैठक में कृषि वर्ष का मासिक कैलेंडर तैयार किया गया, जिसमें किसानों को साथ लेकर राज्य से जिला स्तर तक महोत्सव, मेले आदि की रूपरेखा बनी। गैर सरकारी और उन्नत किसानों को भी इन प्रयासों से जोड़ा जाएगा। बैठक में बताया गया कि कृषि वर्ष 2026 में प्राकृतिक खेती को हर गांव तक पहुंचाने, आर्गेनिक तथा अन्य कृषि उत्पादों को बेहतर बाजार मूल्य उपलब्ध कराने, कृषि और कृषि मंडियों के आधुनिकीकरण, बेहतर मृदा संरक्षण, उद्यानिकी और खाद्य प्रसंस्करण पशुपालन और डेयरी तथा मछली पालन में नवाचार पर विशेष फोकस रहेगा। वर्ष 2026 में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में की जाने वाली गतिविधियों और वातावरण निर्माण और किसानों की जागरूकता के लिए चलाए जाने वाले अभियानों की माहवार जानकारी दी गई।

कृषि वर्ष में होने वाली गतिविधियों के अंतर्गत राज्य स्तरीय एग्रो विजन कार्यक्रम और प्रत्येक जिला और विकासखंड स्तर पर मृदा स्वास्थ्य परीक्षण, आधुनिक कृषि तकनीक, प्राकृतिक खेती और उर्वरकों के संतुलित उपयोग के संबंध में गतिविधियां संचालित की जाएंगी।

सनातन के काम करने वाले हैं, बंगाल भी हमारा है

- धीरेंद्र शास्त्री बोले-भारत में जहां बुलाएंगे, वहां गीता पाठ करेंगे

जयपुर (एजेंसी)। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने कहा-भारत में जहां भी बुलाया जाएगा, वहां गीता पाठ करेंगे। हम देशद्रोही थोड़े ही हैं। सनातन के काम करने वाले हैं, हर जगह जाते हैं। पश्चिम बंगाल भी हमारा है। विपक्ष का आरोप है कि शास्त्री अक्सर वहीं जाते हैं, जहां चुनाव होते हैं। इस

पर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने कहा- हम किसी राजनीतिक दल के पक्ष में नहीं हैं, इसलिए हमारा कोई राजनीतिक विपक्ष नहीं है। बाकी दृष्टि आपकी है। बंगाल में बाबरी विवाद को लेकर पूछे गए सवाल पर कहा- वहीं जाकर बोलेंगे, खबर आप तक आ जाएगी। मुस्कराते हुए आगे कहा- ये राजनेताओं के काम हैं। हम धार्मिक गुरु हैं। हमसे गीता पाठ और रामायण के बारे में पूछो। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री शुक्रवार को जयपुर में कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय के विवाह समारोह में शामिल होने पहुंचे। जयपुर एयरपोर्ट पर मीडिया ने उनसे पश्चिम बंगाल में होने वाले गीता पाठ कार्यक्रम के बारे में बात की।

आप मंदिर के धन का उपयोग बैंक बचाने के लिए नहीं कर सकते

- सुप्रीम कोर्ट ने केरल सरकार को दिया झटका, हाईकोर्ट का आदेश बरकरार

कहा-मंदिर का चढ़ावा भगवान की संपत्ति है, बैंकों को बचाने के लिए नहीं

नई दिल्ली (एजेंसी)। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि मंदिर में चढ़ा हर एक रुपया भगवान की संपत्ति है और इसे किसी भी को-ऑपरेटिव बैंक की आर्थिक हालत सुधारने के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने केरल की कई को-ऑपरेटिव बैंकों की याचिकाएं खारिज कर दीं और हाईकोर्ट के उस आदेश को बरकरार रखा, जिसमें तिरुनेल्ली मंदिर देवस्वम् को जमा राशि दो महीने के भीतर लौटाने को कहा गया था। चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच ने मामले की सुनवाई की। इस दौरान सीजेआई ने बैंकों की तरफ से पेश वकीलों से पूछा- क्या आप मंदिर का पैसा बैंक बचाने के

लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। कोर्ट ने कहा कि यह धन सुरक्षित और भरोसेमंद राष्ट्रीयकृत बैंक में रखा जाना चाहिए, जहां मंदिर को ज्यादा ब्याज भी मिले। हालांकि, कोर्ट ने बैंकों को यह छूट दी कि वे समय बढ़ाने के लिए हाईकोर्ट से अनुरोध कर सकते हैं। केरल के तिरुनेल्ली मंदिर देवस्वम ने 2025 की शुरुआत से अपनी फिक्स्ड डिपॉजिट की रकम वापस मांगते हुए कई बार स्थानीय कोऑपरेटिव बैंकों से गुहार लगाई, लेकिन बैंकों ने पैसे लौटाने से लगातार इनकार कर दिया। मंदिर ट्रस्ट का कहना था कि यह राशि मंदिर के कामकाज और रखरखाव के लिए जरूरी है।

गर्लफ्रेंड से विवाद के चलते मेल नर्स ने किया सुसाइड

तीन दिन पहले खरीदी थी नई कार, भोपाल से की थी बीयूएमएस की पढ़ाई

भोपाल (नप्र)। निशातपुरा इलाके में गुरुवार देर रात एक निजी अस्पताल के मेल नर्स ने अपने घर में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। उसके भाई का आरोप है कि इससे पहले उसका गर्लफ्रेंड से विवाद हुआ था। हालांकि उसने कोई सुसाइड नोट नहीं छोड़ा है। पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है।

पुलिस के मुताबिक कृषक नगर निवास छोटू पुत्र कमल राजपूत (26) एक निजी अस्पताल में मेल नर्स था। वह मूल रूप से शमशाबाद जिला विदिशा का रहने वाला था। भोपाल से ही उसने बीयूएमएस की पढ़ाई की थी। कृषक नगर करोंद में वह अपने दोस्तों के साथ किराए के मकान में रहता था।

घटना के समय रूम पर नहीं था दोस्त- गुरुवार रात उसका दोस्त किसी काम से बाहर चला गया, तभी छोटू राजपूत ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पीएम के लिए भेज दिया। घर की तलाशी लेने पर पुलिस को किसी तरह का कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। पुलिस ने उसके मोबाइल फोन को जब्त कर जांच शुरू कर दी है।

भाई बोला नई कार दिलाई थी, खुशी-खुशी बात की, अचानक मिली मौत की सूचना- मृतक के भाई दीपक राजपूत ने बताया कि गुरुवार शाम को मेरी भाई छोटू से फोन पर बात हुई थी। तीन दिन पहले उसे स्विफ्ट डिजायर कार दिलाई थी। इसके बाद से ही वह बेहद खुश था। मैंने कॉल पर उसे बताया कि अपनी कार की सर्विस कराने भोपाल आने वाला हूं। उसने यहां आने के बाद कई जगह घुमाने का वादा किया था। चंद घंटे बाद ही उसकी मौत की सूचना से पूरा परिवार सदमे में है। उसने एक युवती से प्रेम प्रसंग के चलते जान दी है।

आखिरी बार उसी लड़की से उसकी कॉल पर बात हुई, उसके रूम पार्टनर ने हमें बताया है कि जब वह घर से निकला था, तब छोटू उसी युवती से कॉल पर बात कर रहा था। उसकी मौत की सूचना के बाद युवती ने उसके दोस्त को मैसेज किया है, जिसमें उसने उसके संबंध में किसी को भी न बताने की बात लिखी है। उसी लड़की की प्रताड़ना से तंग आकर भाई ने जान दी है। इसके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए।

गांव में होगा अंतिम संस्कार- शुक्रवार दोपहर पीएम के बाद बॉडी परिजनों को सौंप दी गई है। बॉडी को परिजन एम्बुलेंस से गांव लेकर रवाना हो गए हैं। जहां अंतिम संस्कार होगा। वहीं पुलिस का कहना है कि मृतक के मोबाइल फोन की जांच कराई जाएगी। जांच में आए तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई तय करेंगे।

डीएमके सांसद की टिप्पणी पर संसद में मचा कोहराम

- बालू ने हाईकोर्ट जज को बता दिया 'आरएसएस जज', भड़का सत्ता पक्ष
- रिजिजू बोले-न्यायपालिका को बदनाम करने की आपकी हिम्मत कैसे हुई

नई दिल्ली (एजेंसी)। संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान लोकसभा में शुक्रवार को तमिलनाडु से डीएमके सांसद टीआर बालू और केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू के बीच तीखी बहस हुई। डीएमके सांसद ने एक मुद्दे पर बोलते हुए एक हाईकोर्ट के जज को आरएसएस जज कह दिया। किरेन रिजिजू ने इस पर तुरंत आपत्ति जताई। रिजिजू ने कहा- आप एक जज को आरएसएस का जज कैसे कह सकते हैं।

यह संसद की मर्यादा का उल्लंघन है। आप एक जज के लिए असंसदीय भाषा का इस्तेमाल नहीं कर सकते। आप माफी मांगिए। न्यायपालिका पर कलंक लगाने की आपकी हिम्मत कैसे हुई। इधर, राज्यसभा में विपक्ष ने इंडिगो में स्टाफ की कमी के चलते देश भर में फ्लाइट ऑपरेशन ठप होने के मुद्दे पर केंद्र से जवाब मांगा। रिजिजू ने कहा कि नागरिक उड्डयन मंत्री नायडू हालात की समीक्षा कर रहे हैं।

आजम खान के बेटे अब्दुल्ला को सात साल की सजा

- फर्जी पासपोर्ट मामले में भी कोर्ट ने पाया दोषी, सुनाई सजा

रामपुर (एजेंसी)। रामपुर की एमपी/एमएलए कोर्ट ने सपा नेता आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम को 7 साल की सजा सुनाई है। पेशी के दौरान अब्दुल्ला आजम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हाजिर हुए। कोर्ट ने आजम खान के बेटे अब्दुल्ला को फर्जी पासपोर्ट मामले में दोषी करार दिया है। जन्मतिथि बदलवाने के मामले में यह अब्दुल्ला की तीसरी सजा है। आज से लगभग दो सप्ताह पहले दो पैन कार्ड मामले में आजम खान और अब्दुल्ला आजम दोनों को ही 7-7 साल की सजा हुई थी। दो बर्थ सर्टिफिकेट मामले में 2 साल पहले 2023 दोनों को 7-7 साल की सजा हुई थी। फिलहाल दोनों रामपुर जेल में बंद हैं।

4 दिन में 1200+फ्लाइट रद्द, बैकफुट पर सरकार

- वीकली रेस्ट नियम तत्काल वापस, देशभर में कोहराम

इंडिगो पैसेंजर 4 दिनों से हैं परेशान, मारपीट के हालात

नई दिल्ली (एजेंसी)। केंद्र सरकार ने देश की सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी इंडिगो को फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन के नए नियमों से राहत दे दी है। सरकार ने अपना वह आदेश तत्काल वापस ले लिया है, जिसके तहत पायलटों समेत अन्य क्रू को हर 7 दिनों में लगातार 48 घंटे का वीकली रेस्ट देना अनिवार्य किया गया था। डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन के नए नियमों में वीकली रेस्ट और छुट्टियों को अलग-अलग

मानने का प्रावधान था। यह नियम पायलटों और अन्य क्रू के थकान को कम करने के लिए बनाया गया था। हालांकि, अब क्रू को पहले की तरह हर 7 दिनों में लगातार 36 घंटे का आराम मिलेगा। डीजीसीए के नए नियमों के कारण इंडिगो शुक्रवार को लगातार चौथे दिन क्रू मेंबर्स (पायलट सहित अन्य फ्लाइट स्टाफ) की कमी से जूझती दिखी।

अलर्ट मोड में देश की सभी सुरक्षा एजेंसियां, बदली रणनीति

भारत में तबाही मचाने की तैयारी में 100 से ज्यादा आतंकी

नई दिल्ली (एजेंसी)। जम्मू-कश्मीर में पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ को लेकर सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ गई है। सीमा सुरक्षा बल के कश्मीर फ्रंटियर के आईजी अशोक यादव ने बताया कि नियंत्रण रेखा (एलओसी) के उस पार लगभग 69 लॉन्चपैड ऐक्टिव हैं, जहां 100 से ज्यादा आतंकी घुसपैठ के इंतजार में बैठे हैं। यह गतिविधि हाल के महीनों में तेज हुई है और ड्रोन गश्त, पैदल मूवमेंट में भी बढ़ोतरी हुई है। आतंकवादी अब घुसपैठ के लिए नए रास्तों का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन भारत की सुरक्षा व्यवस्था भी उसके हिसाब से खुद को ढाल चुकी है। काउंटर-इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड को और मजबूत किया गया है ताकि किसी भी कोशिश को नाकाम किया जा सके। जैसे-जैसे सर्दियां नजदीक आती हैं, एलओसी पर बर्फबारी शुरू होने से पहले घुसपैठ बढ़ जाती है, क्योंकि बर्फ जमा होने के बाद रास्ते बंद हो जाते हैं। अशोक यादव ने कहा कि दूसरे पक्ष से लगातार मूवमेंट दिख रहा है और ड्रोन निगरानी में भी इजाफा हुआ है। उन्होंने आशंका जताई कि पहाड़ों पर बर्फ पड़ने से पहले घुसपैठ की और कोशिशें हो सकती हैं। इस साल अब तक चार घुसपैठ प्रयासों में आठ आतंकियों को ढेर किया गया है, जिससे साफ है कि नए रास्तों और चालों के बावजूद भारतीय सुरक्षा तंत्र स्थिति पर काबू बनाए हुए

है। लेकिन अशोक यादव ने चेतावनी दी कि यह इलाका बेहद कठिन है, कड़ाके की ठंड, ऊबड़-खाबड़ पहाड़, खराब मौसम, हमलों का खतरा, स्नाइपिंग, सीजफायर उल्लंघन और फिदायीन हमले ये सब मिलकर चुनौती को बढ़ा देते हैं।

पीओके यानी पाकिस्तान की बॉर्डर एक्शन टीम, जिसमें पाक सैनिक और आतंकवादी शामिल होते हैं, रात में घुसपैठ और घात लगाकर हमले करती है। सर्दियों में जोखिम भरे रास्तों का इस्तेमाल बढ़ जाता है, क्योंकि ऐसे मार्गों पर सामान्य रूप से पेट्रोलिंग कम होती है। भारत को आने वाले हफ्तों में घुसपैठ बढ़ने की आशंका है। बहरहाल, सेना ने इस खतरे से निपटने के लिए अपनी क्षमताएं भी बढ़ानी शुरू कर दी हैं। टकराव की आशंका मद्देनजर बेहतर सेंसर, ड्रोन, मल्टी-लेयर निगरानी और विशेष प्रशिक्षण सब पर तेजी से काम हो रहा है। अशोक यादव ने कहा कि मई में हुए ऑपरेशन सिंदूर ने भारत की तैयारियों को नया आकार दिया है। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (पीओके) के आतंकी ट्रेनिंग कैम्पस और लॉजिस्टिक हब पर लगातार निगरानी रखी जा रही है।

कई कैम्पस भारतीय स्ट्राइक की आशंका में दूसरे इलाकों में शिफ्ट कर दिए गए हैं। भारतीय खुफिया एजेंसियों के मुताबिक, पाकिस्तान की डीप स्टेट लश्कर-ए-तैयबा (एलएटी) को अब पहले से ज़्यादा तरजीह दे रही है, जबकि जैश-ए-मोहम्मद कमजोर स्थिति में पहुंच गया है। ऑपरेशन सिंदूर में जैश को भारी नुकसान हुआ है।

फरार पिता को पकड़ने के लिए बेटे की हिरासत पर हाई कोर्ट की कड़ी नाराजगी

'बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका' पर इसे 'मूलभूत अधिकारों का उल्लंघन' माना

इंदौर। चंदन नगर थाने की पुलिस और टीआई इंद्रमणि पटेल की मनमानी और एक इंजीनियर युवक को अवैध हिरासत में रखने के मामले पर हाईकोर्ट की कड़क टिप्पणी सामने आई। नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी रियल एस्टेट कारोबारी के बेटे राजा को चंदन नगर पुलिस ने अनाधिकृत रूप से बंदी बनाकर करीब 30 घंटे तक थाने में बैठा कर रखा। उसके हाथों में हथकड़ी डाली गई और बिना अपराध, बिना एफआईआर, बिना गिरफ्तारी वारंट थाने में रोककर रखा गया। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की डबल बेंच ने इसे 'मूलभूत अधिकारों का खुला उल्लंघन' करार देते हुए पुलिस पर तीखी टिप्पणी की। अदालत में पेश वीडियो और पेन ड्राइव फुटेज में जब राजा के हाथों में हथकड़ी और 30 घंटे की होल्डिंग साफ दिखाई दी, तो जजों ने कठोर शब्दों में कहा 'हथकड़ी लगा दी थी, बेड़ियां भी पहना देते, यह किसी भी हाल में स्वीकार्य नहीं।' इस पूरे प्रकरण के खिलाफ राजा के परिवार ने हाईकोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की। यह याचिका उसके साले आकाश तिवारी ने वकील नीरज सोनी की मदद से दाखिल की थी। इसमें पुलिस की

अवैध हिरासत और मनमानी कार्रवाई का उल्लेख किया गया। हाई। कोर्ट ने चंदन नगर थाना प्रभारी टीआई इंद्रमणि पटेल और संबंधित पुलिसकर्मियों पर विभागीय जांच और एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए और पुलिस कमिश्नर को दो हफ्तों में पूरी रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया।

युवक का अपराध से वास्ता नहीं

युवक के परिवार ने आरोप लगाया कि चंदन नगर पुलिस ने उसे पिता की गिरफ्तारी के दबाव में एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया। जबकि, युवक एक पढ़ा-लिखा इंजीनियर है और किसी भी अपराध से उसका कोई लेना-देना नहीं। सवाल यह भी उठ रहा है कि जब आरोपी पिता फरार था, तो पुलिस ने उसकी जगह बेटे को निशाना क्यों बनाया, और किस अधिकार से उसे हथकड़ी पहनाई गई? हाईकोर्ट ने इन सभी पहलुओं पर कड़ी नाराजगी जताई है। इस प्रकरण के सामने आते ही टीआई इंद्रमणि पटेल की पुरानी विवादित करतूत भी चर्चाओं में लौट आई हैं। पहले भी पटेल पर मनमानी के कई आरोप लग चुके हैं।

पुलिस की शक्ति का दुरुपयोग

कानूनी जानकारों के अनुसार किसी भी नागरिक को बिना अपराध के थाने में बैठाना, वह भी हथकड़ी लगाकर, पुलिस की शक्ति का सीधा दुरुपयोग है। कानून में यह स्पष्ट है कि हथकड़ी केवल गंभीर अपराध या भागने की ठोस आशंका होने पर ही लगाई जा सकती है, जो इस केस में बिल्कुल नहीं था। हाईकोर्ट के निर्देशों के बाद अब इंदौर पुलिस पर भारी दबाव है कि वह अपने थाना प्रभारी और स्टाफ की इस हरकत पर पारदर्शी रिपोर्ट पेश करे। अदालत की सख्ती के बाद यह मामला सिर्फ एक थाने की मनमानी तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पुलिस प्रशासन की जवाबदेही और कानून के राज पर बड़ा सवाल बनकर खड़ा हो गया है।

उन्होंने अनवर हुसैन नामक व्यक्ति के मामले में कोर्ट में फर्जी अपराधों की सूची पेश की थी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने पटेल और एडिशनल डीसीपी को केस में पक्षकार बनाने के आदेश दिए थे। इससे पहले लसूड़िया थाने में पदस्थ रहते हुए भी पटेल का नाम कई विवादित कार्रवाइयों, मनमाने व्यवहार और दबाव में लिए गए निर्णयों में सामने आता रहा है। लेकिन, रसूख और संरक्षण के कारण उन पर कभी कोई कड़ी विभागीय कार्रवाई नहीं हुई।

एसआईआर ड्यूटी में लापरवाही पर 16 को कलेक्टर का नोटिस

24 घंटे में जवाब अनिवार्य, अन्यथा एक पक्षीय कार्रवाई

इंदौर। मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण कार्य (एसआईआर) के दौरान जिम्मेदारियों में लापरवाही बरतना 16 अधिकारियों और कर्मचारियों को भारी पड़ गया। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी शिवम वर्मा ने निर्वाचन कर्तव्य में उदासीनता और आदेशों की अवहेलना करने पर सभी को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। कलेक्टर ने स्पष्ट निर्देश दिए कि 24 घंटे के भीतर संबंधित अधिकारी अपना जवाब निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के माध्यम से प्रस्तुत करें, अन्यथा एकपक्षीय कार्रवाई की जाएगी। जिन कर्मचारियों को नोटिस जारी किया गया, उनमें जनपद पंचायत समन्वयक मुकेश वर्मा, सहायक शिक्षक राजेंद्र कुवाल, प्राथमिक शिक्षक कांता माने, सहायक ग्रेड-3 कर्मचारी राज्य बीमा सेवाएं की सुहागील मरावी, सहायक शिक्षक संहिता अरदास, नगर निगम (राजस्व) से मनीष

कुरवाड़े, सहायक ग्रेड-3 आबिद खान, नर्मदा विकास प्राधिकरण के राधेश्याम भंवर, गृह निर्माण अधोसंरचना विकास के प्रतीक लेले और घनश्याम आर्य, कर्मचारी राज्य बीमा के विपिन कालेसिरिया तथा आंगनवाड़ी कार्यकर्ता शकुंतला पाल, रेखा यादव, किरण वर्मा और शैलजा वर्मा शामिल हैं। इसके अलावा विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 208 इंदौर-5 में कार्यरत लैब टेक्नीशियन विवेक अखंड को भी चुनावी कार्य में लापरवाही पर नोटिस जारी किया गया। सभी को मिलाकर 16 अधिकारियों और कर्मचारियों के विरुद्ध यह कड़ी कार्रवाई की गई। कलेक्टर ने कहा कि निर्वाचन कार्य अत्यंत संवेदनशील और प्राथमिकता का विषय है, ऐसे में किसी भी प्रकार की लापरवाही सहन नहीं की जाएगी। प्रशासन ने संकेत दिए हैं कि इस महत्वपूर्ण चुनावी प्रणाली की पारदर्शिता और दक्षता बनाए रखने के लिए आगे भी सख्त रुख जारी रहेगा।

बैट और पाइप से दो युवकों पर हमला

इंदौर। विवाद को लेकर कुछ आरोपियों ने रास्ते में जा रहे दो युवकों को घेरकर उन पर बैट और पाइप से हमला कर दिया। हमले में युवक का सिर फूट गया, जबकि दूसरे को भी गंभीर चोटें आई हैं। हमले के बाद सभी आरोपी मौके से फरार हो गए। बाणगंगा पुलिस के मुताबिक, घायल युवकों के नाम गीतांशु और हर्ष उर्फ हर्षु लोधी हैं। घटना सांवेर रोड पर स्थित किराना दुकान के सामने हुई। फरियादी गीतांशु ने बताया कि वह और उसका दोस्त हर्ष पैदल उसके काका राधेश्याम के घर मारुति नगर दवाई पूछने जा रहे थे। रास्ते में उन्हें आरोपी दीपू वर्मा और अंकित यादव मिले। दोनों आरोपियों ने विवाद को लेकर हर्ष को गालियां देना शुरू कर दिया। जब गीतांशु और हर्ष ने गाली देने से मना किया तो आगे रास्ते में आरोपियों के अन्य साथी भय्यू उर्फ चड्डा, बाबू उर्फ योगेश मीणा, मयंक और शंकर मुजालदे भी आ गए और सभी ने मिलकर दोनों युवकों पर हमला कर दिया।

महिला और उसके परिवार से मारपीट

इंदौर। आपसी विवाद के चलते कुछ आरोपियों ने महिला और उसके परिवार के सदस्यों के साथ मारपीट कर दी। घटना बाणगंगा थाने के सामने सर्विस रोड पर हुई। बाणगंगा पुलिस ने फरियादी शिवांगी कोकश निवासी आदर्श गणपति नगर की रिपोर्ट पर तीन आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया है। आरोपियों की पहचान पूजा मडवाल निवासी जनता क्वार्टर पुलिस लाइन, आरती गुर्जर निवासी छोटी भमौरी और नीतेश उर्फ गोलू निवासी भमौरी के रूप में हुई है। फरियादी शिवांगी कोकश ने बताया कि वे थाने के सामने सर्विस रोड पर मौजूद थीं, तभी उन्हें आरोपी मिले। आरोपियों ने शिवांगी को देखते ही गालियां देना शुरू कर दिया। जब शिवांगी ने गाली देने से मना किया तो आरोपियों ने उनके साथ मारपीट शुरू कर दी।

दरवाजा तोड़कर लाखों के जेवरात चोरी

इंदौर। पलासिया थाना क्षेत्र स्थित गायत्री अपार्टमेंट में दिनदहाड़े अज्ञात चोरों ने फ्लैट का मुख्य गेट तोड़कर लाखों के जेवर उड़ा लिए। फ्लैट में रहने वाले आशीष कदम ने बताया कि उनके फ्लैट नंबर 101 को अज्ञात चोरों ने निशाना बनाया। चोरों ने फ्लैट के मेन गेट की कुंडी काटकर अंदर प्रवेश किया। घर के अंदर घुसने के बाद चोरों ने पूरे फ्लैट की तलाशी ली और वहां रखे गहने चुरा लिए। इसी प्रकार, जेलरोड स्थित डॉलर मार्केट में दुकान को अज्ञात चोरों ने निशाना बनाते हुए सेंध लगा दी। चोरों ने बेसमेंट में स्थित दुकान से 16 मोबाइल, स्मार्ट वॉच और हजारों की नकदी चुरा ली। एमजी रोड पुलिस ने व्यापारी हेमंत रंगानी की शिकायत पर अज्ञात आरोपी के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया है। फरियादी ने बताया कि हरिओम कलेक्शन के बेसमेंट में उनकी शॉप नंबर 15 स्थित है। 28 नवंबर की रात चोरों ने दुकान में वारदात की थी।

स्कूली छात्रा से छेड़छाड़, मारपीट

इंदौर। राजेंद्र नगर स्थित शासकीय कन्या पाठशाला के सामने स्थित होटल कर्मचारियों द्वारा स्कूली छात्रा से छेड़छाड़ एवं मारपीट की गई। मामले में प्राचार्य ने राजेंद्र नगर थाने पर शिकायत दर्ज कराई। इसके बाद प्राचार्य ने क्षेत्रीय पार्षद प्रशांत बडवे को स्कूल प्रबंधन द्वारा उक्त समस्या बताई गई। इसमें बताया कि होटल में दिनभर कपड़ा बांधकर लड़के लड़कियां आते है। और दो-दो घंटे रुक के निकल जाते हैं। साथ ही होटल पर आने वाले लड़कों एवं स्टाफ द्वारा छोटी-छोटी बालिकाओं से अभद्र टिप्पणी की जाती है. इस पर पार्षद ने भी पुलिस को सूचना की। जब पुलिस मौके पर पहुंची तब भी होटल में कम उम्र के लड़के-लड़कियां मौजूद थे। रहवासियों ने भी होटल को लेकर विरोध जताया। पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है।

मुंबई से बरामद किराए पर ली कार

इंदौर। पिछले दिनों विजयनगर पुलिस ने किराए पर ली कार को खुर्दबुर्द करने के मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया था। आरोपी अंकित पिता हरिशंकर विश्वकर्मा निवासी अंबिका नगर थाना विजयनगर क्षेत्र से पुलिस पूछताछ कर रही है। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उसके द्वारा महिन्द्रा कंपनी की थार, आर्टिगो, मारुति की बलेनो, प्राक्स सहित कई गाड़ियां किराए पर ली थी। कुछ दिन तक कार मालिक को किराया चुकाया, इसके बाद उन्हें इधर-उधर खड़ा कर दिया। किराए की कार उसने मुंबई में खड़ी की थी। इस पर विजय नगर पुलिस की टीम ने मुंबई से थार गाड़ी को बरामद किया। आरोपी अब तक 51 लाख 30 हजार की कारों को किराए पर धोखाधड़ी पूर्वक ले चुका है। इसके पहले भी वह इस तरह की घटना कारित करता रहा है। आरोपी की मानें तो किराए की कार लेकर वह घुमने निकल जाता था। इस दौरान जहां मर्जी होती वहां कार खड़ी कर इंदौर लौट आता था। यहां आकर फिर अन्य मालिक को झांसे में लेकर कार हथिया लेता और उसे भी बाहरी राज्यों में छोड़ आता था। पुलिस आरोपी से अन्य वारदातों को लेकर पूछताछ कर रही है।

मरीज को निजी अस्पताल भेजने वाले सरकारी डॉक्टर का वेतन काटा गया

ड्यूटी के समय घर पर आराम कर रही महिला डॉक्टर निलंबित

इंदौर। एमवाय अस्पताल हमेशा मरीजों को निजी अस्पताल में भेजने के लिए चर्चा में रहा। ऐसा ही एक मामला फिर सामने आया, जब मरीज को फिर निजी अस्पताल में भेजने का मामला सामने आया। इस मामले में एक डॉक्टर का 15 दिन का वेतन काटा गया। ड्यूटी के समय घर पर आराम कर रही महिला सीनियर डॉक्टर को निलंबित करने की कार्रवाई की गई। कुछ दिन पहले अस्पताल में रात के समय रतलाम से न्यूरोसर्जरी विभाग में एक मरीज इलाज के लिए आया। रातभर ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर ने उसका इलाज करने के बजाय जमीन पर रखा। इसके बाद उससे कहा कि आयुष्मान कार्ड है, तो इंडेक्स अस्पताल में इलाज करवाओ और उसे भेज दिया। मामले में मरीज द्वारा लिखित शिकायत के बाद जांच की गई। जांच में सामने आया कि विभाग में एमसीएच के विद्यार्थी द्वारा मरीज को निजी अस्पताल में इलाज के लिए भेजा गया। इसके एवज

में उसे निजी अस्पताल की ओर से राशि भी मिलती है। मामले में जांच के बाद डॉक्टर का 15 दिन का वेतन काटा गया है।

ड्यूटी डॉक्टर नहीं मिली

एमवाय अस्पताल में जिन डॉक्टरों की ड्यूटी लगती है, वे इस दौरान निजी अस्पताल में रहते हैं या फिर घर पर आराम करते रहते हैं। हाल ही में सिमरोल सड़क हादसे के बाद घायलों को इलाज के लिए एमवाय अस्पताल भेजा गया था, लेकिन इमरजेंसी मेडिसिन विभाग में कोई ड्यूटी डॉक्टर नहीं था। हादसे के बाद डीन पहुंचे तो कोई डॉक्टर नहीं मिला। दो घंटे बाद ड्यूटी पर महिला सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर पहुंची। कारण पूछने पर कहा कि घर पर थी। इस बीच कलेक्टर भी पहुंचे। लापरवाही सामने आने के बाद डीन ने महिला डॉक्टर को बर्खास्त कर दिया है। डॉ अरविंद घनघोरिया, डीन, एमजीएम मेडिकल कॉलेज ने कहा कि एमवायएच से मरीज को लापरवाही कर निजी अस्पताल में भेजने के मामले में कार्रवाई की गई है। एक डॉक्टर का 15 दिन का वेतन काटा गया है। इसके साथ ही ड्यूटी पर मौजूद नहीं होने पर सीनियर रेजिडेंट को बर्खास्त किया गया है। मरीजों के इलाज में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

गिरोह में सीनियर डॉक्टर भी

मरीजों को निजी अस्पताल में इलाज के लिए भेजने के लिए कई गिरोह बने हुए हैं। इन गिरोह में सीनियर डॉक्टर भी शामिल हैं। उन्हीं के संरक्षण में ड्यूटी डॉक्टर, जूनियर डॉक्टर द्वारा यह कार्य किया जाता है। अस्पताल के हड्डी रोग विभाग के डॉक्टर तो अपने ही खुद के अस्पताल में मरीजों को लापरवाही करवाकर ले जाते हैं। इसी प्रकार पेट रोग विभाग, मेडिसिन विभाग, न्यूरोसर्जरी विभाग आदि से भी मरीज बाहर जा रहे हैं, लेकिन जिम्मेदार इन्हें नजरअंदाज कर देते हैं। इनके गिरोह में एंबुलेंस संचालक, स्टाफ, आउटसोर्स कंपनी के कर्मचारी भी शामिल रहते हैं। यही कारण है कि अस्पतालों में भर्ती मरीजों की संख्या लगातार कम हो रही है।

'सामुदायिक मध्यस्थता केंद्र' ने त्वरित न्याय की बड़ी पहल की

31 में से 11 प्रकरणों का समाधान आपसी सहमति से

इंदौर। पुलिस कमिश्नरेट द्वारा संचालित सामुदायिक मध्यस्थता केंद्र आम लोगों के छोटे-बड़े विवादों का तेजी से समाधान निकालने में अहम भूमिका निभा रहा है। आपसी सुलह-सामंजस्य के माध्यम से लोगों को न्याय दिलाने के उद्देश्य से काम कर रहे इस केंद्र ने एक बार फिर उल्लेखनीय कार्य किया। हाल ही में आयोजित जनसुनवाई में आए 31 आवेदनों में से 11 प्रकरणों का समाधान मध्यस्थता केंद्र ने आपसी सहमति से किया। इनमें से चार मामलों में कुल 24,65,000 रुपए आवेदकों को वापस दिलाए, जिससे उनकी लंबे समय से चली आ रही समस्याओं का अंत हुआ। केन्द्र में आवेदक सचिन अग्रवाल निवासी पलसीकर कॉलोनी और विजय कुमार जैसवानी के साथ लेनदेन विवाद

में मध्यस्थता करवाते हुए 21,57,055 रुपए का चेक दिलाया। आवेदक अनीस खान निवासी मेजेस्टिक नगर और चंद्रशेखर मीणा से केंद्र ने हस्तक्षेप कर 2,85,000 की राशि दिलवाई। आवेदक मनीषा मौर्य निवासी नंदबाग कॉलोनी और पल्लवी सोनी के साथ विवाद में 18,000 का निपटारा चेक के माध्यम से करवाया गया। आवेदक कल्पना निवासी परदेशीपुरा का मां-बेटे के आपसी मतभेद को सुलझाते हुए पुत्र ने अपनी मां को हर महीने 5,000 भरण-पोषण देने पर सहमति दी। सामुदायिक मध्यस्थता केंद्र ने वर्ष 2024-25 में अब तक 48 मामलों का सफलतापूर्वक निपटारा किया है, इसके तहत कुल 2,71,48,800 की राशि आवेदकों को वापस दिलाई। यह केंद्र आम लोगों के पारिवारिक विवाद, पड़ोसी झगड़े, किराएदार-मालिक विवाद, छोटे-मोटे सिविल या संपत्ति विवाद, आपसी लेनदेन की समस्याएं को बिना कोर्ट-कचहरी के झंझट में फंसे, केवल बातचीत और सुलह से हल करवाने का सशक्त माध्यम बन गया है।

निजी वाहनों पर हूटर और सायरन का दुरुपयोग बढ़ा, हाईकोर्ट सख्त

16 दिसंबर को सुनवाई में प्रशासन से रिपोर्ट मांगी जाएगी

इंदौर। शहर में अपात्र व्यक्तियों द्वारा निजी वाहनों पर हूटर और सायरन लगाकर प्रभाव जमाने की प्रवृत्ति चिंताजनक रूप से बढ़ रही है। इस गंभीर मुद्दे पर पूर्व पार्षद महेश गर्ग की जून माह में दायर जनहित याचिका पर हाई कोर्ट सख्त रुख अपनाया है।

मामले की पैरवी कर रहे अधिवक्ता मनीष यादव ने बताया कि सुनवाई में कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिए थे कि सभी निजी और अपात्र वाहनों से हूटर-सायरन तुरंत हटाए जाएं। इसके बावजूद पुलिस और आरटीओ द्वारा ठोस कार्रवाई न किए जाने पर कोर्ट ने 10 अक्टूबर की सुनवाई में उपायुक्त से शपथ पत्र प्रस्तुत करने को कहा था। अधिवक्ता यादव का कहना है कि प्रशासन केवल छोटे-मोटे चालानी प्रकरणों को कार्रवाई दिखाकर इतिश्री कर रहा है। जबकि, बड़े पैमाने पर नियमों का उल्लंघन लगातार जारी है। उनका आरोप है कि कई छुटभैये नेता, पार्षद और एमआईसी सदस्य बिना पात्रता के अपने वाहनों पर हूटर-सायरन लगाकर खुलकर नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। नो-पार्किंग में वाहन खड़ा करने से आमजन भ्रमित होते हैं और कानून का दुरुपयोग बढ़ता है। कोर्ट ने इस संबंध में मार्च 2025 के सर्कुलर का कड़ाई से पालन कराने के भी निर्देश दिए हैं। अब 16 दिसंबर को होने वाली अगली सुनवाई में कोर्ट उपायुक्त से पूछेगा कि अब तक आदेशों के पालन में क्या कदम उठाए गए। याचिकाकर्ता पक्ष की मांग है कि अपात्र लोगों पर तत्काल और कठोर कार्रवाई की जाए।

'जयस' जिला अध्यक्ष की याचिका पर हाईकोर्ट सख्त, याचिका खारिज की

एक लाख की कास्ट लगाकर कहा कि यह निजी हित की याचिका

इंदौर। खरगोन में पिछले दिनों आरआई (रक्षित निरीक्षक) और आरक्षक के बीच हुए विवाद के मामले में खरगोन जयस के जिला अध्यक्ष ने इंदौर हाई कोर्ट में अपील की थी। डबल बेंच में मामले की सुनवाई हुई, जिसमें न्यायमूर्ति ने जनहित याचिका (पीआईएल) को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि यह जनहित की नहीं निजी हित की याचिका है। याचिका लगाने वाले जिला अध्यक्ष पर हाई कोर्ट ने एक लाख की कास्ट भी लगाई है। खरगोन रक्षित निरीक्षक सौरभ सिंह कुशवाहा और आरक्षक राहुल चौहान के बीच हुआ विवाद पिछले दिनों बेहद सुर्खियों में रहा।

इस विवाद को जनहित का बताते हुए खरगोन जिले के जयस जिला अध्यक्ष सचिन सिसोदिया की ओर से इंदौर हाई कोर्ट में एक पीआईएल लगाई गई थी। हालांकि, इस पीआईएल से पहले खुद आरक्षक राहुल चौहान ने भी हाईकोर्ट की शरण ली। उन्होंने भी पीआईएल लगाई, जो खुद ही वापस भी ले ली थी। राहुल चौहान द्वारा पीआईएल वापस लेने के बाद जयस खरगोन के जिला अध्यक्ष सचिन सिसोदिया मामले को जनहित का बताते हुए हाईकोर्ट में लेकर आए थे। न्यायमूर्ति विजय कुमार शुक्ला एवं न्यायमूर्ति विनोद कुमार द्विवेदी की डबल बेंच में इस पीआईएल की सुनवाई हुई। जिसमें शासन की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता आनंद सोनी ने तर्क रखे। याचिका लगाने वाले सचिन सिसोदिया और जयस द्वारा आरआई और आरक्षक के विवाद के बाद सोशल मीडिया पर शासन-प्रशासन के खिलाफ टिप्पणी की। आरक्षक राहुल चौहान द्वारा पीआईएल वापस लेने के बाद उसके खिलाफ सोशल मीडिया पर टिप्पणी कर उसे जान से मारने की धमकी तक दी गई। यह सभी तथ्य अतिरिक्त महाधिवक्ता आनंद सोनी ने न्यायमूर्ति के समक्ष रखे। लगभग 15 मिनट तक मामले की सुनवाई हाई कोर्ट में हुई। सभी तर्क और पक्षों को सुनने के बाद न्यायमूर्तियों ने माना कि जो पीआईएल जयस खरगोन के जिला अध्यक्ष द्वारा लगाई गई, वह जनहित की न होकर निजी हित की थी। नाराज होकर कोर्ट ने एक लाख की कास्ट भी लगाई और एक माह में उक्त राशि जमा करने के आदेश दिए हैं।

हेलमेट कार्रवाई को लेकर ट्रैफिक पुलिस की नौटंकी, नाम के मामले

पुलिस आयुक्त के आदेश का ट्रैफिक स्टाफ मखौल उड़ा रहा

इंदौर। हेलमेट की अनिवार्यता को लेकर ट्रैफिक पुलिस ने वृहद स्तर पर अभियान चला रखा है। अभियान में वह केवल नौटंकी कर रही है। इतने बड़े शहर में दिनभर अभियान चलाकर 500-600 वाहन चालकों पर ही कार्रवाई की जा रही है। लाखों वाहन चालक बगैर हेलमेट के ट्रैफिक पुलिस जवानों के सामने से निकलते हैं। पुलिस आयुक्त संतोष सिंह द्वारा हेलमेट को लेकर जागरूकता कार्यक्रम चलाया गया। लोगों को इसके प्रति जागरूक भी किया, लेकिन ट्रैफिक पुलिस के अधिकारी पुलिस आयुक्त के आदेश का खुलेआम मखौल उड़ा रहे हैं।

चंद लोगों पर कार्रवाई कर सुरक्षित सफर का दंभ भरा जा रहा है। पूरा ट्रैफिक स्टाफ भी हेलमेट को लेकर दिखावा कर रहा है। कम संख्या में चालान बनाने की जानकारी लेने पर कहा जाता है कि बल की कमी के कारण अधिक चालान बनाए जाना संभव नहीं है। कई चौराहे तो ऐसे हैं, जहां अभियान की शुरूआत से अब तक किसी भी वाहन चालक का बगैर हेलमेट का चालान नहीं बनाया। इसी तरह की कार्रवाई ई-रिक्शा चालकों पर भी की जा रही है। ट्रैफिक पुलिस की अनदेखी के चलते रिक्शा चालक मनमाने ढंग से वाहन पार्क करते हैं, जिससे रोजाना विवाद की स्थिति बनती है, लेकिन पुलिस इन चालकों पर कड़ी कार्रवाई नहीं कर पाती।

कॉलेज छात्रा से रेप, धर्म बदलने की कोशिश, एफआईआर दर्ज

छात्रा ने हिंदू संगठन से मदद मांगी, उन्होंने पुलिस को सौंपा

इंदौर। डीएवीवी की एमबीए की छात्रा ने मुस्लिम युवक हम्स शेख पर दुष्कर्म, जान से मारने की धमकी और मध्यप्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के तहत एफआईआर लिखवाई। आरोपी ने छात्रा के साथ जबरदस्ती की और मुसलमान बनने के लिए धमकाया और ब्लैकमेल किया। तिलक नगर टीआई मनीष लोधा के मुताबिक संचार नगर निवासी हम्स पुत्र सादिक शेख पीड़िता के साथ पढ़ता था। सहपाठी होने के कारण उसकी बातचीत होने लगी थी।

हम्स ने छात्रा को शादी का प्रस्ताव दिया तो उसने फटकार दिया। कुछ दिन उसने दूरी बनाई, लेकिन बाद में माफी मांग कर दोबारा बातचीत करने लगा। 26 जुलाई को हम्स पीड़िता के घर आ गया और उसकी के साथ जबरदस्ती की। इसके बाद वह ब्लैकमेल करने लगा। अगस्त में पीड़िता की शादी हो गई। उसके बाद पीड़िता को लगा कि वह हम्स परेशान नहीं करेगा। लेकिन वह शादी करने और मुस्लिम धर्म स्वीकारने का दबाव बनाने लगा। आखिरकार हिम्मत कर पीड़िता ने पति को पूरी घटना बताई और बुधवार रात हम्स के खिलाफ केस दर्ज करवाया।

संपादकीय

सवाल विश्वसनीयता का है..

रूसी राष्ट्रपति व्लादिमिर पुतिन के दो दिवसीय भारत दौरे के संदर्भ में दोनों देशों के बीच अनेक समझौतों से इतर इस बात की भी चर्चा रही कि पुतिन का भारत में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से मिलने का कोई कार्यक्रम नहीं था। कांग्रेस का आरोप है कि मोदी सरकार ने जान बूझ कर यह मुलाकात नहीं होने दी। कांग्रेस ने कहा कि यह मोदी सरकार का लोकतांत्रिक परंपरा से हटना और भाजपा की 'असुरक्षा' का संकेत है। कांग्रेस ने सोवियत नेताओं निकोलाई बुल्गानिन और निकिता ख्रुश्चेव की 1955 की भारत यात्रा का हवाला देते हुए कहा कि आज के भारत-रूस संबंध उस शुरुआती भारत-सोवियत साझेदारी से सीधे जुड़े हैं, जो उस वर्ष के अंतिम महीनों में बनी थी। खुद राहुल गांधी ने इस पर अपनी नाराजगी जताते हुए संसद परिसर में मीडिया से चर्चा में कहा कि आमतौर पर परंपरा रही है कि विदेशी मेहमान जब भारत आते हैं तो विपक्ष के नेता से भी उनकी मुलाकात होती है। वाजपेयीजी के समय में होता था, मनमोहनजी के समय में होता था। अब जो हो रहा है, विदेशी मेहमान जब आते हैं या मैं विदेश जाता हूँ तो सरकार उनसे कहती है कि नेता प्रतिपक्ष से मत मिलिए। हमें मैसेज मिलता है कि सरकार ने उनसे कह दिया है कि मुझसे नहीं मिलना है। कारण पूछने पर राहुल ने मुस्कुराते हुए कहा - 'असुरक्षा'। वैसे राहुल गांधी ने कहा वह तथ्यात्मक रूप से सही है। सत्तापक्ष और विपक्ष लोकतंत्र के दो पहिए होते हैं। लिहाजा ज्यादातर लोकतांत्रिक देशों में बड़े देशों के राष्ट्राध्यक्ष वहां राष्ट्राध्यक्षों के साथ प्रतिपक्ष के नेताओं से भी सौजन्य मुलाकात करते हैं। लेकिन मोदी राज में वह परंपरा बंद कर दी गई है। संवैधानिक विशेषज्ञों का कहना है कि विपक्ष के नेता को दरकिनार करना भारत को 'बहुसंख्यकवादी राज्य' की छवि दे सकता है। अलबत्ता राहुल गांधी जो कह रहे हैं, उसमें कितनी सच्चाई है? वैसे मोदी सरकार के इस रवैये के पीछे एक कारण 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद से भाजपा और इंडिया गठबंधन के बीच बढ़ता तनाव है। और राहुल गांधी इसका प्रमुख घटक हैं। राहुल बतौर नेता प्रतिपक्ष लगातार ऐसे मुद्दे उठा रहे हैं, जिनसे मोदी सरकार असहज महसूस कर रही है। संसद के कई सत्र हंगामे की भेंट चढ़ गए। सरकार ने विपक्ष को तमाम मुद्दों को उठाने की अनुमति ही नहीं दी। इसमें दो राय नहीं कि भारत और रूस के बीच समय की कसौटी पर खरे उतरे सम्बन्धों की नींव पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने रखी थी और उसे परवान उनकी बेटी और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने चढ़ाया। इन द्विपक्षीय रिश्तों की खूबी यह है कि दोनों देशों में सत्ता परिवर्तन के बाद भी वो अटूट और अडिग है। हर मुश्किल घड़ी में रूस ने भारत का साथ दिया है। बावजूद इसके अगर मोदी सरकार को राहुल गांधी पर भरोसा नहीं है तो इसका बड़ा कारण तो खुद राहुल ही है। राहुल जिस तरह विदेश में जाकर भी भारत सरकार की खुलेआम आलोचना करते हैं, वो मोदी तो क्या आम भारतीयों को भी नहीं सुहाता। इससे उनकी अगंभीर नेता की छवि बनी है, वो भले इसे अभिव्यक्ति का आजादी का प्रतीक मानें। हालांकि कांग्रेस राहुल के इन भारत विरोधी प्रायोजित दौरों को पीएम मोदी द्वारा विदेशों में कांग्रेस की आलोचना का उदाहरण देकर जायज ठहराने की कोशिश करती है। लेकिन अगर मोदी ने कोई 'गलती' की है तो राहुल उससे भी बड़ी गलती करें, यह तो कहीं से उचित नहीं है। राहुल विदेशी मेहमानों से क्या और कैसी बात करेंगे, जब तक इसका पूरा भरोसा न हो, मोदी सरकार उन्हें शायद ही किसी विदेशी मेहमान से मिलने दे।

संपूर्ण देश के लिए स्थायी प्रेरणा का स्रोत

नजरिया

अवधेश कुमार
लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं।

प्रत्यक्ष और परोक्ष इसके मार्ग में जितनी अड़चनें डाली जा सकती थीं डालीं गईं। जिन लोगों ने शास्त्रों में वर्णित अयोध्या को ही काल्पनिक साबित करने के लिए इतिहास के नाम पर पुस्तकें लिखवाईं, अभियान चलाया न्यायालय में इसके विरुद्ध मुकदमे लड़े और इलाहाबाद उच्च न्यायालय से लेकर उच्चतम न्यायालय के निर्णय पर आज तक प्रश्न खड़ा करते रहे हैं उनसे हमें सकारात्मक प्रतिक्रिया या समर्थन करने की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। ध्यान रखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत के उद्बोधनों के भाव में बिल्कुल समानता थी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का स्वर भी ऐसा ही था।

अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण के साथ शास्त्रीय परंपरा अनुसार निर्माण कार्य पूर्ण हो गया। विरोधियों की प्रतिक्रियाएं वैसी ही हैं जैसी 22 जनवरी 2024 के प्राण प्रतिष्ठा के समय थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंचालक डॉ. मोहन भागवत के बटन दबाने के साथ ध्वज का धीरे-धीरे ऊपर चढ़ना और अंततः मंदिर के शिखर पर विराजमान होकर लहराना भारत के बहुत बड़े वर्ग के लिए वेदनाओं से पूर्ण संघर्ष के युग के समापन और नये युग के सूत्रपात का साक्षात स्वरूप बन गया। सच है कि राजनीतिक और गैर राजनीतिक विपक्ष ने कभी भी श्रीराम मंदिर निर्माण कार्य तो छोड़िए इसके विचार का समर्थन नहीं किया। प्रत्यक्ष और परोक्ष इसके मार्ग में जितनी अड़चनें डाली जा सकतीं थीं डालीं गईं। जिन लोगों ने शास्त्रों में वर्णित अयोध्या को ही काल्पनिक साबित करने के लिए इतिहास के नाम पर पुस्तकें लिखवाई, अभियान चलाया न्यायालय में इसके विरुद्ध मुकदमे लड़े और इलाहाबाद उच्च न्यायालय से लेकर उच्चतम न्यायालय के निर्णय पर आज तक प्रश्न खड़ा करते रहे हैं उनसे हमें सकारात्मक प्रतिक्रिया या समर्थन करने की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। ध्यान रखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डॉक्टर मोहन भागवत के उद्बोधनों के भाव में बिल्कुल समानता थी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का स्वर भी ऐसा ही था। भारत की सही समझ और राष्ट्र के लक्ष्य की यथार्थ कल्पना के कारण स्वर में समानता बिलकुल स्वाभाविक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगर 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की याद दिलाते हुए ध्वजारोहण के साथ संबद्ध किया तो भारत को समझने वालों के लिए यह बिल्कुल स्वाभाविक है। जिन्हें समझ नहीं या समझते हुए भी राजनीतिक रूप से विरोध करना है उनके लिए यह उपहास और विरोध का ही विषय होगा। बात अत्यंत सरल है। किसी भी समाज के अंदर यह भाव बिठा दिया जाए कि आपकी संपूर्ण सभ्यता, जो धर्म से निर्धारित है वह कपोल कल्पनाओं, मिथकों और बहुत हद तक अंधविश्वासों से भरी है तो उसके अंदर एक समाज और राष्ट्र के रूप में बड़े लक्ष्य पाने की प्रेरणा का स्रोत पैदा होना कठिन हो जाएगा। श्रीराम मंदिर आंदोलन केवल एक सामान्य मंदिर के लिए नहीं था, बल्कि उसका लक्ष्य सांस्कृतिक- धार्मिक- राष्ट्रीय पुनर्जागरण तथा ज स्थायी प्रेरणा स्रोत खड़ा करना ताकि भारत जागृत रहे और हम सब देश को शीर्ष पर ले जाने के लिए प्राणपण से संकल्पित हो।

इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ध्वजारोहण उत्सव के क्षण को अद्वितीय व अलौकिक और इसे भारतीय सभ्यता की पुनर्जागरण की ध्वजा कहना स्वाभाविक था। मोहन भागवत के अनुसार यह एक ऐतिहासिक व पूर्णत्व का क्षण, कृतार्थता का तथा संकल्प की पुनरावृत्ति का दिवस था, जिसे हमारे पूर्वजों ने हमें दिया है। दृश्य को याद करिए। ध्वजारोहण के समय सामने की कतार में साधु-संत भावुकता में अपने आंसू पोंछते दिखेंगे। श्रीराम मंदिर के मुख्य शिखर पर केसरिया ध्वज लहराने के साथ अगर जयश्री राम का उद्घोष था तो दूसरी ओर भाव विह्वलता के दृश्य भी। महसूस कर सकते हों तो उसमें अद्भूत आध्यात्मिक ऊर्जा और उमंग साफ दिखाई दे जाएगा। 5 अगस्त,2020 को भूमि पूजन से लेकर अभी तक की प्रक्रिया के लिए अत्यंत सूक्ष्मता से अध्ययन व शोध हुए और फिर साधकों - विद्वानों ने मिलकर इसे संपूर्ण विश्व के लिए अद्भुत स्थान में विकसित किया है। कोरोना काल में हजारों श्रमिकों की अथक मेहनत के बाद श्रीराम मंदिर का पारंपरिक नागर शैली में निर्माण पूरा हुआ। इसके साथ सप्तऋषि मंदिर बने जिनमें निषाद राज और शबरी से लेकर भगवान वाल्मीकि आदि के मंदिरों का निर्माण और प्राण प्रतिष्ठा भी पूर्ण शास्त्रीय परंपरा से हुई। 22 जनवरी, 2024 को भगवान श्रीराम बालक राम के रूप में स्थापित किए गए थे और 5 जून, 2025 को दूसरी प्राण प्रतिष्ठा में भगवान राम राजा के रूप में स्थापित किए गए। इसके बाद अंतिम कार्य ध्वजा स्थापित करने का था।

सनातन परंपरा में शिखर पर लहराते ध्वज को मंदिर का रक्षक, ऊर्जा का वाहक और पूर्णता तथा ईश्वर की उपस्थिति का प्रतीक माना जाता है। ध्वजा से ही मंदिर को पूर्णता प्राप्त होती है। कौन-सा निशान रामलला के धाम की पवित्रता और युगों तक कायम रहने वाली सनातन परंपरा का प्रतिनिधित्व करेगा इसके चयन के लिए अनेक ग्रंथों को खंगाला गया। रामचरितमानस, भारत की सभी भाषाओं के रामायण देखे गये। विश्वकर्मा वास्तु शास्त्र के अध्याय 42 में ध्वजाओं के लक्षणों का विस्तृत वर्णन है। महाभारत, ऋग्वेद, विष्णुधर्मोत्तर पुराण में ध्वज का वर्णन है। इसमें भगवान विष्णु के ध्वज का रंग पीला और सुनहला बताया गया है। जो इनके अवतार होंगे उनके ध्वज का रंग केसरिया और पीतांबरी होगा। सूर्यवंशी होने के कारण सूर्य का निशान अंकित है। सूर्य जीवंतता और ऊर्जा का भी प्रतीक होता है। ओम ब्रह्मांड का द्योतक है, इसलिए ओम का निशान अंकित है। रघुकुल का राजकीय निशान होने के कारण कोविदार वृक्ष को अंकित किया गया है। हरिवंश पुराण में उल्लेख है कि महर्षि कश्यप ने पारिजात के पौधे में मंदार के गुण मिलाकर इसे तैयार किया था। वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के अनुसार चित्रकूट में वनवास के दौरान भगवान राम ने लक्ष्मण को ध्वजों से विभूषित अश्व और रथों से आती हुई सेना की सूचना दी और इसके बारे में पता लगाने को कहा। इसे देखकर लक्ष्मण ने कहा कि 'यथा तु खलु दुर्भद्धिर्भरतः स्वयमागतः। स एष हि महा कायः कोविदार ध्वजो रथे।' अर्थात् 'निश्चय ही दुष्ट दुर्बुद्धि भरत स्वयं सेना लेकर आया है। यह कोविदार युक्त विशाल ध्वज उसी के रथ पर फहरा रहा है।' इसी प्रसंग से स्पष्ट हुआ कि कोविदार वृक्ष युक्त ध्वज अयोध्या की पहचान और प्राचीन धरोहर रही है। प्राण प्रतिष्ठा के समय ही राम मंदिर परिसर में कोविदार वृक्ष लगाए गए हैं, जो इस समय लगभग आठ से 10 फुट के हो चुके हैं।

इतनी सूक्ष्मता से एक-एक पहलू का ध्यान रखने की सोच और इसके पीछे के दर्शन को विरोधी समझ ही नहीं सकते। अगर प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि अयोध्या की भूमि आदर्श आचरण का स्वरूप है और राम आदर्श एवं अनुशासन तथा जीवन के सर्वोच्च चरित्र के प्रतीक जो हमें तभी प्रेरित करेंगे जब हम अपने भीतर के राम को जगाएं। मेकाले शिक्षा प्रणाली की गुलाम मानसिकता से मुक्ति के लिए 10 वर्षों का लक्ष्य देने के लिए निश्चय ही यह उपयुक्त जगह और समय था। अयोध्या व राम - सीता को काल्पनिक बनाने की सोच इसी गुलाम मानसिकता से निकली थी। भारत को अपनी विपुल आध्यात्मिक ऊर्जा, सभ्यता और संस्कृति की शक्ति से विश्व के लिए नेतृत्वकारी आदर्श महाशक्ति के रूप में खड़ा करना है तो प्रेरणा यही से मिलेगी। प्रधानमंत्री ने इसके लिए रामायण में रावण से संग्राम के समय भगवान श्रीराम के कथन का उल्लेख करते हुए कहा कि विकसित भारत की यात्रा को गति देने के लिए हमें एक ऐसे रथ की आवश्यकता है जिसके पहिये वीरता और धैर्य हों, जिसका ध्वज सत्य और परम आचरण हो, जिसके घोड़े शक्ति, विवेक, संयम और परोपकार हों, और जिसकी लगाम क्षमा, करुणा और समता हों।

इसे निश्चय ही उस यज्ञ की आहुति कहनी होगी जिसकी अग्नि बाबर द्वारा मंदिर विध्वंस के साथ ही 500 वर्षों तक लोगों के हृदय में प्रचलित रही और यह संघर्ष अनवरत चलता रहा। डॉ भागवत ने कहा कि वृक्ष स्वयं धूप में खड़े रहकर सबको छाया देते हैं, फल स्वयं उगाते हैं और दूसरों को बांट देते हैं। 'वृक्षाः सत्पुरुषाः इव' अर्थात वृक्ष सत्पुरुषों के समान हैं। उन्होंने कहा कि यदि ऐसा जीवन जीना है तो चाहे कितनी प्रतिकूलता हो, साधनहीनता हो, दुनिया स्वार्थ में बहती हो फिर भी हमारा संकल्प है कि हमें धर्म के पथ पर चलना है। हमारे संकल्प का प्रतीक हम पूरा कर चुके हैं। धर्म, ज्ञान, छाया तथा सुफल संपूर्ण दुनिया में बांटने वाला भारतवर्ष खड़ा करने का काम शुरू हो गया है। इस प्रतीक को ध्यान में रखते हुए सभी विपरीत परिस्थितियों में हमें एकजुट होकर सतत कार्य करना होगा। उनकी कुछ पंक्तियां देखिए, 'एतद्देशप्रसूतस्य सकाशादग्रजन्मनः' अर्थात् इस देश में जन्मे अग्रजन्मा ऐसा जीवन जिएं कि दुनिया उनसे प्रेरणा लें,। 'स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन् पृथिव्यां सर्वमानवाः' यानी पृथ्वी के समस्त मानव भारतवासियों के चरित्र से जीवन की विद्या सीखें। परम वैभव सम्पन्न, सबके लिए खुशी और शांति बांटने वाला तथा विकास का सुफल देने वाला भारतवर्ष हमें खड़ा करना है। यही विश्व की अपेक्षा और हमारा कर्तव्य भी है।

तो संघर्ष से लेकर मंदिर निर्माण, प्राण प्रतिष्ठा और ध्वजारोहण तक के पूरे पुरुषार्थ को देखें तो समझ में आता है कि हर भारतवासी के लिए यह मंदिर और उसके ऊपर लहराता हुआ धर्म ध्वज अपनी संस्कृति की व्यापकता एवं संघर्ष की प्रभाव प्रखरता की सतत प्रेरणा देता रहेगा। हम इससे प्रेरणा लेते हुए सामूहिक रूप से भारत के लक्ष्य का ध्यान रखते हुए काम करेंगे तो यह देश विश्व के लिए आदर्श और प्रेरणादाई देश बनेगा। यही भारत का मुख्य ध्येय है।

भू-सांस्कृतिक मानचित्र बन सकता है नया आधार

पर्यावरण

कुमार सिद्धार्थ
लेखक पर्यावरण सहित सामाजिक आयामों पर लेखन करते हैं।

भारत का भू-सांस्कृतिक मानचित्र (जियो कल्चर मैप) केवल एक नक्शा नहीं, बल्कि मिट्टी, जल, खेती, परंपराओं, समुदायों और सांस्कृतिक व्यवहारों की सामूहिक बुद्धिमत्ता का मानचित्र है। यह उस भारत का प्रतिरूप है, जिसकी बनावट केवल भौगोलिक सीमाओं से नहीं, बल्कि हजारों वर्षों से विकसित एक जीवंत सांस्कृतिक पारिस्थितिकी से होती है। जिस समय दुनिया जलवायु संकट, जैव-विविधता के क्षरण और असंतुलित शहरीकरण की मार झेल रही है, उस समय भारत का यह भू-सांस्कृतिक दृष्टिकोण विकास की नई दिशा का आधार बन सकता है।

दरअसल, आधुनिक विकास मॉडल ने प्रकृति और संस्कृति के बीच जन्मे उस संतुलन को लगातार पीछे धकेला, जो भारतीय जीवन-पद्धति की आत्मा था। बीते दो शताब्दियों में आर्थिक वृद्धि के नाम पर वह दृष्टि हावी हुई जिसने जल, भूमि और समुदायों को संसाधन भर मान लिया। परिणाम यह हुआ कि भारत की अर्थव्यवस्था में कभी 32 प्रतिशत तक योगदान देने वाला प्रकृति-संस्कृति का साझा योग आज घटकर मात्र 4 प्रतिशत तक पहुँच गया है। इस पृष्ठभूमि में भू-सांस्कृतिक मानचित्रण का विचार न केवल वैज्ञानिक महत्व रखता है, बल्कि भारत के भविष्य की दिशा तय करने वाला सांस्कृतिक दस्तावेज भी बन सकता है।

भू-सांस्कृतिक मानचित्र की अवधारणा यह स्वीकार करती है कि भारत को सिर्फ 15 एग्रो-क्लाइमेटिक ज़ोन में बाँटकर नहीं समझा जा सकता। देश की मिट्टी, नमी, स्थलरूप, ऋतु-चक्र, कृषि-पद्धति, बोली-भाषाएँ, लोक-ज्ञान और सामुदायिक ढाँचे इतनी विविधता लिए हुए हैं कि वास्तविकता में यहाँ 86 से अधिक भू-सांस्कृतिक क्षेत्र मौजूद हैं। इन क्षेत्रों की पहचान सात प्रमुख मानकों के आधार पर की जाती है मिट्टी का प्रकार, जल-उपलब्धता, खेती, प्राकृतिक वनस्पतियाँ, पारंपरिक पेशे, सांस्कृतिक व्यवहार और सामुदायिक जल-प्रबंधन। इन सभी तत्वों के संगम से बनने वाले प्रत्येक क्षेत्र का चरित्र विशिष्ट होता है और वही इसे भू-सांस्कृतिक इकाई बनाता है।

इस दृष्टिकोण के उभार के पीछे जल-संरक्षण और नदी-पुनर्जीवन का बड़ा अनुभव भी है। राजस्थान के अलवर में तीन दशक से अधिक समय से जल-कार्य कर रहे तरुण भारत संघ ने पिछले दस वर्षों में 23 नदियों को पुनर्जीवित किया है। इन प्रयासों से यह अनुभव उभरकर आया कि पानी, मिट्टी और संस्कृति एक-दूसरे के पूरक हैं। जहाँ समुदाय अपनी पारंपरिक जल-व्यवस्थाओं के साथ सक्रिय रहता है, वहाँ भूमि की नमी, खेती की उत्पादकता, जैव-विविधता और सामाजिक सद्भाव–सभी में सुधार होता है। यही अनुभव भू-सांस्कृतिक मानचित्रण की वैज्ञानिक आधार-भूमि बनकर उभरा है।

इस अवधारणा की चर्चा हाल ही में नई दिल्ली स्थित इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी में आयोजित एक राष्ट्रीय कार्यशाला में हुई, जहाँ देशभर के वैज्ञानिकों, शिक्षाविदों, अर्थशास्त्रियों, डिज़ाइन विशेषज्ञों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इसे भारत के भविष्य की दिशा के रूप में रेखांकित किया।

विकास बनाम पुनर्जनन के संदर्भ में नये नजरिये को विकसित करने के लिए जल चेतना वाहक एवं जानकार डॉ. राजेंद्र सिंह ने भू-सांस्कृतिक मानचित्र की संकल्पना का एक खाका सामने रखा, जो विकास की पुरानी दृष्टि से बाहर आकर प्रकृति और संस्कृति के पुनर्जनन को केंद्र में होने की पैरवी करता है। ये आत्मनिर्भर भारत का मूल मार्ग होगा। समाज-जीवन में आनंद की प्राप्ति के लिए एक बार फिर अपनी प्रकृति और संस्कृति के योग की ओर देखने की जरूरत है। इस समन्वय को देख, समझकर जब भारत के पुनर्जनन की रीति-नीति और भू-सांस्कृतिक मानचित्र पर काम किया जाएगा, तो देश फिर से अपनी समृद्धि की राह पकड़ेगा। ये समृद्धि की राह ही सनातन होगी।

भू-सांस्कृतिक मानचित्र केवल शोध का विषय नहीं, बल्कि समुदायों पर आधारित विकास का व्यवहारिक ढाँचा है। दिल्ली विश्वविद्यालय की प्रोफेसर मधुलिका बैनर्जी बताती है कि शिक्षा व्यवस्था ने लोक-ज्ञान को उपेक्षित किया है, जबकि भारतीय समाज प्रकृति और संस्कृति के सह-अस्तित्व पर टिका है। एनसीईआरटी के विशेषज्ञों ने भी इस बात को स्वीकार किया कि स्थानीय भू-सांस्कृतिक अध्ययन को पाठ्यक्रम में शामिल किए बिना शिक्षा को वास्तविक जीवन से नहीं जोड़ा जा सकता।

पर्यावरणीय अर्थशास्त्री विजय परांजपे का मानना है कि भारत के कई क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ संस्कृति और पारिस्थितिकी के पारंपरिक तालमेल को फिर से समझने की आवश्यकता है। हमें भू-सांस्कृतिक दृष्टि के आर्थिक पक्ष को को भी देखने की जरूरत होगी। भारत के कई क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ संस्कृति और पारिस्थितिकी के पारंपरिक तालमेल को फिर से समझने की आवश्यकता है। लद्दाख का उदाहरण है, जहाँ दो अलग-अलग सांस्कृतिक समुदाय होने के बावजूद पारिस्थितिकी-आधारित जीवन-शैली सामाजिक समरसता का आधारित है। महाराष्ट्र के कोकण और मराठवाड़ा में भी इसी तरह की पारंपरिक जल-संस्कृतियाँ मौजूद हैं, जिन्हें भू-सांस्कृतिक दृष्टि से देखने पर कई नए पाठ खुलते हैं।

इस अवधारणा को दृष्टिगत रखते हुए अहमदाबाद के एक डिजाइन संस्थान के छात्रों ने देश के विभिन्न क्षेत्रों के भू-सांस्कृतिक मानचित्र पर प्रारंभिक स्तर पर कार्य किए है। इन मानचित्रों में स्थानीय मिट्टी के रंग से लेकर वर्षा-चक्र, लोक-गीतों, खाद्यान्न, नदी-प्रणालियों और पारंपरिक पेशों को दर्शाया गया। ये डिजाइनें बताती है कि भू-सांस्कृतिक मानचित्रण युवाओं के लिए एक प्रयोगशील और रचनात्मक अभ्यास के रूप में उभर सकता है, जो उन्हें अपने परिवेश और जड़ों से गहरे जोड़ता है।

दरअसल, भू-सांस्कृतिक मानचित्र भारत को विकास के उस मॉडल से बाहर निकालने का मार्ग सुझाता है जो केवल संरचनात्मक विस्तार और संसाधनों की खपत को विकास मानता रहा है। मानचित्र बताता है कि वास्तविक विकास तब होगा जब भूमि, जल, जंगल, कृषि और समुदाय–सभी आपसी तालमेल में पुनर्जीवित हों। यही दृष्टि पुनर्जनन आधारित विकास का आधार है, जो न केवल पर्यावरणीय संतुलन बल्कि सामाजिक और आर्थिक स्थिरता भी प्रदान कर सकती है।

नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति और RIS के महानिदेशक डॉ. सचिन चतुर्वेदी ने वैश्विक संदर्भों के नजरिये से बात रखी कि विश्व समुदाय अभी तक केवल 12 प्रतिशत सतत विकास लक्ष्यों को ही पूरा कर पाया है। ऐसे समय में स्थानीय सांस्कृतिक क्लस्टर और पारंपरिक इको-प्रक्रियाएं नए वैश्विक विकास-मॉडल बनेंगे। स्थानीय भू-सांस्कृतिक दृष्टि ही विश्व के सामने एक व्यावहारिक, समुदाय-आधारित और आत्मनिर्भर मॉडल प्रस्तुत कर सकती है।

वास्तव में भू-सांस्कृतिक मानचित्र भारत की उस सामूहिक स्मृति को जगाने का प्रयास है जिसे विकास की अंधी दौड़ में कहीं पीछे छोड़ दिया गया। ये मानचित्र हमें याद दिलाते है कि भारत की सभ्यता का मूल उसकी विविधता में नहीं, बल्कि विविधताओं के मधुर सह-अस्तित्व में है। जब भारत जल, भूमि, नदियों, खेती और संस्कृति के अपने प्राचीन योग को फिर से समझेगा, तभी पुनर्जनन आधारित विकास की राह स्थायी रूप से खुलेगी। भू-सांस्कृतिक मानचित्र इसी समझ का प्रस्ताव है, जो भविष्य के भारत को केवल विकसित नहीं, बल्कि पुनर्जीवित करने की क्षमता रखता है। ये भारत का भू-सांस्कृतिक मानचित्र नीति निर्माताओं, योजनाकारों, ब्यूरोक्रेट्स, आमजन को ऐसे मॉडल प्रदान कर सकता है, जिनमें स्थानीय जरूरतें, विविधता का सम्मान, जल-मिट्टी-संस्कृति-अर्थव्यवस्था का संतुलन स्पष्ट रूप से समझा जा सकेगा।

यादगार बनें सुहानी सर्दियां

अनुभव

सीमा देवेन्द्र
लेखक साहित्यकार हैं।

ये सर्द मौसम ही है के हमें जीने नहीं देता, जबकि ये जानता है के हम कितने शौक़ीन हैं जीने के! सर्दियों में खिली धूप का कोमल स्पर्श, पिघलती ठंड का एहसास, गर्म चाय के कप से उठता धुआँ। ये किसी कवि की कविता सा लग रहा होगा पढ़ने में लेकिन वास्तविकता का अनुभव रोमांच से भर देता है। सर्द शामों का गुजरना और सर्द रातों में अलाव का जलना यही तो मौसम की वास्तविकता से रूबरू करवाता है। उम्र के पड़ाव और सुलगते अलाव की अपनी अलग चाहतें होती हैं।

चाहकर भी गर्म सुरक्षा से बाहर नहीं निकल सकते। कहीं धूप मिल जाए तो ठीक है, ना भी मिले तो देख लें वो सर्द नज़ारें, जो देखे थे कभी साथ मिलकर।

सीनियर सिटिजन के लिए ये मौसम सिर्फ यादों में ही रहता है। हां, चुस्ती फुर्ती वाला ये मौसम ऊर्जा से भरपूर होता है। कड़कड़ाती सर्दी, ठिठुरन भी रोजमर्रा के काम को अंजाम तक पहुंचा ही देती है। बल्कि दुगुने उत्साह से सब लगे रहते हैं अपने अपने कार्य क्षेत्र में।

ये मौसम सेहत निर्माण का भी होता है। इसमें खूब पौष्टिक चीजें खायी जा सकती हैं। इस मौसम में स्वाद होता है, तमाम तरह के व्यंजन, जलेबी से लेकर मूंग, बादाम, खसखस, गाजर का हलवा, कचौड़ी-पकौड़ी, गराड़ू, ड्रायफ्रूट्स तिल जिसमें दिल होता है और भी बहुत कुछ। लेकिन इसके साथ व्यायाम भी जरूरी है। सुबह शाम टहलें। प्रकृति का आनन्द लें। धूप का मजा लें। सूरज तो खुद ही लालायित रहता है बातें करने के लिए वर्ना सूरज से कोई आंखें मिला सकता है भला?

झुकता है आस्मां ज़मीं के लिए
नर्म सर्दी में एक छुअन के लिए!

ऐसे ही कहानी बना जाती है रूहानी सर्दियां। ठंडी हवाएं, चारों ओर गुनगुनी धूप, हरियाली, फूल, पंछी और पूरी कायनात का साथ होना कहीं ना कहीं तन मन को सुकून दे जाता है। जहां अति बरसात अति ग्रीष्म सामान्य जीवन को बेहाल कर देती है वहीं ये सर्दी का मौसम काफी राहत दे जाता है।

मौज मस्ती, पिकनिक, पार्टी इसी मौसम में आयोजित होती है.। संस्थाओं और स्कूलों के वार्षिक आयोजन भी इसी समय होते हैं। पूरे वर्ष भर की उर्जा और आत्मविश्वास का अनूठा संगम इस मौसम की फिज़ाओं में देखा जा सकता है। शारीरिक दृष्टि से भी देखें तो इस मौसम में ज्यादा कार्य करने की क्षमता और उत्साह देखा गया है।

सर्दियों में लेखक और कवि भी अपने आपको खूब उर्जावान महसूस करते हैं। ये हवाओं को छेड़ देते फिर हवाएं इन्हें नहीं बख्शती। तो ज़रा सम्भलकर रहिए ज़नाब मौसम सर्द तो है बेरहम भी और बेदर्द भी।

हाँ, इसमें चाँद और चाँदनी के भाव थोड़े गिरे से रहते हैं। लेकिन एक लेखक और कवि में ही ये ताक़त होती है कि वो कब किसके भाव बढ़ा दे और कब किसको धड़ाम कर दे। कलम के तेवर तो देखते ही बनते हैं, सावन, बसंत क्या सर्दियों में भी। ठिठुरती कलम भी चुप नही रहती। यही तो है मौसम का कमाल।

ख़ैर! आप तो सर्दियों का आनन्द लीजिए। घर में बच्चे बूढ़े सभी का ख़ास ख़याल रखिए और साथ में अपना तो रखिए ही क्योंकि ये मौसम भी बहुत मुश्किल से अपने होते हैं। इनकी आदत तो सबको पता है कि ये कब बदल जाए, इनका कोई भरोसा नहीं। ये सबूत ना भी छोड़े तब भी सरकार जानकार पत्रकार, रचनाकार सबूत जुटा ही लेते हैं। और जिनको यादें सहेजने की आदत होती है वो इन सबूतों को सहेज ही लेते हैं और दिल से लगाकर रखते हैं। घबराते वो हैं जो सबूत कई जगह छोड़ आते हैं। इस मामले में मौसम भी शातिर है 'भरोसा दो और भरोसा लो।'

जागरूक बनिए, जिम्मेदार बनिए, पर्यावरण सहेजिए। विकास के नाम पर तमाम पेड़ काटे जा रहे हैं जिसका रोष मौसम में होता है जो अतिवृष्टि के रूप हमारे लिए हानिकारक प्रभाव छोड़ता है। मौसम में बहकना आम बात है लेकिन इसी बहाने कवि, लेखकों और व्यंग्यकारों की कलम से कुछ अच्छा और प्रभावी सृजन हो जाता है।

मौसम भले ही सर्द हो लेकिन रिश्तो में गर्माहट हो, तो मौसम अच्छे हैं। रिश्तों का कोई मौसम नही होता लेकिन मौसम कभी कभी यादगार रिश्ते दे जाते हैं। शायद मौसम भी इसीलिए बने हैं। सुहानी सर्दियां मुबारक हों।

तिरी नज़दीकियां कुछ वो लिखा गई
कि जितना मैंने तुझे पढ़ा भी नहीं!

स्वामी, सुबह सवेरे मीडिया एल.एल.पी. के लिए उमेश त्रिवेदी द्वारा अग्निबाण पब्लिकेशन, 121, देवी अहिल्या मार्ग, इंदौर, म.प्र. से मुद्रित एवं 662, साई कृपा कॉलोनी, बॉम्बे हॉस्पिटल के सामने, इंदौर से प्रकाशित।

प्रधान संपादक
उमेश त्रिवेदी
कार्यकारी प्रधान संपादक
अजय बोकिल
संपादक (मध्यप्रदेश)
विनोद तिवारी
स्थानीय संपादक
हेमंत पाल
प्रबंध संपादक
रमेश रंजन त्रिपाठी

(सभी विवादों का न्याय क्षेत्र इंदौर रहेगा)
RNI No. MPHIN/ 2015/ 66040,
Mobile No.: 09893032101
Email- subahsaverenews@gmail.com

'सुबह सवेरे' में प्रकाशित विचार लेखकों के निजी मत हैं। इनसे समाचार पत्र का सहमत होना आवश्यक नहीं है।

डरा हुआ आदमी

व्यंग्य

जवाहर चौधरी
लेखक व्यंग्यकार हैं।

डरा हुआ आदमी लोकतंत्र का सबसे मजबूत खंबा होता है। जैसे सर्कस के तंबू में बीच का खंबा होता है, बस वैसे ही। बाकी के सारे खंभे भी उसे पर निर्भर होते हैं। बीच का खंबा अगर जरा भी हिला तो समझो लोकतंत्र को खतरा हुआ। कुछ लोग इन्हें डरा हुआ आदमी कहते हैं और जो जानते हैं वे जिम्मेदार आदमी मानते हैं। डरा हुआ आदमी गुप्त मतदान करते हुए भी डरता है कि भगवान सब देख रहे हैं और मौका पड़ा तो महाआरती के बाद सरकार को सब बता देंगे। हाल के कुछ महत्वपूर्ण बयानों से देश को पता चला है कि आजादी ज्यादा पुरानी नहीं है और डरा हुआ आदमी भी। डरा हुआ आदमी सब समझता है बल्कि दूसरों से कुछ ज्यादा ही समझता है। वो टीवी देखते हुए वह भी देख लेता है जो दिखाया नहीं जा रहा है। अखबार पढ़ते हुए वह शब्द नहीं पढ़ता शब्दों के पीछे का पढ़ता है। चुनावी दल जब वादे करते हैं तो वह उन पर यकीन नहीं करता है, लेकिन यकीन नहीं करने के खतरे जानता है इसलिए फौरन कर लेता है। मीडिया जब विकास की जिंदा खबरें सुनता है तो इसके अंदर कोई 'ओम शांति - ओम शांति' बोलने लगता है। गुस्सा आने पर मुस्कुराने का हुनर उसने सीखा था, अब सुबह से शाम तक मुस्कुराता है।

वह जिनके बीच उठता बैठता है उन्हें भी संदेह से देखता है। उसे विश्वास बना रहता है कि इन सारे लोगों की पहुँच सरकार तक हो सकती है। सरकार के पास वर्दी और बिना वर्दी वाली पुलिस होती है और पुलिस के पास डंडा। और सब जानते हैं कि पुलिस जनता की सेवक है। रात में वह सपना देखता है और चीखना चाहता है। लेकिन उसकी इतनी आवाज भी नहीं निकलती है कि बगल में सोया हुआ उठ जाए। उसको लगता है कि यदि उसने सिस्टम के खिलाफ कुछ भी बोला तो वह अभिमन्यु की तरह घिर जाएगा। उसे हर समय लगता है कि वह महाभारत के युद्ध मैदान में असुरक्षित खड़ा हुआ है। डरे हुए आदमी को अपने भी अपने से नहीं लगते हैं। वह मानता है की एक डर ही है जो उसकी सभी खतरों से रक्षा करता है। डर ही उसका जीवन है और डर नहीं होता तो वह कभी का फोटो हो गया होता।

डरा हुआ आदमी सोशल मीडिया पर किसी भी पोस्ट को लाइक करने से पहले बार-बार चेक करता है कि लाइक बटन का रंग कहीं 'विपक्ष' से मेल तो नहीं खाता। वह सिर्फ हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं, बहुत सुन्दर जैसे कमेंट करता है, लेकिन हमेशा यह ध्यान रखता है कि कमेंट इतना छोटा हो कि उस पर कोई 'काउंटर कमेंट' न कर पाए। प्रोफाइल पिक्चर पर उसने खुद की नहीं, एक गैर राजनीतिक फूल की तस्वीर लगा रखी है। जब उसका बच्चा स्कूल में कोई प्रश्न पूछता है, तो वह उसे धीरे से डांटता है, 'बेटा, कुछ पूछना, ज्यादा सोचना गंदी बात होती है। टीचर जो भी बता दे वही सच है। प्रश्न नहीं करोगे तो सौ साल जियोगे, बस उत्तर याद रखो।'

कई बार जब डरा हुआ आदमी खाली और अकेला होता है तो विचार आते जाते रहते हैं। कभी कभी सोचता है कि देश बड़ा या जीवन! अंदर से पहली आवाज निकलती है - देश बड़ा। लेकिन तुरंत ही वह भूल सुधार भी करता है। अंदर से कोई फटकारता है कि अबे जानता नहीं क्या, 'जान है तो जहान है'। जान बचे तो समझो लाखों पाये। इनदिनों घर से बाहर निकलो तो लगता है कि जान शरीर से आगे आगे चल रही है। शरीर अगर कदम से कदम नहीं मिला पाया तो समझो जान ये गई वो गई। दूसरे दिन खबर छपेगी कि हार्ट अटैक से एक और गया। अभी जो कनिया पहलवान हैं ना, अपने चक्कू कट्टा वाले, वह भगवान तो नहीं हैं पर भगवान से कम भी नहीं हैं। जब देखो तब काले भैंसे पर सवार दिखाई देते हैं। सामने पड़ जाएं तो कमर अपने आप झुक कर दोहरा जाती है। और आदमी के मुँह नाक से अनुलोम विलोम और कपालभाँति निकलने लगती है। ऐसी सिचुएशन में कोई सीन तान कर खड़ा हो जाए तो अंजाम क्या होगा! आप समझ सकते हैं। लेकिन डॉक्टर एक बात अच्छी भी कहते हैं कि डरे हुए आदमी को कब्ज की शिकायत नहीं रहती है। कब्ज न हो तो शरीर अनेक रोगों से बचा रहता है। इसलिए हर आदमी को दिमाग और पेट साफ रखना चाहिए।

अंबेडकर परिनिर्वाण दिवस

चित्रा माली

सहायक प्रोफेसर गांधी एवं शांति अध्ययन विभाग महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विवि क्षेत्रीय,केंद्र कोलकाता।

बाबा साहब : एक प्रतीक और कई मायने

बहरहाल इस फिल्म की समीक्षा करना मेरा मकसद नहीं है,सोशल मीडिया पर यह पहले से उपलब्ध है। इस फिल्म में डॉ. बी. आर. अंबेडकर की तस्वीर को प्रतीकात्मक तौर पर दिखाया गया है जो बिना कुछ कहे बहुत कुछ बयान कर रही है। महात्मा फुले की तरह ही डॉ. अंबेडकर का मानना भी था कि ब्रिटिश सरकार सामाजिक और धार्मिक रूप से तटस्थ है, इसलिए सामाजिक संघर्ष में उसके प्रभाव का इस्तेमाल निचली जातियों के पक्ष में किया जा सकता है।

21 नवंबर 2025 में ओटीटी प्लेटफार्म नेटफ्लिक्स पर नीरज घायवान निर्देशित फिल्म 'होमबाउंड' रिलीज हुई है। इसके पूर्व यह सिनेमा हाल में 26 सितंबर 2025 को रिलीज हो चुकी थी। ओटीटी प्लेटफार्म पर आने के बाद अभी हाल में यह खासी चर्चा में है। फिल्म 'होमबाउंड' ऑस्कर 2026 के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि है। इस फिल्म के पूर्व अजीब दास्तां,मसान,जूस, सेक्रेड गेम्स सीरीज के कुछ एपिसोड्स का सह-निर्देशन और मेड इन हेवन सीरीज़ के कुछ एपिसोड्स का निर्देशन नीरज के द्वारा किया गया हैं। बहरहाल इस फिल्म की समीक्षा करना मेरा मकसद नहीं है, सोशल मीडिया पर यह पहले से उपलब्ध है। इस फिल्म में डॉ.बी.आर.अंबेडकर की तस्वीर को प्रतीकात्मक तौर पर दिखाया गया है जो बिना कुछ कहे बहुत कुछ बयान कर रही है। महात्मा फुले की तरह ही डॉ.अंबेडकर का मानना भी था कि ब्रिटिश सरकार सामाजिक और धार्मिक रूप से तटस्थ है, इसलिए सामाजिक संघर्ष में उसके प्रभाव का इस्तेमाल निचली जातियों के पक्ष में किया जा सकता है। दमित जातियों के लिए अलग से राजनीतिक दायरे को विकसित करने के लिए डॉ.अंबेडकर ने कई प्रयास किए। 1919 में उन्होंने साउथबरो कमीशन के सामने अछूतों के पृथक मतदाता मंडलों की मांग रखी और यही से आधुनिक भारतीय राजनीति में दमित जातियों के हितों को सुरक्षित रखने के लिए आंदोलन शुरू हुए जो आज भी किसी न किसी रूप में चल रहे है। डॉ.अंबेडकर ने 1918 और 1920 में उत्पीड़ित वर्गों के सम्मेलनों में दमितों के तत्कालीन नेतृत्व (जो गैर-दलित था) को खारिज करते हुए दावा किया कि दमितों की बागडोर उन्हीं के बीच से निकले व्यक्तियों के हाथों में होनी चाहिए। दमित जातियों के बीच डॉ.अंबेडकर की लोकप्रियता बहुत तेजी से बड़ी जिसके फलस्वरूप उन्हें 1932 में गोलमेज सम्मेलन में आमंत्रित किया गया था। यहां पर डॉ. अंबेडकर ने दमित जातियों के लिए पृथक मतदाता मंडल की मांग रखी। जिसे ब्रिटिश सरकार ने मान लिया था। इसका विरोध गांधी जी ने किया था क्योंकि वे हिंदू धर्म में विभाजन नहीं चाहते थे। इसी मुद्दे पर गांधी जी और डॉ.अंबेडकर के बीच पूना पैक्ट हुआ था। डॉ.अंबेडकर ने स्वतंत्र भारत में संविधान निर्माण और पहले कानून मंत्री के तौर पर भारतीय राज्य को सामाजिक और धार्मिक रूप से तटस्थ बनाने का काम किया। भारतीय संविधान में दमित/अछूत जातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है जो भारतीय समाज में खासकर हिंदू समाज में अछूत जातियों को यातनाओं और भेदभाव के विरुद्ध सम्मान और गरिमामय जीवन के लिए आवश्यक है और साथ ही यह गांधी जी के विचारों का सम्मान भी है। गांधी जी ने कहा था कि 'सच्ची स्वतंत्रता या स्वराज तभी आ पाएगा जब हिंदू समाज इस कलंक से मुक्ति हासिल कर लेगा। संविधान में विधायिका और सरकारी नौकरियों में सबसे निचली जातियों के लिए सीटों का आरक्षण सुनिश्चित किया गया है। कानून बनाकर हिंदू मंदिरों में सभी जातियों के प्रवेश को भी सुनिश्चित किया गया और समाज से छुआछूत मिटाने की बात कही गई। इन सभी प्रावधानों का व्यापक तौर पर स्वागत किया गया। मद्रास के मुनिस्वामी पिल्लई ने इस पर टिप्पणी की कि 'जब तक हमारे देश में छुआछूत की भावना जिंदा है, हमारे देश का सही नाम कलंक या काला धब्बा होना चाहिए.... हमारे महान संतों ने इसे दूर करने का भरसक प्रयास किया था लेकिन इस महान सभा को और भारत के नए संविधान को यह श्रेय जाता है कि हम जोर देकर कह सकें कि अब से हिंदुस्तान में छुआछूत नहीं रहेगी। एच.जे. खांडेकर ने जोरदार ढंग से सरकारी नौकरियों में दमित जातियों के लिए आरक्षण की पैरवी की। उन्होंने आईएएस परीक्षा के परिणामों का जिक्र किया था जिसमें कई हरिजन उम्मीदवारों का साक्षात्कार हुआ था लेकिन उनमें से किसी का भी चयन नहीं किया गया। कमोबेश यही स्थिति आज भी देखी जा सकती है जिसमें इन वर्गों के उम्मीदवारों को एनएफएस कर दिया जाता है।'

'एनहिलेशन ऑफ़ कास्ट्स' में डॉ.अंबेडकर लिखते है कि अंतर्जातीय विवाहों को प्रोत्साहन देकर और अछूतों को पुरोहित बना कर हिंदू धर्म को उसकी बुराइयों से छुटकारा दिलाया जा सकता है। इसी क्रम में उन्होंने महाड़ सत्याग्रह और मंदिर प्रवेश की मुहिमों का आयोजन

किया। लेकिन इस प्रक्रिया में डॉ.अंबेडकर ने देखा कि संस्कृति के क्षेत्र में विभिन्न समुदाय स्वतंत्रता,भाईचारे और बराबरी के तीन अनिवार्य मूल्यों के आधार पर संवाद करने के लिए तैयार नहीं हैं। वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि संस्कृति अपने-आप में अधिकारों की दावेदारी में बाधक बन गई है और इसलिए राष्ट्रीय पैमाने पर किसी सांस्कृतिक समुदाय की स्थापना करने का मतलब होगा धार्मिक कट्टरता को सत्तारूढ़ हो जाने का मौका दे देना। डॉ. अंबेडकर का मानस बुद्धिवाद और सेकुलर तत्वों के घटकों से मिलकर बना था और परंपरा की उनकी समझ शास्त्रों की आलोचनात्मक जांच-पड़ताल करते हुए वैज्ञानिक दृष्टि विकसित करने के आधार पर बनी थी। आखिरकार वे जानना चाहते थे कि हिंदू धर्म की खामियां इतनी भीषण क्यों हैं और क्या वजह है जो उनके निवारण की नैतिक प्रेरणाओं को इतना दुर्बल कर देती है। 25 जनवरी 1949 को डॉ.बी.आर.अंबेडकर ने एक महत्वपूर्ण भाषण दिया जिसमें उन्होंने कहा कि प्राचीन भारत के लोग भी लोकतंत्र की कुछ प्रणालियों से जरूर वाकिफ़ थे। एक ऐसा भी वक्त था जब हिंदुस्तान गणराज्यों से अटा पड़ा था। उन्होंने विशेष रूप से बौद्ध धर्म का जिक्र किया और कहा कि बौद्धों ने अपने भिक्षु संघों में लोकतांत्रिक आदर्शों को बढ़ावा दिया था,जिसमें संसदीय कार्यवाहियों की तरह ही नियमों का पालन किया जाता था। वहां भी मतदान, प्रस्ताव,कटौती और चेतावनी जैसे संसदीय नियमों का इस्तेमाल होता था। डॉ. अंबेडकर ने सदन को आश्वस्त किया कि संघ का मतलब ये नहीं है कि राज्यों को कोई सार्थक शक्ति हासिल ही नहीं होगी। उन्होंने कहा कि ये बात गलतफहमी के तहत फैली है कि केंद्र के पास 'अत्यधिक शक्तियां हैं और राज्यों की हालत नगरपालिका जैसी हो गई है'।

संविधान ने विधायिका और कार्यपालिका की शक्तियों का बंटवारा कर दिया है। केंद्र और राज्य इस मामले में एक समान हैं। डॉ.अंबेडकर ने ड्राफ्टिंग कमेटी के अन्य सदस्यों,अपने सहयोगी कर्मचारियों और कांग्रेस पार्टी को भी धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि 'कांग्रेस पार्टी के अनुशासन की वजह से ही ड्राफ्टिंग कमेटी,संविधान सभा में संविधान बनाने का काम यह जानते हुए भी कर पाई कि हरेक धारा और हरेक संशोधन का क्या भविष्य होने वाला है'। इसी के साथ डॉ.अंबेडकर ने तीन चेतावनियां भी दी थी जिनमें से मैं एक का जिक्र कर रही हूं। उन्होंने भारतीयों से कहा कि वे महज 'राजनीतिक लोकतंत्र से संतुष्ट न हों'। हिंदुस्तान को विदेशी शासन से मुक्ति मिली है लेकिन अभी भी समाज असमानता और कठोर पदानुक्रम द्वारा शासित हो रहा था। इस तरह एक बार जब देश 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र बन गया है तो यह कई विरोधाभासों से पूर्ण जिंदगी में प्रवेश करने जा रहा था। हम राजनीति में तो समानता पाएंगे लेकिन सामाजिक और आर्थिक जीवन में असमानता से जूझते रहेंगे। राजनीति में हम एक व्यक्ति,एक मत और एक मूल्य के सिद्धांत को तो मानते रहेंगे लेकिन अपने सामाजिक और आर्थिक जीवन में हम अपने सामाजिक और आर्थिक ढांचे की वजह से एक व्यक्ति और एक मूल्य की भावना को अस्वीकार करते रहेंगे। आखिर कब तक हम इन विरोधाभासों के साथ जिंदगी जीते रहेंगे ? कब तक हम अपने सामाजिक और आर्थिक जीवन में समानता से इनकार करते रहेंगे? अगर हम लंबे समय तक ऐसा करने से इनकार करते रहे तो हम अपने राजनीतिक लोकतंत्र को संकट में डालने का काम करेंगे। डॉ. अंबेडकर की चेतावनी जो आने वाले भविष्य की चिंता थी वर्तमान में भी जस की तस बनी हुई है और इस फ़िल्म होमबाउंड में भी परिलक्षित होती है जिसमें में दमित और अल्पसंख्यक समुदाय के साथ सामाजिक और आर्थिक भेदभाव के साथ और भी कई समस्याओं को एक साथ देखा जा सकता है। अंत में डॉ. बी. आर. अंबेडकर का कथन जिसमें उन्होंने कहा था कि 'संवैधानिक नैतिकता एक स्वाभाविक भावना नहीं है। इसका क्रमिक विकास किया जाता है। हमें यह सोचना चाहिए कि हमारे लोगों को अभी यह सीखना है। हिंदुस्तान की ज़मीन पर लोकतंत्र अभी ऊपरी सतह पर है जो अपने आप में अलोकतांत्रिक बात है'।

डॉ. अंबेडकर महापरिनिर्वाण दिवस

डॉ. भूपेन्द्र कुमार सुल्लेरे

लेखक साहित्यकार हैं।

सामाजिक न्याय, संवैधानिक मूल्यों व राष्ट्रीय समरसता के शिल्पी

6 दिसंबर भारतीय इतिहास का एक गंभीर और प्रेरणादायी दिवस है। इसी दिन 1956 को डॉ. भीमराव रामजी अंबेडकर ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया–परंतु उनका जीवन, विचार और संघर्ष आज भी करोड़ों भारतीयों को प्रकाश-दीप की भाँति मार्ग दिखाते हैं।

'एजुकेशन, एजिटेशन, ऑर्गनाइजेशन' का उनका आह्वान आज भी सामाजिक चेतना का आधार है। डॉ. अंबेडकर का जीवन : संघर्ष से तपकर निकला तेजस्वी व्यक्तित्व डॉ. अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को अछूत अनुभव की पीड़ा झेलते एक परिवार में हुआ। सामाजिक भेदभाव, अपमान और तिरस्कार उनके जीवन में जन्मजात चुनौतियाँ बनीं; परंतु उन्होंने इन चुनौतियों को अपने संघर्ष का आधार बनाया और विश्व के सबसे शिक्षित समाज सुधारक, चिंतक और विधिवेत्ता के रूप में पहचान बनाई।

महत्वपूर्ण पड़ाव : कोलंबिया विश्वविद्यालय और लंदन स्कूल ऑफ़ इकॉनॉमिक्स से उच्च शिक्षा 'द प्रॉब्लम ऑफ रुइपी', 'ऐनिहिलेशन ऑफ कास्ट', 'स्टेट्स एंड माइनॉरिटीज' जैसे क्रांतिकारी ग्रंथ श्रमिक, महिला अधिकार, दलित अधिकार, आर्थिक न्याय और सामाजिक समानता पर अथक कार्य भारतीय संविधान के शिल्पकार : आधुनिक भारत की नींव रखने वाले महापुरुष डॉ. अंबेडकर को संविधान निर्माण समिति का अध्यक्ष बनाना भारतीय लोकतंत्र का ऐतिहासिक निर्णय था। उन्होंने एक ऐसे संविधान की रचना की, जो न केवल शासन की आधारशिला है, बल्कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक न्याय पहुँचाने का मार्ग भी है।

संविधान में उनका विशेष योगदान :

समता और स्वतंत्रता का मूल सिद्धांत अनुसूचित जाति, जनजाति तथा पिछड़े वर्गों के अधिकारों की सुरक्षा मौलिक अधिकार और विधिक सुरक्षा सामाजिक न्याय आधारित लोकतंत्र

आरक्षण व्यवस्था : शोषित-पीड़ित वर्ग को अवसर प्रदान करने का संवैधानिक प्रावधान समान नागरिक अधिकार और मौलिक कर्तव्यों की परिकल्पना वे कहते थे–

'मैं ऐसे संविधान का विरोध करूंगा जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय न दे सके।' अनुसूचित जाति एवं वंचित वर्गों के लिए डॉ. अंबेडकर का योगदान डॉ. अंबेडकर ने न केवल संवैधानिक अधिकार दिए, बल्कि सामाजिक परिवर्तन के कई निर्णायक कदम भी उठाए।

मुख्य योगदान -शिक्षा को सामाजिक मुक्ति का प्रमुख साधन बताया मंदिर प्रवेश, पीने के पानी, सार्वजनिक स्थानों के उपयोग पर समान अधिकार के लिए आंदोलन

अस्पृश्यता निवारण अधिनियम और सामाजिक सुधार उपाय जातिगत भेदभाव के उन्मूलन हेतु राष्ट्रीय विमर्श खड़ा करना महिला अधिकारों और हिंदू कोड बिल के माध्यम से परिवार में समान अधिकार उनका अंतिम लक्ष्य था–

'अंतिम व्यक्ति तक अवसर और सम्मान पहुँचाना।' डॉ. अंबेडकर के मूल्यों पर आधारित जीवन-दर्शन डॉ. अंबेडकर का जीवन कुछ मूलभूत मूल्यों पर आधारित था, जिन पर भारतीय समाज को आज भी चलना चाहिए।

मुख्य मूल्य: शिक्षा का महत्व : सामाजिक उठान का सर्वश्रेष्ठ साधन

स्वाभिमान और आत्मसम्मान: व्यक्ति को बराबरी का दर्जा

संवैधानिक राष्ट्रवाद: देश का विकास कानून और संस्थाओं के माध्यम से

तर्क और वैज्ञानिक दृष्टि: अंधविश्वास और रूढ़ियों के विरुद्ध

समानता और समरसता: जाति-मुक्त समाज की परिकल्पना

लोकतांत्रिक चेतना : संवाद, विमर्श और विचार की स्वतंत्रता भारत की सामाजिक समरसता के लिए डॉ. अंबेडकर का संदेश डॉ. अंबेडकर भारतीय समाज को विभाजन से निकालकर समरसता और समानता की ओर ले जाना चाहते थे।

उन्होंने स्पष्ट कहा था-

'जाति भारत के लिए एक शाप है। जब तक जाति का विनाश नहीं होगा, समरस समाज नहीं बन सकता।'

उनकी समरसता की अवधारणा में तीन मुख्य तत्व थे–

समान अवसर समान गरिमा समान व्यवहार वे सामाजिक एकता को भारतीय राष्ट्रवाद की आत्मा मानते थे। भारत की सभ्यतागत एकता और अंबेडकरी विचार डॉ. अंबेडकर भारत की एकता को सांस्कृतिक विविधता में निहित मानते थे। उनके अनुसार–

भारत एक साझी सांस्कृतिक चेतना का देश है परंपरा और आधुनिकता का संतुलन ही भारत की शक्ति है जाति-मुक्त समाज ही भारत के भविष्य का मार्ग है संविधान भारतीय एकता का सबसे बड़ा प्रतीक है महापरिनिर्वाण दिवस का महत्वः स्मृति और संकल्प का दिन 6 दिसंबर केवल स्मरण का दिन नहीं–यह सामाजिक न्याय, मानव गरिमा और संवैधानिक चेतना को पुनः स्थापित करने का दिवस है। यह दिन हमें पुनः याद दिलाता है कि–न्याय बिना समाज अधूरा है सम्मान बिना स्वतंत्रता अधूरी है संविधान बिना लोकतंत्र अधूरा है सद्भाव, समरसता और समानता से ही भारत मजबूत बनता है।

डॉ. अंबेडकर का संदेश–'भेदभाव रहित भारत ही हमारा लक्ष्य' डॉ. भीमराव अंबेडकर का जीवन स्वतंत्र भारत के सामाजिक पुनर्निर्माण की आधारशिला है। उनका दर्शन हमें बताता है कि–

शिक्षा से चेतना आती है चेतना से स्वाभिमान और स्वाभिमान से सामाजिक परिवर्तन

महापरिनिर्वाण दिवस पर हमें यह संकल्प लेना चाहिए कि–

'हम एक ऐसे भारत के निर्माण में योगदान देंगे, जहाँ बराबरी, न्याय और समरसता केवल शब्द नहीं, बल्कि जीवन की वास्तविकता बनें।'

अंबेडकर परिनिर्वाण दिवस

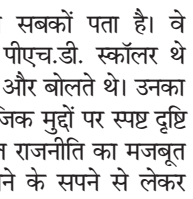

डॉ. ब्रह्मदीप अलूने

लेखक 'गांधी है तो भारत है' के लेखक हैं।

जीवन के संघर्ष में ढूंढिए, आत्महत्याओं में अंबेडकर कहीं नहीं है...

आंध्र प्रदेश निवासी आईपीएस अधिकारी पूरन कुमार ने हरियाणा में कई प्रमुखों स्थानों पर अपनी सेवाएं दी थी। वे अंबाला और रोहतक रेंज के इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस यानी आईजीपी रह चुके थे,साथ ही उन्होंने होम गार्ड्स,टेलीकॉम, डायल-112 इमरजेंसी रिस्पॉन्स प्रोजेक्ट जैसे महत्वपूर्ण विभागों का नेतृत्व किया। पूरन कुमार ने इस वर्ष अक्टूबर में खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों और हरियाणा के डीजीपी पर उत्पीड़न का आरोप लगाया। पूरन कुमार ने अपने दर्द को साझा करते हुए कहा की उन्हें सेवा में कई बार अपने वरिष्ठ अधिकारियों के उत्पीड़न और भेदभाव का सामना करना पड़ा। पूरन कुमार ऐसे अधिकारी माने जाते थे जो सरकारी वाहनों के दुरूपयोग,अवैध धार्मिक निर्माण, पदोन्नति व रैंक मान्यता में भेदभाव जैसे मसलों को उठाते थे। यदि उन्होंने आत्महत्या नहीं की होती,तो ये आवाज़ और मजबूत हो सकती थी। वे उन दलितों व अन्य कर्मचारियों के लिए प्रेरणा बन सकते थे, जो डर के चलते आवाज़ नहीं उठा पाते। अगर उन्होंने ज़िंदा रहते हुए लड़ाई जारी रखी होती,तो यह न केवल उनके लिए बल्कि करोड़ों कई लोगों के लिए एक मजबूत मिसाल बन सकती थी।

रोहित वेमुला का नाम हम सबकों पता है। वे हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के पीएच.डी. स्कॉलर थे और वंचित वर्ग के लिए लिखते और बोलते थे। उनका लेखन,संगठन क्षमता और सामाजिक मुद्दों पर स्पष्ट दृष्टि उन्हें विश्वविद्यालय की प्रगतिशील राजनीति का मजबूत चेहरा बनाती थी। वैज्ञानिक बनने के सपने से लेकर सामाजिक अन्याय के खिलाफ संघर्ष तक,रोहित ने शिक्षा और समानता को जीवन का केंद्र बनाया था। रोहित वेमुला ने भी आत्महत्या की थी। उनकी आत्महत्या के मूल कारण संस्थागत भेदभाव,प्रशासनिक उत्पीड़न और राजनीतिक दबाव से गहराई से जुड़े थे। विश्वविद्यालय ने उन्हें और उनके साथियों को कथित शिकायतों के आधार पर निलंबित कर दिया था,हॉस्टल से बेदखल किया गया और आर्थिक सहायता भी रोक दी गई। यह कार्रवाई राजनीतिक हस्तक्षेप और वैचारिक ध्रुवीकरण का परिणाम मानी गई। लगातार अपमान, अलगाव और भविष्य को लेकर अनिश्चितता ने उनके मानसिक स्वास्थ्य पर गंभीर असर डाला। अपने अंतिम पत्र में उन्होंने लिखा कि वे मनुष्य होने की आकांक्षा से भी वंचित महसूस कर रहे थे। रोहित की मृत्यु ने भारतीय विश्वविद्यालयों में व्याप्त जातिगत और वैचारिक भेदभाव की गहरी संरचनात्मक समस्या की ओर इशारा किया था।

मुथुकृष्णन, दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के प्रतिभाशाली शोधार्थी थे। वे तमिलनाडु के एक साधारण दलित परिवार से आए थे और सामाजिक न्याय,समानता और हाशिए पर पड़े समुदायों की समस्याओं पर गहरी संवेदनशीलता रखते थे। उनकी पहचान केवल एक छात्र के रूप में नहीं, बल्कि एक विचारशील लेखक,सामाजिक मुद्दों पर सक्रिय आवाज और विश्वविद्यालय परिसर में समानता के पक्षधर व्यक्तित्व के रूप में थी। उनके लेखन में सामाजिक विषमता,जातिगत दमन और अवसरों की असमानता की तीखी आलोचना साफ दिखाई देती थी। मार्च 2017 में उनकी संदिग्ध आत्महत्या ने पूरे देश में हलचल मचा दी। मुथुकृष्णन लगातार महसूस करते थे कि शिक्षा संस्थानों में जातिगत पक्षपात और सामाजिक पृष्ठभूमि के आधार पर भेदभाव अब भी गहराई से मौजूद है। उन्होंने अपने अंतिम दिनों में फेसबुक पर पीड़ा लिखी की इस देश में समान अवसर नहीं है,वह उनके भीतर चल रही मानसिक वेदना को स्पष्ट करती है। उन्होंने बार-बार बताया कि विश्वविद्यालयों में अनुसूचित जाति और वंचित समुदायों के छात्रों के साथ अदृश्य और सूक्ष्म भेदभाव किया जाता है, जिससे उनका आत्मसम्मान टूटता है। समाचार पत्रों में यह लिखा गया की यह सामाजिक उपेक्षा,संरचनात्मक भेदभाव और मानसिक तनाव का सम्मिलित बोझ था जिसने मुथुकृष्णन जैसी प्रतिभा को समाप्त कर दिया।

अनीता,तमिलनाडु के अरियालुर जिले के एक बेहद गरीब दलित परिवार की प्रतिभाशाली छात्रा थीं। उनका सपना डॉक्टर बनने का था,जिसे उन्होंने अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितियों में भी जीवित रखा था। अनीता ने बारहवीं कक्षा में विज्ञान वर्ग से शानदार अंक प्राप्त किए और तमिलनाडू मेडिकल प्रवेश प्रणाली के तहत मेडिकल कॉलेज में प्रवेश पाने की पूरी योग्यता रखती थीं। लेकिन 2017 में नीट को अनिवार्य करने के फैसले ने उनके सपने और संघर्ष को गहरा झटका दिया। अनीता ने राज्य बोर्ड की परीक्षा से टॉप करने के बावजूद नीट के लिए पर्याप्त संसाधन न होने,कोचिंग की सुविधा न मिल पाने और परीक्षा के पैटर्न में भारी अंतर के कारण असमान शैक्षणिक प्रतियोगिता का सामना किया। इससे उनका आत्मविश्वास टूटने लगा। अनीता ने सुप्रीम कोर्ट में नीट के खिलाफ याचिका दायर की थी,उनका तर्क था कि यह परीक्षा गरीब,ग्रामीण,दलित और पिछड़े वर्ग के छात्रों के लिए अनुचित है। लेकिन जब निर्णय उनके पक्ष में नहीं आया तो उनके भीतर असफलता,निराशा और भविष्य के सपनों के टूटने का बोझ असहनीय हो गया। सितंबर 2017 में उनकी आत्महत्या ने पूरे देश को झकझोर दिया। डॉ.पायल तड़वी एक प्रतिभाशाली आदिवासी समुदाय से आने वाली युवा डॉक्टर थीं,जिन्होंने कठिन सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों को पार करते हुए मेडिकल क्षेत्र में अपना स्थान बनाया था। वे मुंबई के टॉपिवाला नेशनल मेडिकल कॉलेज और बीवाईएल नायर अस्पताल में स्त्रीरोग विभाग की पीजी छात्रा थीं। पायल न केवल अपने परिवार की पहली महिला डॉक्टर थीं बल्कि आदिवासी समुदाय के लिए प्रेरणा का स्रोत भी थी। मई 2019 में उनकी आत्महत्या ने पूरे देश में आक्रोश पैदा कर दिया। पायल लम्बे समय से अपने विभाग में वरिष्ठ रेज़िडेंट डॉक्टरों द्वारा जातिगत टिप्पणियों,अपमानजनक व्यवहार,पेशेवर बहिष्कार और निरंतर मानसिक उत्पीड़न का सामना कर रही थीं। कई रिपोर्टों में बताया गया कि उन्हें ऑपरेशन थिएटर से बाहर रखा जाता,काम के दौरान नीचा दिखाया जाता और उनकी जाति पर अपमानजनक टिप्पणियां की जाती थीं। यह संस्थागत जातिगत उत्पीड़न धीरे-धीरे उनके आत्मसम्मान और मानसिक स्वास्थ्य को गंभीर रूप से प्रभावित कर रहा था। यह मानसिक,सामाजिक और पेशेवर उत्पीड़न का मिला,जुला दबाव था जिसने उन्हें आत्महत्या जैसे चरम कदम की ओर धकेला।

आधुनिक और स्वतंत्र भारत में दलित और वंचितों की सुरक्षा के लिए अनेक संविधानिक प्रावधानों के बाद भी प्रतिभाशाली अधिकारियों और विद्यार्थियों की जातिगत भेदभाव के चलते आत्महत्याएं समाज को शर्मसार करने वाली है। लेकिन यह वंचित वर्ग के पढ़े लिखे युवाओं की संघर्ष क्षमता में कमी को भी दर्शाता है,और फिर डॉ. अंबेडकर के अनुयायी होने का दावा करने वाले युवाओं के लिए तो आत्महत्या की स्वीकार्यता हो ही नहीं सकती।

डॉ.भीमराव अंबेडकर के सामने चुनौतियां कम नहीं थीं, लेकिन वे हर परिस्थिति में अडिग रहे। उनके संघर्ष का विस्तार और गहराई इतनी बड़ी थी कि किसी भी सामान्य व्यक्ति को तोड़ सकती थी, लेकिन अंबेडकर ने हर कठिनाई को अपने मिशन की ऊर्जा बना दिया। डॉ. अंबेडकर के समय और आज का समय मूलभूत रूप से भिन्न हैं। अंबेडकर ने ऐसे दौर में संघर्ष किया,जब अस्पृश्यता,जातिगत भेदभाव,सामाजिक बहिष्कार और आर्थिक शोषण व्यापक रूप से स्वीकृत सामाजिक व्यवस्था का हिस्सा थे। उनके समय में शिक्षा, संसाधन,अवसर और अभिव्यक्ति की आज़ादी दलितों सहित वंचित समुदायों के लिए लगभग बंद दरवाज़े थे। शिक्षा,सामाजिक सम्मान हो या राजनीतिक प्रतिनिधित्व का अधिकार, अंबेडकर को कड़े संघर्ष,विरोध और अपमान झेलकर हासिल करना पड़ा।

डॉ.अंबेडकर ने अपने जीवन में वे सभी अत्याचार,अपमान, उपेक्षा और भेदभाव झेला,जिनसे कोई भी व्यक्ति टूट सकता था। लेकिन उन्होंने कभी हार मानने या जीवन से भागने को विकल्प नहीं बनाया। जिस समाज ने उन्हें पानी तक नहीं छूने दिया,उन्होंने उसी समाज का संविधान लिखा। जिन लोगों ने उनका रास्ता रोका,उन्होंने उन्हें अपनी बुद्धि और कर्म से पीछे छोड़ दिया। जिन जातिगत दीवारों ने उन्हें रोकने की कोशिश की,उन्होंने ज्ञान और संघर्ष से उन दीवारों को तोड़ दिया।

आज संविधान, कानून, शिक्षा और लोकतांत्रिक संस्थाएं दलितों के पास ताकत का औज़ार बनकर खड़ी हैं। समस्याएं आज भी हैं, लेकिन वे अंबेडकर के दौर जैसी भयावह, निराशाजनक और सर्वव्यापी नहीं हैं। अंबेडकर हमेशा जीवन को जीने, समाज बदलने और सशक्त बनने की प्रेरणा देते हैं। अगर डॉ. अंबेडकर ने आत्महत्या की होती,तो यह करोड़ो लोगो के लिए मार्गदर्शन और प्रेरणा का संकट बन जाता। बहरहाल जिंदगी में अंबेडकर को ढूँढ़िए। अंबेडकर के जीवन में आत्मविश्वास, संघर्ष और बेहतर भविष्य की रोशनी मिलेगी।

2023-24 में राजस्व वसूली लक्ष्य के अनुरूप नहीं होने से लैप्स हो गई राशि

नगरपालिका को अनुदान राशि से धोना पड़ा हाथ

बैतूल। नगरपालिका की लडख़ड़ाती राजस्व वसूली का सीधा असर अब शासन से मिलने वाली वित्तीय सहायता तक पहुंच गया है। वित्तीय वर्ष 2023-24 की राजस्व वसूली निर्धारित लक्ष्य से 22 प्रतिशत कम होने के कारण नगरपालिका को शासन से मिलने वाली 15वें वित्त आयोग की 12 करोड़ रुपए की अनुदान राशि से हाथ धोना पड़ा है। यह राशि सीधे उन निकायों को आवंटित कर दी गई, जिनकी वसूली लक्ष्य के अनुरूप रही। अब नगर पालिका दिसंबर माह में शिविरों के माध्यम से वसूली बढ़ाने की तैयारी कर रही है। दरअसल वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 में नपा को 11.63 करोड़ रुपए के राजस्व की डिमांड पूरी करनी है, लेकिन अब तक सिर्फ 2.73 करोड़ रुपए ही वसूले जा सके हैं। यानी वसूली 25 प्रतिशत पर ही अटकी है। स्थिति यह है कि विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत जिले में चल रहा सर्वे कार्य में नगर पालिका के सहायक निरीक्षकों को भी लगाया गया है, ऐसे में नवंबर माह में वसूली की रफ्तार काफी धीमी रही। जिसका असर नगरपालिका की वित्तीय स्थिति पर पडऩे की बात कहीं जा रही है, जो नपा की गंभीर नकदी कमी को दर्शाता है।

खराब प्रदर्शन का सीधा प्रभाव - शासन हर वर्ष राजस्व वसूली लक्ष्य में लगभग 13 प्रतिशत की बढ़ोतरी करता है, लेकिन वित्तीय वर्ष 2023-24 में नगरपालिका लक्ष्य से 22 प्रतिशत कम वसूली कर पाई। निर्धारित लक्ष्य से बड़े अंतर के कारण शासन ने अनुदान राशि को स्वीकृत नहीं किया और उसे अन्य निकायों की ओर मोड़ दिया। यह राशि अगर मिल जाती, तो बैतूल में सडक़, जलप्रणाली और अन्य मूलभूत सुविधाओं से जुड़े विकास कार्यों को गति मिल सकती थी। ग्रांट लैप्स होने के बाद नगरपालिका सीएमओ ने स्पष्ट रूप से कहा कि इस स्थिति की बड़ी वजह राजस्व अमले की लापरवाही है। उन्होंने बताया कि राजस्व अमले द्वारा वसूली समय पर और लक्ष्य के अनुरूप नहीं की गई। वर्तमान में भी वसूली को लेकर यही स्थिति बनी हुई है। अब पूरी प्रक्रिया की समीक्षा की जाएगी।

विकास कार्यो पर रोक जैसे हालात - नगरपालिका की आर्थिक तंगी का असर, जो निर्माण कार्य चल रहे और प्रस्तावित है, उन विकास कार्यों पर साफ दिख रहा है। बताया जा रहा है कि कई प्रोजेक्टों के वर्कऑर्डर जारी होने के बावजूद भुगतान के लिए धन उपलब्ध नहीं है। कुछ ठेकेदारों ने काम शुरू नहीं किया, जबकि कुछ ने शुरू किए गए कार्य मध्य में रोक दिए। भविष्य की स्वीकृत योजनाएं भी अभी कागजों पर ही अटक गई हैं। यह स्थिति बताती है कि नगरपालिका की वित्तीय व्यवस्थाओं में सुधार की तत्काल जरूरत है। इधर राजस्व वसूली को लेकर नगरपालिका सीएमओ ने राजस्व निरीक्षकों और सहायक राजस्व निरीक्षकों को सख्त निर्देश देकर प्रतिदिन कम से कम 25 हजार रूपये वसूली का लक्ष्य दिया था, लेकिन विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत सर्वे के कारण वसूली की रफ्तार धीमी पड़ गई।

लोक अदालत और शिविर लगाकर वसूली की तैयारी

नगरपालिका अब राजस्व संग्रह बढ़ाने के लिए लोक अदालत के माध्यम से वसूली के साथ-साथ वार्ड-वार्ड शिविर लगाने की योजना बनाई है। बताया जा रहा है कि दिसंबर माह से नगरपालिका शिविर लगाकर संपत्तिकर और जलकर की वसूली करेगी। शहर के सभी वार्डों में शिविर लगेंगे। जिससे कि वसूली अभियान को तेज गति मिल सके। बताया जा रहा है कि नगरपाालिका ने किस दिन, किस वार्ड में शिविर लगाना है, इसकी भी कार्ययोजना बना ली है। जैसे ही राजस्व निरीक्षक और सहायक राजस्व निरीक्षक विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत सर्वे से फ्री होते है, नगरपालिका वसूली अभियान को तेज कर देगी, ताकि नगरपालिका की वित्तीय स्थिति में सुधार आ सके। इसके अलावा जिन कर्मचारियों ने वसूली में लापरवाही की है, उनके विरुद्ध कार्रवाई भी कर सकती है।

इनका कहना है -

मैं उस समय यहां पदस्थ नहीं था, हो भी सकता है कि राशि लैप्स हो गई हो। जो निकाय वसूली बढ़ाकर नहीं करती है तो राशि लैप्स हो जाती है। मैंने मेरे कार्यकाल में करों में वृद्धि की है। पहले नल का 125 लगता था, जिसे बढ़ाकर 150 और कचरे का 100 प्रतिमाह कर दिया है। पुराने समय में करों में वृद्धि नहीं होने के कारण राशि लैप्स हुई होगी। मैं इसे दिखवाता हूं।

- सतीश मटसेनिया, सीएमओ, नगरपालिका बैतूल

793 ग्रामों में पेयजल प्रबंधन के लिए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के सुझाव पर बनेगी कार्ययोजना

545 ग्रामों में प्रगतिरत समूह जलप्रदाय योजनाओं को शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश

बैतूल। आदिवासी बाहुल्य बैतूल जिले के गांव-गांव तक नियमित पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष, बैतूल विधायक हेमंत खंडेलवाल का फोकस ग्रामीण इलाकों के पेयजल प्रबंधन पर है। बैतूल जिले के 545 ग्रामों में नियमित पेयजल की उपलब्धता के लिए श्री खंडेलवाल के विशेष प्रयासों से लगभग 806 करोड़ रुपए की चार समूह जलप्रदाय योजनाएं प्रगतिरत हैं। श्री खंडेलवाल की चिंता बैतूल जिले के उन 793 ग्रामों की है, जहां पीएचई एवं ग्राम पंचायत द्वारा नल जल योजनाएं संचालित की जा रही है। भू जल स्तर में लगातार आ रही गिरावट से आगामी 25-30 वर्षों में इन 793 ग्रामों में संभावित पेयजल समस्या के स्थाई निराकरण के लिए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष, बैतूल विधायक हेमंत खंडेलवाल ने महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं। भोपाल में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में बैतूल जिले के 793 ग्रामों में पेयजल प्रबंधन को लेकर दिए गए महत्वपूर्ण सुझावों को मध्य प्रदेश की पीएचई मंत्री श्रीमती संपतिया उईके एवं एसीएस पी.नरहरि ने खासी गंभीरता से लेकर सुझाव के मुताबिक कार्य योजना बनाने के निर्देश विभाग के अफसरों, इंजीनियरों को दिए। बैठक में भैंसदेही विधायक महेंद्र सिंह चौहान, मुलताई विधायक चंद्रशेखर देशमुख ,आमला विधायक डॉ योगेश पांडाग्रे, घोड़ाडोंगरी विधायक श्रीमती गंगाबाई उईके ,जल निगम के एमडी के.वी.एस. चौधरी, पीएचई के प्रमुख अभियंता संजय अंधवान सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे । भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने बैठक में अवगत कराया कि बैतूल जिले में 545 ग्रामों में पेयजल के लिए लगभग 806 करोड़ रुपए की लागत से गढ़ा, मेंढ़ा, घोघरी, वर्धा समूह जल प्रदाय योजनाएं प्रगतिरत है। जबकि अन्य लगभग 793 ग्रामों में पीएचई एवं ग्राम पंचायत द्वारा नलजल योजनाओं, ट्यूबवेल, स्पॉट सप्लाई के माध्यम से पेयजल प्रबंधन किया जा रहा है । श्री खंडेलवाल ने कहा कि पानी के लगातार दोहन से भूजल स्तर 600 से 1000 फीट तक पहुंच गया है। आगामी वर्षों में भूजल स्तर में और अधिक गिरावट होने से समूह जल प्रदाय योजनाओं से छूट लगभग 793 ग्रामों में पेयजल संकट की स्थिति निर्मित हो सकती है। श्री खंडेलवाल ने इन 793 ग्रामों में पेयजल प्रबंधन के लिए सुझाव दिया कि पूरे जिले को समूह जलप्रदाय योजनाओं से कवर करने के लिए नदियों पर वाटर बॉडी की श्रृंखला का निर्माण कर जल स्त्रोत डेवलप किए जाएं तथा 50 से 100 ग्रामों की क्लस्टर आधारित समूह जलप्रदाय योजनाएं बनाई जाए। इसके लिए पीएचई ,जल निगम एवं पंचायत संस्थाएं समन्वय स्थापित कर कार्य करें। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष, बैतूल विधायक हेमंत खंडेलवाल द्वारा भविष्य को दृष्टिगत रखते हुए बैतूल जिले के 793 ग्रामों में पेयजल प्रबंधन को लेकर दिए गए महत्वपूर्ण सुझाव पर पीएचई मंत्री श्रीमती संपतिया उईके एवं एसीएस पी.नरहरि ने सहमति जताते हुए उक्त सुझाव के अनुसार कार्य योजना बनाने के निर्देश अधिकारियों और इंजीनियरों को दिए।

शहर में बिगड़ती यातायात व्यवस्था और सुरक्षा को लेकर एसडीएम ने ली बैठक

आमला। हर साल की तरह इस साल भी गन्ने के मौसम में शहर के मुख्य मार्ग और रिहायशी इलाकों से गुजरती गन्ने की ओवरलोड ट्रालियां लगातार दुर्घटनाओं का सबब बनती जा रही है। इलाके में कई बार तो इन गन्नों की ओवरलोड ट्रालियां, लोगों की जान तक ले चुकी है, किंतु सुरक्षा से खिलवाड़ और यातायात व्यवस्था को बिगाड़ती गन्नों की ये ओवरलोड ट्रालियों पर हमेशा ही स्थानीय प्रशासन मूक दर्शक बना रहता है। अब एक बार फिर इलाके में गन्ने की ट्रालियां गुजरने का सिलसिला शुरू हो गया है। शिकायतें हुई तो प्रशासन ने जनपद के सभाकक्ष में कुछ व्यापारी और कुछ किसानों को बुलाकर समझाइश भी दी है। इस मौके पर एसडीम शैलेंद्र बड़ोनिया, नगरपालिका अधिकारी नितिन बिंझवे, थाना प्रभारी मुकेश ठाकुर , बिजली कंपनी के कनिष्ठ यंत्री विलास उईके, नगर पालिका अध्यक्ष नितिन गाडरे, उपाध्यक्ष किशोर माथनकर के अलावा व्यापारी संघ अध्यक्ष संजय साहू, हेमंत गुगनानी, गुणवंत सिंह चड्ढा, किसान संघ के संतोष यादव, दिनेश रघुवंशी, रविकांत उघड़े आदि शामिल थे। किसानों और व्यापारियों के बीच हुई बैठक का नेतृत्व एसडीएम शैलेंद्र बडोनिया द्वारा किया गया। जिसमें सर्वसम्मति से व्यापारियों ने दुकानों के बाहर तक पसरी दुकानों और सामान को नियंत्रण में रखने तथा बाजार के दिन बड़े वाहनों को दुकानों के सामने खड़े नहीं करने पर अपनी सहमति दी है। इधर इलाके में दो साप्ताहिक बाजार लगते हैं ऐसे में इस दिन रात 9 बजे से सुबह 9 के बीच ही गन्ने की ट्रालियां निकालने पर किसानों ने अपनी सहमति दी है। यानी व्यापारी और किसानों ने शहर की यातायात व्यवस्था को व्यवस्थित रखने के लिए अपनी-अपनी सहमति दे दी है, इससे जंहा लोगों को सुविधा और सुरक्षा मिलेगी, वंही यातायात व्यवस्था दुरुस्त रहेगी। हालांकि नियम न मानने वालों के खिलाफ कार्यवाही की बात भी प्रशासन द्वारा की गई है।

व्यवस्था सुधारे बिजली कंपनी

बैठक में उपस्थित बिजली कंपनी के कनिष्ठ यंत्री विलास उईके को शहर में बेतरतीब लटके बिजली के तारों को हटाकर केबल लगाने और बिजली के पोल की ऊंचाई बढ़ाने को लेकर अधिकारियों ने निर्देश दिए है। गौरतलब है कि बिजली कंपनी की लापरवाही भी शहर में अक्सर हादसे का कारण बनती है, जिससे लोगों को परेशानी हो रही है।

समस्याओं को लेकर जेएच कॉलेज में एबीवीपी ने किया प्रदर्शन

बैतूल। जिले के सबसे बड़े जेएच कॉलेज में शुक्रवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) के कार्यकर्ताओं और छात्रों ने कॉलेज प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया। छात्रों ने कॉलेज परिसर का मुख्य द्वार बंद कर दिया और धरना देते हुए नारेबाजी की। हंगामे की सूचना मिलने पर पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे और छात्रों को समझाया। इसी बीच, प्राचार्य भी कॉलेज पहुंचीं। इस दौरान छात्रों और प्राचार्य के बीच कॉलेज की विभिन्न समस्याओं को लेकर बहस हुई। इसके बाद छात्र नेताओं ने अनुविभागीय दंडाधिकारी (एसडीएम) को एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कॉलेज में हो रही गड़बडियों की की जांच की मांग की गई है। छात्रों ने ज्ञापन में बताया कि अनुसूचित जाति-जनजाति (एससी-एसटी) के छात्रों के लिए पुस्तकें नहीं खरीदी जा रही हैं। कॉलेज परिसर, दफ्तर और विभिन्न विभागों में मादक पदार्थ पाए जा रहे हैं। कई बार ज्ञापन देने के बावजूद इन समस्याओं पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इसके अतिरिक्त, छात्रावास में बाहरी छात्राओं को दो साल से रखा गया है, जबकि इस वर्ष की छात्राओं का प्रवेश अब तक नहीं हुआ है। छात्रों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर शीघ्र कार्रवाई नहीं की गई तो वे एक बड़ा आंदोलन शुरू करेंगे।

शासकीय एकलव्य महिला आईटीआई में उद्यमिता कार्यशाला आयोजित

बैतूल। शासकीय एकलव्य महिला आईटीआई बैतूल में शुक्रवार को सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत एमएसएमई टेक्नोलॉजी सेंटर भोपाल के अधिकारियों द्वारा उद्यमिता कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस दौरान प्रशिक्षणार्थियों को पारंपरिक रोजगार के साथ-साथ उद्योग की स्थापना, स्टार्टअप और कौशल आधारित स्वरोजगार के लिए मार्गदर्शन दिया गया। एमएसएमई भोपाल के इंजीनियर देवेंद्र कुमार परोरा सुबोध कुमार ने छात्राओं को प्रोजेक्ट रिपोर्ट, उद्यम पंजीयन, मार्केट सर्वे, वित्तीय सहायता, बैंकिंग, ब्रांडिंग एवं मार्केटिंग तकनीकी सहित उद्यमिता से जुड़े अनेक विषयों पर प्रशिक्षण दिया। श्री परोरा ने बताया कि व्यवसाय की नींव केवल पूंजी पर नहीं, बल्कि योजना, कौशल, आत्मविश्वास, मार्केट की समझ और प्रबंधन क्षमता पर आधारित होती है। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति का कौशल ही उसकी सबसे बड़ी पूंजी है, जो व्यवसाय शुरू करने में निर्णायक की भूमिका निभाती है। छोटे स्तर पर शुरू गया किया गया व्यापार भी निरंतर सुधार एवं प्रयास से बड़े उद्योग का स्वरूप ले सकता है।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सहित विधायकों ने वर्ल्ड कप विजेता दुर्गा को किया सम्मानित

बैतूल और भैंसदेही विधायक भेंट करेंगे 51-51 हजार की प्रोत्साहन राशि

बैतूल। पहले टी-20 ब्लाइंड महिला वर्ल्ड कप में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर टीम इंडिया को विश्व विजेता बनने में मुख्य भूमिका अदा करने वाली बैतूल जिले के भैंसदेही विधानसभा क्षेत्र के रॉक्सी ग्राम की बिटिया ब्लाइंड क्रिकेटर दुर्गा येवले को शुक्रवार को भोपाल स्थित निवास पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष, बैतूल विधायक हेमंत खंडेलवाल सहित जिले के विधायकों ने सम्मानित किया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सहित जिले के विधायकों ने बैतूल, मध्यप्रदेश सहित देश का नाम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रोशन करने वाली बिटिया दुर्गा को पुष्प गुच्छ, शॉल, श्रीफल भेंट कर अभिनंदन किया और उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी । भाजपा प्रदेश अध्यक्ष, बैतूल विधायक हेमंत खंडेलवाल एवं भैंसदेही विधायक महेंद्र सिंह चौहान द्वारा प्रतिभावान बिटिया दुर्गा येवले को प्रोत्साहन स्वरूप 51- 51 हजार रुपए की राशि भेंट की जाएगी। इस दौरान भैंसदेही विधायक महेंद्र सिंह चौहान, मुलताई विधायक चंद्रशेखर देशमुख, आमला विधायक डॉ योगेश पंडाग्रे, घोड़ाडोंगरी विधायक श्रीमती गंगाबाई उईके मौजूद रहे ।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बैतूल विधायक हेमंत खंडेलवाल ने वर्ल्ड कप विजेता दुर्गा येवले को अपने भोपाल स्थित निवास पर सम्मानित करते हुए कहा कि बैतूल की बेटी दुर्गा ने दिव्यांगता के बावजूद अपनी मेहनत और दृढ़ इच्छा शक्ति से ऐतिहासिक सफलता हासिल करने के साथ ही बैतूल से लेकर मध्यप्रदेश और देश का नाम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रोशन किया है। आज दुर्गा येवले समाज के लिए प्रेरणास्त्रोत है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष श्री खंडेलवाल ने कहा कि ग्रामीण अंचलों में प्रतिभाओ की कमी नहीं है, जरूरत है प्रतिभाओं को आगे लाकर उन्हें सही प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की मध्यप्रदेश सरकार खिलाडियों, दिव्यांगजनों सहित समाज के हर वर्ग के उत्थान के लिए सतत काम कर रही है उन्होंने वर्ल्ड कप विजेता दुर्गा येवले को आगे बढ़ाने के लिए हर संभव मदद का भरोसा दिया।

टी - 20 की महिला विश्वकप विजेता दुर्गा येवले (यादव) का भाजपा ने किया सम्मान

बैतूल। टी-20 दृष्टिबाधित विश्वकप क्रिकेट प्रतियोगिता में भारत को विश्व विजेता बनाने वाली क्रिकेट टीम की विकेट कीपर बल्लेबाज दुर्गा येवले (यादव) के अपने गृह जिले में प्रथम आगमन पर भाजपा परिवार ने अंतराष्ट्रीय स्तर पर जिले का मान बढाने वाली बिटिया का आत्मीय अभिनंदन कर पुष्पगुच्छ और स्मृति चिन्ह भेंट कर स्वागत किया। इस अवसर पर उत्साहित भाजपा कार्यकर्ता व पदाधिकारियों ने विश्व पटल पर जिले का नाम स्वर्णिम अक्षरो में अंकित करने वाली दुर्गा येवले (यादव) का पुष्प वर्षा करते हुए जमकर आतिशबाजी कर मिठाई वितरित कर स्वागत किया। इस गौरवपूर्ण मौके पर भाजपा जिलाध्यक्ष सुधाकर पंवार ने कहा कि भैंसदेही विकासखंड के ग्राम राक्सी में निवासरत झब्बु येवले (यादव) एवं गौरा येवले (यादव) की बिटियां ने पूरे जिले का मस्तक विश्व पटल पर उचा किया है। बचपन से दृष्टि बाधित होने के बावजूद बिटियां ने अपने सपनों को साकार करने के लिए जो परिश्रम किया है। वह सम्मान का अधिकार है। खेल के मैदान में अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन करने की निरंतरता ही विश्व विजेता बनाती है। हमारे जिले की बिटियां विश्व कप विजेता टीम की सदस्य है यह हर खेल प्रेमी के लिए गौरव का विषय है। दुर्गा येवले (यादव) ने अंतराष्ट्रीय क्षितिज पर उत्कृष्ट प्रदर्शन कर प्रेरणा का कार्य किया है। आज जब संसाधनो की कमी का बहाना बनाकर लोग अपने सपने त्याग देते है ऐसे समय में अपने परिश्रम पर विश्वास जताते हुए दुर्गा यादव के प्रयास समाज के लिए युवाओं के लिए प्रेरणा का कार्य करेगें ऐसी शुभकानाओं के साथ उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते है। अभिनंदन के दौरान जिला महामंत्री कृष्णा गायकी, जिला उपाध्यक्ष रश्मि साहू, कुणाल शर्मा, बिरजू पारखे सहित बडी संख्या में पार्टी पदाधिकारी व कार्यकर्तागण मौजूद रहे।

धार के ख्यात एडवोकेट रामनारायण धाकड़ की पत्नी प्रभादेवी के निधन पर नेत्रदान

प्रभादेवी धाकड़ शिक्षा जगत से जुड़ी हुई थीं

धार। धार के ख्यात एडवोकेट राम नारायण धाकड़जी की पत्नी श्रीमती प्रभादेवी का 65 वर्ष की उम्र में शुक्रवार को देवलोक गमन हो गया । राम नारायण जी और उनके पुत्र प्रकाश धाकड़ ने श्रीमती प्रभावती जी धाकड़ के नेत्रदान की सहमति मानव सेवा कल्याण समिति के राजेश नाहर को दी उसके उपरांत जिला अस्पताल के नेत्र सहायक कर्मा मुजाल्दा व पीयूष परमार ने स्व. प्रभावती जी के नेत्रदान की प्रक्रिया पूर्ण की। स्व प्रभावती जी के नेत्र को पति राम नारायण धाकड़ व पुत्र प्रकाश धाकड़ ने स्वास्थ्य विभाग व संस्था मानव सेवा कल्याण समिति को सौपा। मानव सेवा कल्याण समिति द्वारा यह 23 वां नेत्रदान है । इस अवसर पर समिति के अंशुल शर्मा, मिलन पाल , मनोज जैन , प्रफुल्ल जैन राजेश नाहर मौजूद थे। अंशुल शर्मा ने धाकड़ परिवार के इस दुख की घड़ी में नेत्रदान निर्णय की सराहना की व आभार माना। उल्लेखनीय है कि धार मानव सेवा समिति द्वारा विगत 15 दिनों में किया गया तीसरा नेत्रदान है जो दर्शात है कि धार शहर के नागरिक अब नेत्रदान, अंगदान, देहदान के प्रति काफी जागरूक हो चुके है।

भाजपा किसान मोर्चा की आगामी कार्य योजना को लेकर जिला बैठक

धार मुख्यालय पर किसान सम्मान यात्रा व किसान सम्मेलन का आयोजन होगा

धार। भाजपा जिला कार्यालय पर भाजपा किसान मोर्चा की आगामी कार्यक्रमों को लेकर जिला बैठक आयोजित की गई । मुख्य अतिथि भाजपा किसान मोर्चा प्रदेश महामंत्री एवं पूर्व जिलाध्यक्ष दिलीप पटोंदिया तथा अध्यक्षता भाजपा जिला अध्यक्ष महंत निलेश भारती ने बैठक को संबोधित किया।

इस दौरान मंच पर किसान मोर्चा पूर्व जिला अध्यक्ष जगदीश जाट, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष शैलेष यादव,भाजपा नेता महेश रावला ,किसान मोर्चा जिला महामंत्री विष्णु चौधरी,भाजपा जिला मीडिया प्रभारी संजय शर्मा, मोर्चा जिला उपाध्यक्ष रविंद्र पाटीदार,राजेंद्र पटेल पर्यावरणविद डॉ अमृत पाटीदार चतर सिंह बिजुर उपस्थित रहे। सर्व प्रथम अतिथियों ने भारत माता व पितृ पुरुष पंडित दीनदयाल उपाध्याय डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्रों पर माल्यार्पण दीप प्रज्वालित कर बैठक आरंभ की।

जिलाध्यक्ष निलेश भारती ने कहा कि प्रदेश सरकार से लेकर केंद्र सरकार तक किसान कल्याणकारी योजना के माध्यम से सरकार कृषि को लाभ का धंधा बनाने के कार्य में लगी है। भावांतर योजना से लेकर किसान सम्मान निधि तक ऐसी अनेक योजनाएं है जो भाजपा की सरकार किसानों के लिए कर रही है।

मुख्य अतिथि दिलीप पटोंदिया ने कहा कि प्रदेश नेतृत्व के अहवान पर आगामी दिनों में धार मुख्यालय पर किसान सम्मान यात्रा व किसान सम्मेलन का आयोजन तय हुआ है । इस आयोजन में किसान मोर्चा की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी हैं । हम सभी राष्ट्रवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। भाजपा की सरकार अंत्योदय के आधार पर जनकल्याणकारी कार्य कर रही है। भाजपा की सरकार ने गांवों को शहरों से जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री सड़क से लेकर किसान क्रेडिट कार्ड और नदी जोड़ो योजना से लेकर कृषि सिंचाई योजनाएं भावांतर योजना से लेकर किसान सम्मान निधि तक भाजपा सरकार ने किसानों के लिए दी है। प्रदेश की डॉ मोहन यादव सरकार ने लाखो किसानों के खाते में भावांतर की राशि डाली गई है।

इस अवसर पर विधायक प्रतिनिधि लाखन सिंह राजपूत, भाजपा जिला सह मीडिया प्रभारी दीपक सिंह रघुवंशी, किसान मोर्चा जिला पदाधिकारी राजेश वर्मा विकास शर्मा खरसोड़ा गंगाराम पटेल अनिरुद्ध सिंह ठाकुर रितेश अग्निहोत्री जगदीश कामदार रामलाल संगीत्रा कमलेश बिजवा खेमराज लववंशी समेत किसान मोर्चा मंडल अध्यक्ष उपस्थित रहे।

कलेक्टर सुश्री मीना ने समय-सीमा की बैठक में दिए महत्वपूर्ण निर्देश

ई-फाइलिंग पोर्टल पंजीयन में तेजी लाएं, सभी विभाग एक सप्ताह में कार्य पूर्ण करें : कलेक्टर सुश्री सोनिया मीना

नर्मदापुरम (निप्र)। ई-फाइलिंग पोर्टल पर सभी जिला अधिकारी अपने-अपने संबंधित विभागों का पंजीयन किया जाना सुनिश्चित करें। उक्त प्रक्रिया को आगामी एक सप्ताह में पूरी की जाए। संभाग आयुक्त कार्यालय द्वारा प्राप्त टीएल प्रकरणों का निराकरण समय अवधि में किया जाए। वन अधिकार पट्टा धारकों को शासन की योजनाओं का लाभ प्रदान किए जाने हेतु विशेष शिविरों का आयोजन किया जाए। जनजातिय कार्य विभाग अन्य संबंधित विभागों के साथ समन्वय कर केसीसी, पीएम किसान सम्मान सहित शासन की अन्य हितग्राही मूलक योजनाओं का लाभ पट्टा धारकों को पहुंचाए। सभी जिला अधिकारी अपने विभाग अंतर्गत संचालित विभिन्न स्वरोजगार योजनाओं के तहत प्राप्त लक्ष्यों की पूर्ति करें। धन उपार्जन केन्द्रों का सतत निरीक्षण कर समस्त आवश्यक व्यवस्थाओं का जायजा लें अधिकारी। उक्त निर्देश कलेक्टर सुश्री सोनिया मीना द्वारा साप्ताहिक समय सीमा की बैठक के दौरान समस्त जिलाधिकारियों को दिए गए।

ई-फाइलिंग पंजीयन एक सप्ताह में पूर्ण करें

कलेक्टर सुश्री सोनिया मीना ने समय सीमा की बैठक के दौरान निर्देशित किया कि सभी जिला अधिकारी अपने-अपने कार्यालय का पंजीयन ई फाइलिंग पोर्टल पर आगामी एक सप्ताह में किया जाना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि आगामी भविष्य में ई फाइलिंग पोर्टल के माध्यम से ही न्यायालयीन प्रक्रिया का संचालन किया जाएगा। साथ ही किसी भी प्रकार के न्यायालय प्रकरण को दर्ज करने में भी आसानी होगी। इसी के साथ कलेक्टर ने ई विकास पोर्टल के संबंध में भी किसानों से पोर्टल का संचालन करवाए जाने हेतु निर्देशित किया। कलेक्टर ने उपसंचालक कृषि विभाग को निर्देश दिए की पोर्टल के माध्यम से टोकन जेनरेशन किए जाने के लिए किसानों को प्रक्रिया से अवगत करावे।

टीएल प्रकरणों का समय-सीमा में निराकरण करें अधिकारी

बैठक के दौरान कलेक्टर ने निर्देश दिए कि संभाग आयुक्त कार्यालय से प्राप्त टीएल प्रकरणों के अंतर्गत समय सीमा में जवाब दर्ज किए जाएं। उन्होंने कहां की निर्धारित समय अवधि में जवाब दर्ज करना संबंधित अधिकारियों का दायित्व है। कलेक्टर ने समय सीमा शाखा प्रभारी को निर्देशित किया की समस्त अधिकारियों को संभाग आयुक्त कार्यालय द्वारा प्राप्त टीएल मामलों की सूची उपलब्ध करवाए एवं सर्व संबंधित अधिकारी उक्त प्रकरणों में शीघ्र ही शाखा में जवाब प्रस्तुत करें। कलेक्टर ने सख्त निर्देश दिए की समय सीमा के प्रकरणों के निराकरण में हीलाहवाली करने पर संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध नियम अनुसार कार्यवाही प्रस्तावित की जाएगी। इसी प्रकार उन्होंने निर्देश दिए की कलेक्टर कार्यालय द्वारा दर्ज टीएल प्रकरण में भी शीघ्र जवाब दर्ज किए जाएं तथा उक्त जवाब नस्ती पर भी प्रस्तुत करें जिससे टीएल प्रकरण को बंद किया जा सके। उन्होंने निर्देश दिए की 1 वर्ष अधिक पुरानी कोई भी टीएल प्रकरण लंबित न रहे संबंधित अधिकारी या सुनिश्चित करें।

वन अधिकार पट्टाधारकों को योजनाओं का लाभ दिलाने हेतु आयोजित करें विशेष शिविर

बैठक के दौरान वन अधिकार पट्टाधारकों को शासन की हितग्राही मूलक योजनाओं के लाभ से लाभान्वित करने के लिए जनजातीय कार्य विभाग को कलेक्टर द्वारा निर्देशित किया गया कि बैंक तथा अन्य विभागों के के बीच समन्वय

करवाते हुए पट्टाधारकों को केसीसी, पीएम किसान सम्मान निधि सहित शासन की अन्य योजनाओं का लाभ प्रदान कराया जाए। उन्होंने निर्देश दिए की जनजातीय कार्य विभाग विशेष शिवरों का आयोजन करें एवं योजनाओं का लाभ संबंधित पट्टाधारियों को उपलब्ध कारावें। कलेक्टर ने कहा कि एलडीएम योजनाओं से बैंक में लंबित संबंधित प्रकरणों का रिव्यू भी नियमित रूप से करें।

न्यायालयीन प्रकरणों में समय पर जवाब दर्ज करें अधिकारी

बैठक के दौरान कलेक्टर ने निर्देशित किया कि संबंधित अधिकारी विधि शाखा से समन्वय अपने-अपने कार्यालय से संबंधित न्यायालयीन प्रकरणों के बारे में जानकारी एकत्रित कर उनमें समय सीमा अवधि के अनुसार जवाब दावे दर्ज करें। उन्होंने कहा कि समस्त अधिकारी स्वयं जवाबदारी के साथ शाखा प्रभारी से चर्चा कर मामलो का गहनता पूर्वक अवलोकन करें एवं जवाब प्रस्तुत करे। कलेक्टर ने धान उपार्जन की समीक्षा करते हुए उपार्जन प्रक्रिया से संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि उपार्जन केन्द्रों का सतत भ्रमण करें। उन्होंने उपायुक्त सहकारिता, जिला आपूर्ति अधिकारी, जिला प्रबंधक वेयरहाउसिंग आदि अधिकारियों को निर्देशित किया कि उपार्जन केंद्र तथा वेयरहाउस का निरंतर निरीक्षण कर

स्वरोजगार योजनाओं के लक्ष्यों की शत-प्रतिशत पूर्ति करें संबंधित विभाग

समय सीमा की बैठक के दौरान कलेक्टर ने निर्देश दिए की स्वरोजगार योजनाओं के प्राप्त लक्षयों की पूर्ति के लिए संबंधित विभाग योजनाओं का लाभ पात्र नागरिकों तक पहुंचाने हेतु कार्यवाही तेज करें। उन्होंने निर्देश दिए की सभी संबंधित विभाग अपने-अपने विभागीय कार्यों में प्रगति लाए। उन्होंने निर्देश दिए की योजनाओं के अंतर्गत प्रकरण दर्ज न होने की स्थिति में संबंधित क्षेत्र के सीईओ एवं सीएमओ से चर्चा कर हितग्राहियों की पहचान करें। विशेष कार्यशालाओं का आयोजन भी करें जिससे हितग्राहियों को आवश्यकता अनुसार योजनाओं का लाभ प्रदान किया जा सके। कलेक्टर ने स्पष्ट रूप से निर्देश दिए की सभी विभाग यह सुनिश्चित करें की योजनाओं के लक्ष्य शत प्रतिशत प्राप्त कर लिए जाएं इसके लिए अभी से योजनाओं की वर्तमान स्थिति का आंकलन कर कार्य योजना तैयार करें। उन्होंने कहा कि संबंधित सीईओ एवं सीएमओ अपने क्षेत्र अंतर्गत पीएमएफएमई योजना के तहत स्वरोजगार स्थापित किए जाने हेतु पात्र हितग्राहियों का चिन्हांकन कर संबंधित विभाग के जिलाधिकारी को जानकारी उपलब्ध करवाए। एलडीएम बैंक मैनेजर्स से सतत बैठके कर स्वीकृत प्रकरणों में ऋण राशि का संवितरण सुनिश्चित करावे।

व्यवस्थाओं का जायजा लें। किसी भी प्रकार की अनियमित पाए जाने पर संबंधितों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करें। उन्होंने समस्त एसडीएम एवं तहसीलदारों को भी निर्देश दिए की व्यवस्थाओं को सुचारू रखने के लिए वह भी निरंतर धान खरीदी की मॉनिटरिंग करें।

कबड्डी खेल प्रदर्शन के साथ हुई सांसद खेल महोत्सव की शुरूआत

हरदा (निप्र)। सांसद खेल महोत्सव की शुरूआत मंगलवार को कबड्डी खेल प्रदर्शन के साथ ही हुई। सांसद खेल महोत्सव के तहत हरदा विधानसभा में मंगलवार को नगरपालिका अध्यक्ष श्रीमती भारती राजू कमेड़िया, जिला पंचायत उपाध्यक्ष श्री दर्शन सिंह गहलोत, पूर्व कृषि मंत्री श्री कमल पटेल, उपाध्यक्ष नगरपालिका परिषद हरदा श्री अंशुल गोयल, जिला अध्यक्ष भाजपा श्री राजेश वर्मा, जिला ओलम्पिक संघ अध्यक्ष श्री संदीप पटेल द्वारा उद्घाटन किया गया। पूर्व मंत्री श्री पटेल ने सांसद खेल महोत्सव के आयोजन पर ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाली प्रतिभा को हरदा जिले का नाम रोशन करने के लिए शुभकामनाएं दीं एवं सांसद खेल महोत्सव का ध्वजारोहण किया। इस अवसर पर जिला ओलम्पिक संघ अध्यक्ष श्री संदीप पटेल ने खिलाड़ियों को अनुशासन व नियम से खेल हेतु शपथ दिलाई। ब्लॉक समन्वयक सुश्री सलमा खान ने बताया कि 3 दिसंबर को विधान सभा स्तर की प्रथम खेल प्रतियोगिता शुरूआत खो खो खेल से हुई। खो खो खेल प्रतियोगिता बालक बालिका वर्ग में ग्राम मसनगांव, चारूवा, हंडिया, छीपाबड़, मांदला, सांदीपनी स्कूल खिरकिया, शास उत्कृष्ट विद्यालय हरदा, शासकीय महात्मा गांधी स्कूल हरदा, शास कन्या शाला हरदा, जोनर एजुकेशन सिस्टम हरदा, सनफ्लावर स्कूल, संस्कार विद्यापीठ स्कूल हरदा, महर्षि ज्ञानपीठ स्कूल हरदा के लगभग 560 बच्चो ने भाग लिया। इस दौरान जनप्रतिनिधियों से खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर प्रतियोगिता की शुरूआत की। फाइनल मुकाबला बालक वर्ग में सांदीपनी स्कूल खिरकिया विरुद्ध खो खो कल्याण संघ हरदा के मध्य खेला गया, जिसमें सांदीपनी स्कूल विजेता रहा। बालिका वर्ग फाइनल मैच खो खो कल्याण संघ हरदा विरुद्ध सनफ्लावर स्कूल हरदा के मध्य हुआ। जिसमें खो खो कल्याण संघ विजेता रहा। इस प्रकार बालक वर्ग में सांदीपनी विद्यालय खिरकिया विजेता तथा खो खो कल्याण संघ हरदा उप विजेता रहा तथा जोनर एजुकेशन सिस्टम हरदा तृतीय स्थान पर रहा।

संक्षिप्त समाचार

ग्रामीणो ने बीएलओ की उपलब्धि पर स्वागत किया

विदिशा (निप्र)। मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान (एसआईआर) के तहत शत प्रतिशत कार्यो को संपादन करने वाले बीएलओ का स्थानीय ग्रामीणो ने स्वागत किया है। नटेरन एसडीएम श्री अजय प्रताप सिंह पटेल ने बताया कि शमशाबाद विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत उक्त कार्य को संपादित कराने वाले मतदान केन्द्र क्रमांक 161 कस्बाखेडी के बीएलओ श्री लालाराम अहिरवार द्वारा सौ प्रतिशत एसआईआर के कार्य पूर्ण कराने पर ग्रामीणो द्वारा भव्य स्वागत किया गया है।

ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस पर किया गया 861 बच्चों का टीकाकरण

सीहोर (निप्र)। स्वास्थ्य विभाग द्वारा ग्राम स्वास्थ्य पोषण दिवस के तहत जिलेभर में विभिन्न स्वास्थ्य संस्थाओं में शिविर लगाकर गर्भवती महिलाओं एवं बच्चों के विभिन्न बीमारियों से बचाव के लिए टीकाकरण किया गया। जिले में 02 दिसंबर को आयोजित शिविरों में शून्य से एक वर्ष की आयु के 655 बच्चों तथा एक वर्ष से अधिक आयु के 206 बच्चों का टीकाकरण किया गया। इसके साथ ही 95 गर्भवती महिलाओं का स्वास्थ्य परीक्षण भी किया गया। स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रत्येक मंगलवार एवं शुक्रवार को ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसके तहत शिविर लगाकर बच्चों के टीकाकरण के साथ ही बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं को अन्य स्वास्थ्य सेवाएं भी उपलब्ध कराई जाती है।

किसानों के हितों को ध्यान में रखकर तय हों फसल ऋणमान : कलेक्टर सुश्री सोनिया मीना

नर्मदापुरम (निप्र)। कलेक्टर सुश्री सोनिया मीना की अध्यक्षता में वर्ष 2026-27 के फसल ऋणमान के निर्धारण हेतु जिला स्तरीय तकनीकी समूह की बैठक संपन्न हुई। बैठक में जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक के मुख्य कार्यपालन अधिकारी संयोजक के रूप में उपस्थित रहे। कलेक्टर सुश्री मीना द्वारा निर्देश दिए गए कि वर्ष 2026-27 के लिए प्रस्तावित फसल ऋणमान, वर्ष 2025-26 हेतु राज्य स्तरीय तकनीकी समूह द्वारा निर्धारित ऋणमान से कम नहीं होना चाहिए। उन्होंने संबंधित विभागों को फसल ऋणमान के निर्धारण में आवश्यक तकनीकी परीक्षण, मूल्यांकन एवं औचित्य का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए। बैठक के दौरान कलेक्टर सुश्री मीना द्वारा निर्देशित किया गया कि जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक से संबद्ध सहकारी समितियों के पुराने कालातीत सदस्यों की वसूली आगामी नेशनल लोक अदालत 13 दिसम्बर 2025 के माध्यम से कराई जाएगी। इसके प्रभावी क्रियान्वयन एवं व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु उपायुक्त सहकारिता, जिला नर्मदापुरम तथा जिला बैंक नर्मदापुरम के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को निर्देशित किया गया। बैठक में जिला विकास अधिकारी, नाबार्ड, उप संचालक किसान कल्याण एवं कृषि विभागश्री जे आर हेडाउ, उपायुक्त सहकारिता श्री शिवम मिश्रा, सहायक संचालक मत्स्य विभागश्री वीरेन्द्र चौहान, उप संचालक पशुपालन विभाग सहित बैंक के मुख्य कार्यपालन अधिकारी उपस्थित रहे।

रायसेन में विधिक जागरूकता एवं साक्षरता शिविर आयोजित

रायसेन (निप्र)। मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार एवं प्रधान जिला न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री अनिल कुमार सोहाने के मार्गदर्शन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रायसेन द्वारा विश्व एड्स दिवस के संबंध में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रायसेन एवं सर्वोदय विंध्य विकास समिति रायसेन के संयुक्त तत्वाधान में दिनांक 03 दिसम्बर 2025 को एनजीओ सर्वोदय विन्ध्य विकास समिति सांची रोड रायसेन में विधिक जागरूकता एवं साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित द्वितीय जिला न्यायाधीश श्री महेश कुमार माली द्वारा एड्स रोग के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि यह एक गंभीर बीमार है जिसका अभी तक कोई इलाज नहीं है।

ई-विकास पोर्टल आधारित उर्वरक वितरण प्रणाली- किसानों के लिए पारदर्शी एवं समय पर उर्वरक उपलब्धता की नई पहल

नर्मदापुरम (निप्र)। किसान कल्याण तथा कृषि विकास नर्मदापुरम द्वारा किसानों को अनुदानित उर्वरकों की सुलभता से उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु ई-विकास पोर्टल आधारित उर्वरक वितरण प्रणाली लागू की जा रही है। इस संबंध में कृषि विस्तार एवं प्रशिक्षण केन्द्र पवारखेड़ा, जनपद पंचायत सभाग्रह सिवनी मालवा एवं जनपद पंचायत सभाग्रह पिपरिया में प्रशिक्षण आयोजित किया गया। प्रशिक्षण में उपसंचालक कृषि श्री जे.आर. हेडाऊ, सहायक संचालक कृषि एवं क्रिस्प के प्रतिनिधि द्वारा जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित से संबंधित प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के प्रबंधक, मार्कफेड डबल लॉक उर्वरक वितरण केन्द्रों के प्रबंधक, एम.पी. एग्रो गोदाम प्रभारी, विपणन समितियों के प्रभारी एवं निजी फुटकर उर्वरक विक्रेताओं को प्रशिक्षण दिया गया । ई-विकास पोर्टल आधारित उर्वरक वितरण प्रणाली के माध्यम से पोर्टल पर दिखाए गए, उर्वरक विक्रेता के पास उपलब्ध उर्वरक की मात्रा अनुसार मनचाहे निकटतम उर्वरक विक्रेता अथवा फर्म के नाम का चयन कर, किसान भाई अपना पंजीयन करने उपरान्त उर्वरक प्राप्ति के लिए घर बैठे ई-टोकन प्राप्त कर सकते है। इस टोकन में किसान की जानकारी, उर्वरक का प्रकार, मात्रा, उर्वरक वितरण केन्द्र/फर्म एवं प्राप्ति तिथी की समय सीमा दर्ज होती है। किसान इस टोकन को मोबाईल ऐप या वैब पोर्टल के माध्यम से निर्धारित समय पर उर्वरक प्राप्त कर सकते है, इससे अनुदानित उर्वरकों का पारदर्शिता से वितरण होगा और किसानों को लंबी कतारो से मुक्ति मिलेगी। जिन किसान भाइयों की भूमि की जानकारी एग्रीस्टेक पोर्टल पर उपलब्ध नहीं है वे किसान भाई ट्रस्ट/पट्टा/अन्य किसान पंजीयन प्रक्रिया के माध्यम से भूमि की जानकारी को अपडेट कर सकते है जिसका सत्यापन संबंधित क्षेत्र के राजस्व अधिकारी द्वारा किया जाएगा। यह उर्वरक वितरण प्रणाली, डिजिटल कृषि की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो जिले के किसान भाइयों को समय पर, फसल की आवश्यकता अनुसार उर्वरको की उपलब्धता में सरलता एवं पारदर्शिता के साथ-साथ शासकीय संसाधनों के प्रभावी प्रबंधन में भी सहायक सिद्ध होगी।

अपनी मेहनत और लगन से अनेक दिव्यांगजनों ने सफलता के कीर्तिमान स्थापित किए हैं: कलेक्टर श्री विश्वकर्मा

विश्व दिव्यांगजन दिवस पर रायसेन में जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित

रायसेन (निप्र)। जिनके मन में कुछ कर दिखाने का जज्बा हो, पक्का इरादा हो वह कभी किसी बाधा से नहीं घबराते। जब दिव्यांग अपने मन में कुछ करने की ठान लेते हैं, पूरी लगन और मेहनत से प्रयास करते है तो वह जीवन में उच्च लक्ष्यों को प्राप्त करके समाज के लिए प्रेरणा स्त्रोत बनते हैं। अनेक दिव्यांगजनों ने अपनी मेहनत और दृढ़ निश्चय से सफलता के कीर्तिमान स्थापित किए हैं। यह बात कलेक्टर श्री अरूण कुमार विश्वकर्मा ने विश्व दिव्यांगजन दिवस पर रायसेन स्थित खेल स्टेडियम में आयोजित दिव्यांगजनों के कौशल एवं सामर्थ्य

प्रदर्शन और सांस्कृतिक कार्यक्रम में कही। उन्होंने कहा कि कि दिव्यांगजनों में बहुत सी प्रतिभाएं होती है।

बस जरूरत होती है तो उस प्रतिभा को पहचानने की और निखारने की। कार्यक्रम में दिव्यांग बच्चों द्वारा जिस प्रकार अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया है, निश्चित ही वह सामान्य बच्चों से किसी भी प्रकार से कम नहीं है। कलेक्टर श्री विश्वकर्मा ने प्रतियोगिता में भाग लेने वाले दिव्यांगजनों से कहा कि निरंतर प्रयास से ही परिणाम मिलते है। हारना-जीतना उतना मायने नहीं रखता है जितना निरंतर खेलते रहना। निरंतर खेलते रहने वाले ही विजेता होते हैं।

दिव्यांगजनों को इस प्रकार की गतिविधियों, कार्यक्रमों में सहभागिता करते रहना चाहिए इससे उनका उत्साहवर्धन होता है, आगे बढ़ने के लिए प्रेरित होते हैं। उन्होंने कहा कि सभी को दिव्यांगजनों का मनोबल बढ़ाने की दिशा में सदैव कार्य करना चाहिए। खेल स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में अनेक सांस्कृतिक तथा खेलकूद प्रतियोगिताएं आयोजित की गई जिसमें दिव्यांग बच्चों द्वारा अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हुए मनमोहक और आकर्षक प्रस्तुतियां दी गई।

इस अवसर पर सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग तथा खेल विभाग के अधिकारी, दिव्यांगजन तथा नागरिक उपस्थित रहे। दिव्यांगजनों द्वारा बनाई गई सामग्री की लगाई गई प्रदर्शनी कार्यक्रम स्थल पर जिज्ञासा समाज कल्याण सेवा समिति सहित अन्य संस्थाओं के दिव्यांगजनों द्वारा तैयार की गई सामग्री की प्रदर्शनी भी लगाई गई। कलेक्टर श्री विश्वकर्मा ने दिव्यांगजनों द्वारा तैयार की गई सामग्रियों का अवलोकन करते हुए की सराहना की। उन्होंने दिव्यांगजनों से चर्चा कर उनका उत्साहवर्धन भी किया।

शिवाजी ऑडिटोरियम में मनाया विश्व दिव्यांग दिवस

दिव्यांगजन सशक्तिकरण को बढ़ावा देने खेलकूद प्रतियोगिता और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित

बैतूल (निप्र)। विश्व दिव्यांग दिवस जिले में 3 दिसंबर को उत्साह और सकारात्मक ऊर्जा के साथ मनाया गया। इस अवसर पर मुख्य कार्यक्रम शिवाजी ऑडिटोरियम में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में श्री सुधाकर पवार , जिला पंचायत उपाध्यक्ष श्री हंसराज धुर्वे, सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन विभाग सुश्री रोशनी वर्मा, जिला परियोजना समन्वयक जिला शिक्षा केंद्र श्री भूपेंद्र वरकड़े, जिला विधिक सहायता श्री सोमनाथ राय सहित अन्य अधिकारी और बड़ी संख्या में दिव्यांगजन, उनके परिवारजन तथा समाजसेवी संस्थाएं उपस्थित थे। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस अवसर पर दिव्यांगजन सशक्तिकरण को केंद्र में रखते हुए खेलकूद प्रतियोगिताएं और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए।

बाल विवाह मुक्त भारत की दिलाई शपथ

कार्यक्रम में सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की सुश्री रोशनी वर्मा ने कहा कि यह दिन केवल औपचारिक दिवस के रूप में न देखा जाए। यह कार्यक्रम उन विशेष बच्चों के लिए मनाया जा रहा है, जिनके लिए शासन और विभिन्न सामाजिक संगठनों द्वारा अधिकार और सुविधाएं सुनिश्चित की गई हैं। उन्होंने बच्चों से कहा कि वे खेलों में भाग लेते समय केवल जीत-हार की चिंता न करें, बल्कि खुश होकर खेलों का आनंद लें। उन्होंने सभी को बाल विवाह मुक्त भारत की शपथ भी दिलाई।

जिला परियोजना समन्वयक शिक्षा केंद्र श्री भूपेंद्र वरकड़े ने कहा कि हमारे समाज में ऐसे बच्चे भी हैं, जिन्हें पहले पर्याप्त अवसर नहीं मिलता था। आज हम उन्हें समाज के साथ जोड़ने और उनकी उपलब्धियों को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। उन्होंने बच्चों को बधाई देते हुए कहा कि वे बड़े उत्साह के साथ पढ़ाई और खेलों में हिस्सा लें और हर क्षेत्र में सकारात्मक सहयोग दें। उन्होंने माता-पिता और शिक्षकों से भी आग्रह किया कि वे बच्चों का मनोबल बढ़ाएं और उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें, ताकि वे अपनी प्रतिभा से अपने और समाज का नाम रोशन करें।

कलेक्टर ने सेमलखेड़ी ग्राम का भ्रमण कर व्यवस्थाओं को और अधिक सुदृढ़ और संवेदनशील बनाने के निर्देश दिए

विदिशा (निप्र)। कलेक्टर श्री अंशुल गुप्ता ने आज सिरोंज तहसील के ग्राम सेमलखेड़ी एवं इसके आश्रित ग्रामों का दौरा कर विभिन्न शासकीय संस्थानों एवं विकास कार्यों का विस्तृत निरीक्षण किया। अपने स्थलीय भ्रमण के दौरान कलेक्टर ने शाला, आंगनबाड़ी केंद्र, उप स्वास्थ्य केंद्र, शासकीय उचित मूल्य दुकान तथा ग्राम पंचायत अंतर्गत संचालित योजनाओं की समीक्षा की। निरीक्षण के दौरान उन्होंने संबंधित विभागों द्वारा संधारित की जाने वाली विभिन्न पंजीयों, अभिलेखों एवं योजनाओं के क्रियान्वयन की स्थिति का बारीकी से परीक्षण किया। कलेक्टर ने व्यवस्थाओं को और अधिक सुदृढ़ एवं संवेदनशील बनाने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं।

कलेक्टर ने ग्रामीण जनों की समस्याओं को सुना: दौरे के दौरान कलेक्टर श्री गुप्ता ने स्थानीय ग्रामीणों से भी संवाद किया। उन्होंने ग्रामीणों की व्यक्तिगत तथा सार्वजनिक समस्याओं को ध्यानपूर्वक सुना और इनके त्वरित निराकरण हेतु अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किए। कलेक्टर का यह निरीक्षण ग्रामीण क्षेत्रों में शासकीय व्यवस्थाओं को मजबूत करने तथा जनसमस्याओं का मौके पर ही समाधान सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

घोघरी मध्यम परियोजना की टेस्टिंग और ट्रायल 30 दिसंबर तक पूर्ण की जाए: जल संसाधन मंत्री सिलावट

जल संसाधन मंत्री ने की बैतूल जिले के विधायकों के साथ परियोजनाओं की समीक्षा

बैतूल (निप्र)। जल संसाधन मंत्री श्री तुलसी सिलावट की अध्यक्षता में 2 दिसंबर को भोपाल में जल परियोजनाओं की प्रगति को लेकर बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष एवं विधायक बैतूल श्री हेमन्त खंडेलवाल, आमला विधायक डॉ योगेश पंडाग्रे, विधायक मुलताई श्री चंद्रशेखर देशमुख, विधायक भैंसदेही श्री महेंद्र सिंह चौहान , विधायक घोड़ाडोंगरी श्रीमती गंगाबाई उईके तथा जल संसाधन विभाग के अधिकारी, संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। विधायक श्री खंडेलवाल की पहल पर बैतूल जिले की सिंचाई परियोजनाओं को गति देने के लिए यह विशेष समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैतूल जिले की प्रमुख परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए जल संसाधन मंत्री श्री तुलसी सिलावट ने घोघरी मध्यम परियोजना की टेस्टिंग और ट्रायल 30 दिसंबर 2025 से पहले हर हाल में पूर्ण किए जाने के निर्देश अधिकारियों को दिए।उन्होंने कहा कि पारसडोह परियोजना की सिंचाई व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित करें एवं निर्गुड प्रोजेक्ट को शीघ्र पूर्ण करें।

इसके अलावा उन्होंने मेंढ़ा मध्यम परियोजना का कार्य जून 2026 तक पूर्ण करने तथा अतिरिक्त 4500 हेक्टेयर सिंचाई क्षमता बढ़ाने के संबंध में आवश्यक प्रस्ताव एवं कार्यवाही शीघ्र तैयार करने के लिए जल संसाधन विभाग के संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया। वहीं गढ़ा मध्यम परियोजना को भी जून 2026 से पहले पूर्ण करने के लिए विभाग को तेजी से काम बढ़ाने को कहा गया। उन्होंने कहा कि जिले में चल रही हर जल परियोजना किसानों और ग्रामीणों के हित से जुड़ी है, इसलिए काम की रफ्तार तेज की जाए और निर्धारित समयसीमाओं का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए।

शीतलझिरी परियोजना के लिए मिलेगा विशेष पैकेज

बैठक के दौरान मंत्री श्री सिलावट ने जिला जनजातीय बहुल क्षेत्र होने के कारण शीतलझिरी मध्यम परियोजना के लिए विशेष पैकेज पर विस्तृत चर्चा की। उन्होंने कहा कि इस परियोजना की स्वीकृति के लिए आवश्यक प्रक्रिया तुरंत शुरू की जाए, जिससे क्षेत्र के ग्रामीणों को दीर्घकालिक लाभ मिल सके। मंत्री श्री सिलावट ने शेष विधानसभा वार विधायकों की मांग पर नवीन योजनाएं बनाने के भी निर्देश दिए। मंत्री श्री सिलावट ने बैतूल जिले के हर विधानसभा क्षेत्र से 5-5 नई जल योजनाएं (बैराज, जलाशय) चिन्हित कर इन योजनाओं की साध्यता और स्वीकृति की कार्रवाई जल्द प्रारंभ करने के निर्देश दिए। मंत्री श्री सिलावट ने कहा कि नहरों के अंतिम छोर तक पानी पहुंचे और किसानों को सिंचाई में किसी भी प्रकार की दिक्कत न आए, इसके लिए जिले के विभिन्न जलाशयों की नहरों की मरम्मत और सुदृढ़ीकरण के लिए आर आर आर योजना के तहत प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए।

सर्द हवाओं का असर

भोपाल, ग्वालियर-चंबल ठिठुरा

रीवा सबसे ठंडा,पारा 5.8 डिग्री, भोपाल-जबलपुर समेत 17 शहरों में 10 डिग्री से कम तापमान

भोपाल (नप्र)। उत्तर से आ रही सर्द हवाओं से मध्यप्रदेश का भोपाल,ग्वालियर-चंबल हिस्सा ठिठुर गया है। गुरुवार-शुक्रवार की रात में भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर समेत 17 शहरों में पारा 10 डिग्री से नीचे रहा। प्रदेश में रात के तापमान में औसत 2 से 3 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है।

रीवा प्रदेश के इकलौते हिल स्टेशन पचमढ़ी से भी ठंडा रहा। यहां पारा सबसे कम 5.8 डिग्री पर पहुंच गया। भोपाल में 8.2 डिग्री, इंदौर में 11 डिग्री, ग्वालियर में 7.5 डिग्री, उज्जैन में 11.7 डिग्री और जबलपुर में 9.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

मौसम विभाग के अनुसार, राजगढ़ में 6 डिग्री, पचमढ़ी में 6.7 डिग्री, शिवपुरी में 7 डिग्री, उमरिया में 7.1 डिग्री, नौगांव में 8.2 डिग्री, सतना में 8.6 डिग्री, दमोह-खजुराहो में 9 डिग्री, गुना में 9.5 डिग्री, सीधी में 9.6 डिग्री, मलाजखंड में 9.7 डिग्री और धार में तापमान 9.9 डिग्री रहा।

दिसंबर में भी रिकॉर्ड तोड़ेगी सर्दी

मौसम विभाग की माने तो इस बार सर्दी का असर तेज रहा है। भोपाल में नवंबर की सर्दी का 84 साल का रिकॉर्ड टूट चुका है, जबकि इंदौर में 25 साल में सबसे ज्यादा ठंड पड़ी है। ऐसी ही सर्दी दिसंबर में भी रहेगी।

इसलिए फिर बढ़ी सर्दी

मध्यप्रदेश में तेजी से सर्दी बढ़ रही है। ग्वालियर समेत 9 शहरों में पारा 10 डिग्री सेल्सियस से कम रहा था। इकलौते हिल स्टेशन पचमढ़ी में पारा सबसे कम 6.6 डिग्री रहा। वहीं, गुरुवार-शुक्रवार की रात भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर समेत 17 शहरों में तापमान 10 डिग्री से नीचे ही रहा।

मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक, हिमालयी क्षेत्र में एक वेस्टर्न डिस्टरबेंस (पश्चिमी विक्षोभ) एक्टिव है, जबकि इसके पीछे एक और वेस्टर्न डिस्टरबेंस आ रहा है। इस वजह से पहाड़ों में बर्फबारी-बारिश होगी और फिर ठंडी हवाएं एमपी में आएगी।

मौसम विभाग ने पहाड़ी राज्य- हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों में 5 और 7 दिसंबर को वेस्टर्न डिस्टरबेंस के चलते बर्फबारी और बारिश होने की संभावना जताई है। इसके बाद हवा की दिशा उत्तरी होगी। जिससे 7-8 दिसंबर को एमपी के उज्जैन, ग्वालियर, चंबल और सागर में ठंड का असर बढ़ जाएगा। यही पर उत्तरी हवाओं का असर सबसे ज्यादा होता है। भोपाल, इंदौर, जबलपुर-नर्मदापुरम संभाग में भी कड़ाके की सर्दी का असर देखने को मिलेगा।

जंगल पर हंगामा, विजयवर्गीय बोले- वहां आदिवासी कम

विपक्ष का वॉकआउट, सिंगरौली में पेड़ कटेंगे, लगेंगे दूसरे जिलों में- वनमंत्री

भोपाल (नप्र)। 1 मध्य प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन सिंगरौली में 6 लाख पेड़ों की कटाई को लेकर जमकर हंगामा हुआ। कांग्रेस ने इसे अवैध कटाई और अडाणी समूह को फायदा पहुंचाने की कार्रवाई बताया।

वन राज्य मंत्री दिलीप अहिरवार संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए, जिसके बाद उनके बचाव में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि सिंगरौली में आदिवासी कम हैं। इस बयान के बाद भाजपा और कांग्रेस के बीच तीखी बहस शुरू हो गई और कांग्रेस विधायकों ने नारेबाजी करते हुए सदन से वॉकआउट कर दिया।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि सदन में यह साफ हुआ कि कौन सदस्य जनता की समस्याओं के प्रति कितने जिम्मेदार हैं। उन्होंने कहा कि विपक्ष ने भी इस सत्र में कई बार सकारात्मक भूमिका निभाई। सत्र के दौरान सरकार ने कई विधेयक और अनुपूरक बजट पारित किए, जो राज्य के विकास के लिए जरूरी हैं।

नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने भी कहा कि सदन में उठाए गए सवाल जनता से जुड़े थे और भविष्य में विधानसभा सत्र की अवधि और बढ़ाई जानी चाहिए। इसके बाद हंगामे और वॉकआउट के चलते विधानसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई।

सिंगरौली में पेड़ काटने के मुद्दे पर हंगामा

कांग्रेस विधायक विक्रांत भूरिया ने कहा कि सिंगरौली से पेड़ काटकर सागर और शिवपुरी में रोपण किया जा रहा है, जो न्यायसंगत नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि अडाणी को श्रेष्ठ बताने के लिए आदिवासियों की जमीन से जंगल साफ किया जा रहा है। वहीं, विधायक जयवर्धन सिंह ने वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के उल्लंघन का आरोप लगाया।

वन मंत्री के जवाब से विपक्ष रहा असंतुष्ट

वन राज्य मंत्री अहिरवार ने सफाई दी कि 2672 हेक्टेयर क्षेत्र में कटाई केंद्र सरकार की अनुमति से, नियमानुसार की जा रही है और जितने पेड़ काटे जा रहे हैं, उतने लगाए भी जा रहे हैं। जमीन के बदले जमीन भी दी जा रही है। इसके बावजूद विपक्ष असंतुष्ट रहा।

कर्ज, भ्रष्टाचार और विकास पर भी टकराव

नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने सरकार पर 74 हजार करोड़ का कर्ज लेने, जल जीवन मिशन में घोटालों और हेलिकॉप्टर किराए पर करोड़ों खर्च करने के आरोप लगाए। उन्होंने अनुपूरक बजट को कर्ज उन्मुखी बजट बताया। डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा ने जवाब दिया कि यह कर्ज नहीं, निवेश है और इससे प्रदेश का विकास किया जा रहा है।

जबलपुर-मंडला के बीच चलेगी नई ट्रेन

नारायण सिंह पट्टा ने केंद्र शासन से आग्रह किया है कि मंडला रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर वीरांगना दुर्गावती स्टेशन मंडला किया जाए। साथ ही जबलपुर भोपाल ओवरनाइट एक्सप्रेस, इंटरसिटी एक्सप्रेस, जबलपुर से हजरत निजामुद्दीन की ओर जाने वाली गोंडवाना सुपरफास्ट एक्सप्रेस को मंडला स्टेशन तक चलाया जाए।

इस पर लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने संशोधन करने के बाद जबलपुर से मंडला को कनेक्ट कर नई ट्रेन चलाने की बात कही गई।

सागर में सुपरफास्ट ट्रेन स्टॉपेज को मंजूरी

शासकीय संकल्प के अंतर्गत इंजीनियर प्रदीप लारिया ने केंद्र सरकार से अनुरोध किया है कि सागर जिले के नरयावली और जरूआखेड़ा स्टेशन पर राज्य रानी सुपरफास्ट ट्रेन का स्टॉपेज किया जाए। सदन में इसे मंजूरी दे दी गई है और केंद्र सरकार को भेजने का फैसला किया गया।

डिप्टी सीएम बोले- कर्ज नहीं निवेश है

विपक्ष द्वारा कर्ज लिए जाने को बार-बार मुद्दा बनाए जाने पर डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा ने कहा, यह कर्ज नहीं निवेश है। नियम और प्रक्रिया में समय सीमा में कर्ज ले रहे हैं। ब्याज समय पर दे रहे हैं और विकास के काम इससे कर रहे हैं। सरकार की जो भी योजनाएं हैं, वह किसी वर्ग विशेष के लिए नहीं है बल्कि सबके लिए हैं।

नारेबाजी करते हुए कांग्रेस का वॉकआउट

नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा, जब पहले सिंगरौली ब्लॉक पेसा एक्ट के दायरे में आ रहा था, तो संसदीय कार्य मंत्री ने यह गलत जानकारी क्यों दी कि वह एरिया पेसा के दायरे में नहीं आता था। जबकि अगस्त 2023 में इसको लेकर साफ कहा गया है कि वह इलाका पेसा एक्ट के दायरे में आता है। सरकार इस बारे में जवाब दे। इसको लेकर कांग्रेस और भाजपा में बहस की स्थिति शुरू हो गई। इसके बाद कांग्रेस के विधायक नारेबाजी करते हुए बाहर निकल गए।

अन्य अहम फैसले

- जबलपुर-मंडला के बीच नई ट्रेन चलाने को मंजूरी।
- सागर के नरयावली और जरूआखेड़ा में सुपरफास्ट ट्रेन स्टॉपेज को हरी झंडी।
- देवरी का नाम देवपुरी करने का प्रस्ताव खारिज।
- आरजीपीवी में भ्रष्टाचार की जांच की मांग।
- खबर के मिनट टु मिनट अपडेट के लिए ब्लॉग से गुजर जाइए।

सागर का देवरी, देवपुरी नहीं होगा

विधायक बृज बिहारी पटेरिया ने सागर जिले के देवरी का नाम बदलकर देवपुरी करने का प्रस्ताव रखा। राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा ने इससे सहमति जताते हुए भारत सरकार को प्रस्ताव भेजने की बात कही और कहा कि भारत सरकार से अनुमति नहीं दी है इसलिए इसे अग्राह्य किया जाए।

मंत्री विजयवर्गीय बोले-वर्मा का बयान दुर्भाग्यपूर्ण, उनको कड़ी से कड़ी सजा देने की कोशिश

अजाक्स के अध्यक्ष और आईएएस अधिकारी संतोष वर्मा द्वारा ब्राह्मणों की बेटियों को लेकर दिए गए बयान पर नगरीय विकास और आवास विभाग के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा है कि वर्मा का बयान दुर्भाग्यपूर्ण और निंदाजनक है। सरकार उनको कड़ी से कड़ी सजा देने की कोशिश कर रही है। उधर, वर्मा के खिलाफ आज ब्राह्मण समाज की फिर प्रदर्शन करने की तैयारी है। इसके पहले पूर्व मंत्री गोपाल भार्गव और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह से भी भाजपा सांसदों और ब्राह्मण समाज के पदाधिकारियों ने मुलाकात करके वर्मा के खिलाफ कार्यवाही की मांग की है।

चाकू दिखाकर 12वीं की छात्रा का अश्लील वीडियो बनाया

5 लाख फिरौती मांगी, 2 लाख लेने के बाद भी किया वायरल, लोगों का चक्काजाम

गरोठ (नप्र)। मंदसौर जिले के शामगढ़ में 12वीं की 16 वर्षीय छात्रा को ब्लैकमेल करने और अश्लील वीडियो वायरल करने का मामला सामने आया है। घटना से नगर में तनाव और भारी आक्रोश है। इसके चलते पूरा शामगढ़ नगर बंद है और पुलिस बल तैनात कर दिया गया है।

राव कॉलोनी निवासी रिहान पिता शाकिर अब्बासी और बाबू पिता रिहान शाह पर आरोप है कि उन्होंने नाबालिग लड़की को चाकू की नोक पर डराकर अश्लील वीडियो बनाने के लिए मजबूर किया। वीडियो बनाने के बाद उन्होंने इसे वायरल करने की धमकी देकर पीड़िता के परिवार से 5 लाख रुपए की फिरौती मांगी। परिवार ने डरकर पहले 2 लाख रुपए नकद दे दिए थे, लेकिन पूरी रकम नहीं मिलने पर आरोपियों ने गुरुवार शाम सोशल मीडिया पर वीडियो डाल दिए। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि आरोपी रिहान ने उसकी मां के मोबाइल से वीडियो बनाकर अपने फोन पर ट्रांसफर कर लिया था।

विरोध प्रदर्शन के बाद पूरा शामगढ़ नगर बंद- वीडियो वायरल होने की खबर फैलते ही गुरुवार रात सैकड़ों लोगों ने शामगढ़ थाने का घेराव कर दिया और तत्काल गिरफ्तारी की मांग की। शुक्रवार को यह जनाक्रोश और बढ़ गया, जिसके चलते हिंदू संगठनों के सक्रिय होने के बाद एहतियात के तौर पर पूरे शामगढ़ नगर को बंद कर दिया गया है।

एएसपी हेमलता कुरील ने बताया कि दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। नगर परिषद सीएमओ सुरेश यादव को बुलाया गया है। थाने बुलडोजर की मांग पर चर्चा चल रही है। आरोपियों के घर तोड़ने की कार्रवाई की जा सकती है।

नल कनेक्शन काटा, मकान तोड़ने की तैयारी- स्थिति को नियंत्रित करने के लिए शुक्रवार को नगर में अतिरिक्त पुलिस बल बुलाया गया है। नगर परिषद की ओर से आरोपियों के मकानों पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। नल कनेक्शन काट दिए गए हैं और मकान की नपती (नाप-जोख) की जा रही है। आक्रोशित लोग प्रशासन से आरोपियों के मकान तोड़ने और उनकी तत्काल गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं।

7 करोड़ की आबादी पर 12.84 करोड़ जाँच, साइंस हाउस का फर्जीवाड़ा खुद आँकड़ों से बेनकाब : जयवर्धन सिंह

भोपाल। मध्यप्रदेश कांग्रेस कार्यालय में आयोजित संयुक्त पत्रकार वार्ता में पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह, विधायक ऋषि अग्रवाल, विधायक देवेंद्र पटेल, मीडिया विभाग के अध्यक्ष मुकेश नायक, और एनएसयूआई के राष्ट्रीय प्रवक्ता विराज यादव उपस्थित रहे।

विधायक जयवर्धन सिंह ने स्वास्थ्य विभाग में 943 करोड़ रुपये के कथित महाघोटाले का खुलासा किया। उन्होंने बताया कि विभाग ने विधानसभा में 68 हजार पन्नों का रिकॉर्ड प्रस्तुत किया, जिनके प्रारंभिक अध्ययन में यह सामने आया कि 7 करोड़ की आबादी पर 12.84 करोड़ जाँचें दिखाकर फर्जी बिल बनाए गए।

- एक ही व्यक्ति की दो कंपनियों को अलग-अलग नाम से टेंडर दिया गया।
- एक ही टेस्ट के अलग-अलग रेट लगाकर भारी लूट हुई।
- 0 प्रतिशत जीएसटी वाली स्वास्थ्य सेवाओं पर 18 प्रतिशत जीएसटी वसूला गया।
- ब्लॉक अस्पतालों, सीएचसी और पीएचसी में जमीन पर जाँच किए बिना फर्जी रिपोर्टें बनाई गईं।

श्री जयवर्धन सिंह ने कहा यह वही कंपनी है जिस पर ईडी और इंकम टेक्स एंड की कार्रवाई हो चुकी है और मालिक जेल जा चुका है, फिर भी भाजपा सरकार ने जुलाई 2025 में इसे एक वर्ष का एक्सटेंशन दे दिया। स्वास्थ्य जैसी महत्वपूर्ण सेवा को निजी कंपनियों के हवाले कर जनता के जीवन के साथ खिलवाड़ किया गया है। मैं मांग करता हूँ कि पूरे प्रकरण की सीबीआई जाँच कर जिम्मेदारों पर कार्रवाई की जाए। यह भ्रष्टाचार नहीं, बल्कि मध्यप्रदेश के लोगों की सेहत के साथ किया गया अपराध है। विधायक देवेंद्र पटेल ने रायसेन जिले के सरकारी स्कूलों में बच्चों के अधिकारों के गंभीर उल्लंघन की जानकारी दी।

मेट्रो दौड़ने को तैयार, पर पार्किंग कहीं नहीं

सभी 8 स्टेशन के नीचे दुकान बनाकर कमाई की तैयारी, यात्रियों को 'ड्रॉप एंड गो' की ही सुविधा

भोपाल (नप्र)। कमिश्नर मेट्रो रेल सेफ्टी ने भोपाल मेट्रो के प्रायोरिटी कॉरिडोर के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया है। इसके बाद लोकार्पण की तैयारियां तेज हो गई हैं। हालांकि, भोपाल में 8 में से 1 भी मेट्रो स्टेशन पर पार्किंग नहीं है। ऐसे में ये स्टेशन 'दूसरों' की पार्किंग के भरोसे ही रहेंगे।

भोपाल मेट्रो की ऑरेंज लाइन का प्रायोरिटी कॉरिडोर 6.22 किलोमीटर लंबा है। इसमें कुल 8 स्टेशन- सुभाष नगर, केंद्रीय स्कूल, डीबी मॉल, एमपी नगर, रानी कमलापति, डीआरएम तिराहा, अलकापुरी और एम्स शामिल हैं। इनमें से एक भी स्टेशन पर पार्किंग की व्यवस्था नहीं होने से यात्रियों को अपनी गाड़ियां खड़ी करने के लिए मुश्किलें झेलनी पड़ेंगी।

पिक एंड ड्रॉप की व्यवस्था ही रहेगी- मेट्रो स्टेशनों पर सिर्फ पिक एंड ड्रॉप की व्यवस्था ही रहेगी। यानी, यात्री किसी गाड़ी से उतर और चढ़ सकेगा, लेकिन अपने वाहन यहां खड़े नहीं कर सकेगा। सूत्रों के अनुसार, मेट्रो कॉर्पोरेशन स्टेशन के नीचे आउटलेट्स बनाएगा। ऐसे में स्टेशन के नीचे पार्किंग की व्यवस्था नहीं मिलेगी। इस मुद्दे पर

मेट्रो अफसरों का कहना है कि पार्किंग के लिए व्यवस्था कर रहे हैं ताकि यात्रियों को परेशानी का सामना न करना पड़े।

13 दिसंबर को शुरुआत की उम्मीद कम- सीएमआरएस ने मेट्रो कॉर्पोरेशन को एनओसी दे दी है। यह रिपोर्ट सरकार को सौंप दी गई है ताकि लोकार्पण के लिए तारीख तय कर ली जाए। उम्मीद है कि दिसंबर में ही मेट्रो आम लोगों के लिए दौड़ सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या तो वर्चुअल शुभारंभ कर सकते हैं या मेट्रो को हरी झंडी दिखाने भोपाल आ सकते हैं। हालांकि, समय कम होने और अभी तक तारीख तय नहीं होने से 13 दिसंबर को मेट्रो की शुरुआत होने की उम्मीद कम ही है।

छतरपुर में ट्रक से टकराई कार, 5 की मौत

सभी मृतक एक ही परिवार के सदस्य; कार का गेट तोड़कर निकालने पड़े शव

छतरपुर (नप्र)। छतरपुर में ट्रक और कार की आमने-सामने से टक्कर हो गई। हादसे में 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। एक्सीडेंट गुलगंज के पास नेशनल हाईवे पर करीब 8 बजे हुआ। कार में सतना का प्रजापति परिवार सवार था, जो शाहगढ़ जा रहा था। सूचना मिलते ही सागर आईजी हिमानी खन्ना सहित गुलगंज पुलिस मौके पर पहुंची। कार के गेट तोड़कर शवों को बाहर निकाला जा सका।

सीधी में साढ़े तीन करोड़ के मकान, 12 लाख के जेवर मिले, ईओडब्ल्यू के छापे में खुलासा

हाईस्कूल प्रिंसिपल के पास 10 फोर-व्हीलर, 4 टू-व्हीलर

सीधी (नप्र)। सीधी में खुखरा हाई स्कूल का प्रिंसिपल अभिमन्यु सिंह फॉर्च्यूनर, इको स्पोर्ट्स, बोलेरो, इंडिका, जेसीबी, ट्रैक्टर, हार्वेस्टर समेत 10 फोर-व्हीलर और 4 टू-व्हीलर गाड़ियों का मालिक निकला। आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ की छापामार कार्रवाई में सीधी शहर में बने 7500 वर्गफीट वाले मकान का पता चला है, जिसकी अनुमानित कीमत डेढ़ करोड़ रुपए है।

इसके अलावा तीन अन्य मकान हैं, जिनकी कुल कीमत करीब 2 करोड़ रुपए है। करीब सात लाख रुपए के सोने और पांच लाख रुपए के चांदी के आभूषण मिले हैं। प्रिंसिपल अभिमन्यु सिंह के घर पर शुक्रवार सुबह करीब 5 बजे 50 सदस्यीय टीम ने छापा मारा। अफसरों ने एक साथ अमहा स्थित ऊंची हवेली, मड़वास गांव में बने

पुश्तैनी घर और कुसमी स्थित संपत्तियों की जांच शुरू की। उनका बैंक लॉकर भी खंगाला जा रहा है। ईओडब्ल्यू ने अभिमन्यु सिंह के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का केस दर्ज किया है।

कई दस्तावेज बरामद, पुलिसकर्मी संभाल रहे सुरक्षा- त्रिपाठी ने बताया कि अभी तक कई महत्वपूर्ण दस्तावेज बरामद किए जा चुके हैं। जांच की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ रही है। कार्रवाई पूरी होने तक टीमें सभी ठिकानों पर तैनात रहेंगी। इस पूरी कार्रवाई में सीधी पुलिस लाइन के पुलिसकर्मी सहयोग कर रहे हैं। ईओडब्ल्यू टीम ने स्थानीय पुलिस अधीक्षक से आवश्यक सहायता मांगी थी, जिसके बाद पुलिस बल मौके पर पहुंचकर सुरक्षा और व्यवस्था की जिम्मेदारी संभाल रहा है।

दो महीने पहले दर्ज हुई थी शिकायत

ईओडब्ल्यू की टीम ने खटखटाया तो प्राचार्य अभिमन्यु सिंह ने घर का दरवाजा खोला। इसके बाद 13 लोगों की टीम अंदर दाखिल हो गई। इसी दौरान दो अन्य ठिकानों पर भी अलग-अलग टीमें पहुंचीं।

टीम के कार्यवाहक निरीक्षक हरीश त्रिपाठी ने बताया कि यह कार्रवाई दो महीने पहले रीवा ईओडब्ल्यू कार्यालय में दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर की जा रही है। प्रारंभिक जांच में आरोप सही पाए जाने के बाद यह रेड मारी गई है।